हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

13 जून, 2005

खण्ड 2, अंक 2

अधिकृत विवरण

Haryana Vidhan Sabha Secretariat
LIBRARY
Chandigarh

विषय सूची

सोमवार, 13 जून, 2005

	पृष्ठ संख्या
शोक प्रस्ताव	1
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	2
नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	24
वर्ष 2005-06 के बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा	28

मूल्य : 83

Haryana Vidhan Sabha Secretariat
LIBRARY
Chandigarh

हरियाणा विधान सभा

सोमवार, 13 जून, 2005

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में 2.00 बजे मध्याह्न पश्चात हुई। अध्यक्ष (सरदार एच०एस०चट्ठा) ने अध्यक्षता की।

शोक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : आनरेबल मैम्बर्ज, अब मुख्यमंत्री जी शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष जी, 9 जून को हरियाणा में एक भीषण तूफान कई इलाकों में आया। इससे प्रदेश में कई जाने गयीं यहां तक कि, एक चार साल का बच्चा भी उस तूफान में मारा गया। इस तूफान में कुछ जानवर भी मारे गये। काफी नुकसान हमारा इस तूफान से हुआ। जिनकी इस तूफान में जाने गयी हैं उनके बारे में मैं एक शोक प्रस्ताव सदन में रखता हूं--

"यह सदन 9 जून, 2005 को राज्य के विभिन्न भागों में आए भीषण तूफान में मारे गये लोगों के दुख:द एवं असामायिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।"

डा० सुशील इन्दौरा (ऐलनाबाद एस०सी०) : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी शोक प्रस्ताव लाए हैं। जो भीषण तूफान 9 जून को आया था उसमें कई जाने भी गयी हैं और उससे हमारे प्रदेश को बहुत नुकसान भी हुआ है। मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी के नेता श्री ओम प्रकाश चौटाला की तरफ से भी शोक संतप्त परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं और साथ ही एक बात की तरफ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान भी आकृष्ट करना चाहूंगा कि यह एक ऐसी परिस्थिति हुई कि अचानक एक हादसे के तौर पर यह तूफान आया। इस तूफान से खास तौर से जो मेरा जिला है या जो सिरसा पार्लियामैंट की कांस्टीच्यूंसी के फतेहाबाद आदि ऐरियाज पड़ते हैं, वे काफी प्रभावित रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं वहां पर जाकर आये हैं जिसके लिए मैं इनका आभार भी व्यक्त करता हूं। मेरा सरकार से निवेदन है कि जो इस तूफान से वहां पर नुकसान हुआ है उसके बारे में गहराई से सोचते हुए सरकार को उचित कारवाई करने का काम करना चाहिए।

परिवहन मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : स्पीकर साहब, हरियाणा में आए भीषण तूफान की चर्चा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की । इस तूफान से जान और माल दोनों की हानि हुई। मैं मुख्यमंत्री जी द्वारा लाए गए शोक प्रस्ताव के अनुमोदन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, 24 घंटे के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी खुद वहां पहुंच गए और सरकार ने न केवल वहां पर हुए जान और माल के नुकसान का पूर्ण मुआवजा दिया बल्कि मुख्यमंत्री जी ने एक

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]
पूरा पैकेज वहां के लिए दिया जबकि कई नेता जिनके जिले के अंदर जान और माल की हानि हुई, वे मनाली की वादियों में घूम रहे थे । एक नया उदाहरण समाज सेवा का भी और सरकार की जिम्मेवारी का भी हमारी सरकार ने स्थापित किया है। अध्यक्ष महोदय, जहां हम शोक संतप्त परिवारों के साथ संवेदना व्यक्त करते हैं वहीं मैं यह भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने जो इस बारे में चर्चा की तो मुख्यमंत्री जी के और सरकार के नोटिस में यह मामला है। खुद अपने हाथ से प्रभावित परिवारों के एक एक सदस्य को मुख्यमंत्री जी राशि देकर आए हैं और उनके आँसू पौंछकर आये हैं। सरकार इस मामले को लेकर संवदेनशील है और हम अपनी जिम्मेदारी पर खरा उतरेंगे।

Mr. Speaker : Hon'ble Members, the leaders of different parties have expressed their views and I also associate myself with their feelings and express deep sense of sorrow on the untimely demise of the various people, who lost their lives in the storm in different parts of the State.

Now, I would request you to observe silence for two minutes while standing as a mark of respect to the memory of the deceased.

(At this stage the House stood in silence for two minutes as a mark of respect to the memory of the deceased).

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष : ऑनरेबल मैम्बर्ज, अब सवाल होंगे।

Issuing of N.O.Cs. for Petrol Pumps

***3. Shri Karan Singh Dalal :** Will the Deputy Chief Minister be pleased to state—

(a) the number of petrol pumps for which N.O.Cs. were issued by the State Government for setting up of petrol pumps along the National Highways, State Highways and other roads from January, 2000 to February, 2005 in the State;

(b) whether prior permission from the Ministry of Environment and Forests Government of India was required under Forest Conservation Act, 1980 for changing the use of forest areas/lands to non-forest use or setting up of petrol pumps along the roads; and

(c) the number of petrol pumps for which permission of Government of India, Ministry of Environment and Forests has been obtained before issuing N.O.Cs. to petrol pumps as mentioned in part (a) above ?

उप मुख्यमंत्री (श्री चन्द्र मोहन) :

(क) राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य राजमार्गों तथा अन्य सड़कों के साथ लगते

पैट्रोल पम्पों की स्थापना के लिए जनवरी, 2000 से फरवरी, 2005 तक जिला मैजिस्ट्रेटों द्वारा जारी किए गए अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्न प्रकार से है--

1.	राष्ट्रीय राजमार्ग	242
2.	राज्य राजमार्ग	297
3.	अन्य सड़कें	208
	कुल	747

(ख) हाँ, श्री मान

(ग) 5 मामलों में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने से पहले पर्यावरण तथा वन मंत्रालय, भारत सरकार से पूर्व अनुमति ली गई थी।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपने जवाब में जैसा माना है कि 747 पैट्रोल पम्पस को माननीय जिलाधीशों ने एन०ओ०सीज०इशू की और केवल पांच केसिज में मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायर्न्मेंट एंड फौरैस्ट, गवर्नमैंट ऑफ इंडिया से इजाजत ली गई। इस प्रकार से इसमें कानून के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया गया है और पर्यावरण के साथ भी खिलवाड़ किया गया है एक तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जिन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स ने इन पैट्रोल पम्पस को स्थापित करने के लिए एन०ओ०सी०इशू किए उनके खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ? दूसरे, अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी यह भी बताएं कि जहां फरवरी, 2005 तक 747 पैट्रोल पम्पस को एन०ओ०सीज० दिए गए तो पहली मार्च से 21 मार्च, 2005 तक जब नयी विधान सभा के लिए वोटों की गिनती होनी थी, उस वक्त कितने एन०ओ०सीज० इस तरह से पैट्रोल पम्पस को स्थापित करने के लिए इस प्रदेश में इशू किए गए ?

Mr. Speaker : You put the question. You will get the reply. (Interruptions).

श्री चंद्र मोहन : अध्यक्ष महोदय, 1 मार्च से 31 मई, 2005 तक जो कुल 87 स्थलों के लिए एन०ओ०सीज० इशू किए गए उनका विवरण इस प्रकार है राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए 22, राज्य राजमार्गों के लिए 25, अन्य सड़क एवं नगर पालिकाओं के लिए 40 यानि कुल 87, मार्च, 2005 में 73, अप्रैल, 2005 में 5 तथा मई, 2005 में 9 स्थलों के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी किए गए।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्री जी ने बताया कि 1 मार्च से 21 मार्च तक भी अंधाधुंध तरीके से कानून को ताक पर रख कर रिश्वत लेकर पिछली सरकार के समय उस समय के मुख्यमंत्री ने व उनके परिवार ने लोगों को ये अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किए। वे लोग पैसा लेकर के डी०सी० को टैलीफोन किया करते थे। ये लोग यह भी नहीं देखते थे कि एन०एच०ए०आई० ने एन०ओ०सी० दिया है या नहीं दिया है। इस वजह से भी पर्यावरण का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जिन्हें एन०ओ०सीज० इशू हुए हैं उन पैट्रोल पम्प के मालिकों ने बाकायदा चौधरी देवी लाल ट्रस्ट के नाम से रिश्वत के तौर पर चैक से पेमेन्ट की हुई है तो अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या वे उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे जिन्होंने

दबाव में आकर कानून को ताक पर रखकर प्रदेश के पर्यावरण के साथ खिलवाड़ किया?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, जैसा मंत्री जी ने बताया कि हमारी नयी सरकार बनने से पहले जनवरी, 2000 और मार्च, 2005 के बीच में 87 में से 73 पैट्रोल पम्पों को एन०ओ०सीज० दिए गए। इस हिसाब से आप स्वयं अन्दाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से पैट्रोल पम्प को एन०ओ०सीज० दिए गए। हालांकि पैट्रोल पम्प को एन०ओ०सी० देना सरकार का काम नहीं है यह काम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का होता है और जैसा कि दलाल साहब ने भी कहा, हम सभी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को यह लिख रहे हैं कि इन चार चीजों के बारे में क्लीयरैंस चाहिए। ये हैं नेशनल हाई-वे, सी०एल०यू०, फायर सेफटी और ट्रैफिक कन्ट्रोल। इनके लिए हम उनको स्टीपुलेटिड टाईम दे रहे हैं और उनको ये डायरेक्शंज दे रहे हैं कि इन सभी चीजों की क्लीयरैंस वे स्टीपुलेटिड टाईम में पूरी करवायें। जिन पैट्रोल पम्प की क्लीयरैंस नहीं आयेगी, उनके खिलाफ हम कारवाई करेंगे।

श्री अमीर चन्द मक्कड़ : स्पीकर सर, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहूंगा कि अभी पैट्रोल पम्प हाई-वेज के साथ लगाने की बात चल रही थी तो क्या ऐसे पैट्रोल पम्प शहर के अन्दर भी लगाने की अनुमति सरकार दे रही है या नहीं ? क्योंकि हांसी शहर में 2004 में जीत कालोनी के अन्दर एक प्लाट में पैट्रोल पम्प लगाया गया है।

Mr. Speaker : It is not possible to reply particular one station. This question relates to entire state.

श्री अमीर चन्द मक्कड़ : स्पीकर सर, मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या उस पैट्रोल पम्प के बारे में भी जोकि म्यूनिसिपल कमेटी की जमीन को घेर कर प्लाट में गलत ढंग से लगाया गया है, सरकार इन्क्वायरी करवायेगी? (इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया)

श्री एस०एस० सुरजेवाला : स्पीकर सर, जो यह इतने एन०ओ०सीज० पैट्रोल पम्प लगाने के लिए चुनाव के दौरान वोट पड़ने के बाद दिए गये हैं इन सबमें सरासर अनियमितताएं हैं। न तो उनके पास भारत सरकार की इन्वायर्नमैन्ट एवं फोरैस्ट मिनिस्ट्री की क्लीयरैंस है और न ही उनके पास नेशनल हाई-वे अथोरिटी की क्लीयरैंस हैं। जब तक ये इनसे क्लीयरैंस नहीं ले लेते तब तक क्या इन पैट्रोल पम्प के एन०ओ०सीज० को सस्पैंड किया जायेगा ?

श्री चन्द्रमोहन : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आदरणीय श्री सुरजेवाला जी ने सवाल किया है मैं उनको बताना चाहूंगा कि हम इसके लिए उनको कुछ समय देंगे। अगर उसके बाद भी वे क्लीयरैंस की शर्तों को पूरा नहीं करते तो उनके खिलाफ ऐक्शन लिया जायेगा।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से और उप-मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार उन पैट्रोल पम्पों के मालिकों से अब यह कहने जा रही है कि जो परमिशन उन्होंने उस समय नहीं ली वह अब ले लें ? लेकिन अध्यक्ष महोदय, अब तक तो बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है, कानून की उल्लघंना हो चुकी है और रिश्वत का लेन-देन हो चुका है। मैं आपके माध्यम से फिर मुख्यमंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जहां कानून की उल्लघंना हुई है और जहां मेनडेटरी प्रोवीजन को तोड़ा गया है क्या ऐसे पैट्रोल पम्पस के मालिकों के खिलाफ और उन अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने जान-बूझकर रिश्वत ली एवं चौधरी देवीलाल

ट्रस्ट में लाखों रूपया लोगों से डरा धमका कर जमा करवाया और एन०ओ०सीज० दिए, कार्यवाही की जाएगी ? क्या उस ट्रस्ट की इंक्वायरी करवायी जायेगी कि कितने पैट्रोल पम्प मालिकों ने पैसे दिए ? क्या ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी जो कानून तोड़ चुके हैं, जिन्होंने इस तरह के एन०ओ०सीज० इश्यु करवाये ? जैसा कि श्री सुरजेवाला जी ने कहा कि एन०ओ०सीज० आप अब मांग रहे हैं आप उनसे कहें कि वो परमिशन लायें और आप उन्हें एन०ओ०सी० दें। क्या ऐसे पैट्रोल पम्प मालिकों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ताकि भविष्य में ऐसी अनियमितताएं न हों और प्रदेश का पर्यावरण खराब न हो।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : जैसा मैंने कहा कि उनको थोड़ा समय और देंगे और हर केस का इंडीविज्युल केस के रूप में फैसला करेंगे।

श्री रणबीर सिंह महेन्द्रा : अध्यक्ष महोदय, क्या उन एन०ओ०सीज० को उप-मुख्यमंत्री जी विदड्रा कर सकते हैं या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट विदड्रा कर सकते हैं ?

श्री चन्द्र मोहन : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने काबिल दोस्त को बताना चाहूंगा कि सरकार इनको विदड्रा कर सकती है।

तारांकित प्रश्न सं० 9

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री धर्मपाल सिंह मलिक सदन में उपस्थित नहीं थे।)

Setting up of a Medical College in Bhiwani

***29. Dr. Shiv Shankar Bhardwaj :** Will the Minister for Health be pleased to State—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to set up a Medical College in Bhiwani; and

(b) if so, the time by which the aforesaid proposal is likely to be materialize?

स्वास्थ्यमंत्री (बहिन करतार देवी) :

(क) नहीं, श्रीमान् जी ।

(ख) --

डा० शिव शंकर भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, दक्षिणी हरियाणा में कोई मैडीकल कालेज नहीं है, सरकार की प्रतिबद्धतता लोगों के स्वास्थ्य के लिए है। भिवानी एक ऐसा स्थान है जहां सिविल हस्पताल है जो कि सारे एशिया का डिस्ट्रिक्ट लैवल का सबसे बड़ा हस्पताल है इसमें सारे डिपार्टमैंटस हैं मैडीसिन, सर्जरी, गायनी, आइज, स्किन और ब्लड बैंक आदि। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को कहना चाहता हूं कि इस होस्पिटल को मैडीकल कालेज बनाया जाए। इस पर सरकार का बहुत ज्यादा पैसा खर्च होने वाला नहीं है क्योंकि यहां पर सारा इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार है। इसलिए मेरी स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना है कि यहां पर एक

मैडीकल कालेज बनाया जाए। ऐसा होने से स्वास्थ्य के प्रति हमारी जो प्रतिबद्धतता है, वह पूरी हो जाएगी।

बहिन करतार देवी : अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहती हूं कि यह ठीक है कि भिवानी में 300 बैड का अस्पताल है लेकिन वहां पर मैडीकल कालेज बनाने के लिए 25 एकड़ जमीन चाहिए जबकि वहां जमीन केवल 4 एकड़ ही है। अभी तक राज्य में 3 मैडीकल कालेज हैं जिनमें से एक प्राइवेट मैडीकल कालेज मुलाना में है और बाकी के दो मैडीकल कालेज एक अग्रोहा में और दूसरा पी०जी०आई०, रोहतक में सरकारी तौर पर काम कर रहे हैं।

श्रीमती सुमिता सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से कहना चाहती हूं कि जब केन्द्र में एन०डी०ए० की सरकार थी तो सैन्टर के स्वास्थ्य मंत्री सी०पी० ठाकुर जी करनाल के पास कुंजपुरा में कल्पना चावला के नाम से एक मैडीकल कालेज खोलने की अनाउंसमैंट करके गए थे, लेकिन उस अनाउंसमैंट के बाद हमें कोई जानकारी नहीं है कि इसके लिए भूमि अधिकृत की गई है या नहीं और न ही इस बारे में हमें कोई और जानकारी है इसलिए मैं मंत्री महोदया से जानना चाहूंगी कि क्या करनाल में कोई मैडीकल कालेज खोलने के बारे में सरकार विचार कर रही है ?

बहिन करतार देवी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि अभी इस बारे में विभाग के पास केन्द्र सरकार की तरफ से कोई सूचना नहीं आई है।

श्री नरेश यादव : अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदया ने बताया कि भिवानी में 300 बैड का अस्पताल आलरेडी है और मैडीकल कालेज खोलने के लिए उन्होंने जमीन का ही प्रोवीजन बताया है तो मैं इस बारे में कहना चाहूंगा कि हमारे दक्षिणी हरियाणा के एरियाज में जैसे रिवाड़ी, भिवानी, नारनौल और महेन्द्रगढ़ में कोई मैडीकल कालेज नहीं है। अटेली और बाछौद की पंचायत 100 एकड़ जमीन देने के लिए तैयार भी है, वहां अभी मुख्यमंत्री महोदय जी जाकर आए हैं, वहां हवाई पट्टी भी है, वहां की पंचायत जमीन देने को तैयार है, वहां आस पास कोई मैडीकल कालेज नहीं है, इसलिए अगर जमीन ही आधार है और पंचायत जमीन देने को तैयार है तो मैं मंत्री महोदया से कहना चाहूंगा कि वहां मैडीकल कालेज बनाया जाए। नारनौल से जयपुर 150 किलोमीटर, नारनौल से दिल्ली 130 किलोमीटर, नारनौल से अग्रोहा, हिसार 250 किलोमीटर पड़ता है। रोहतक में भी एक मैडीकल कालेज और यूनीवर्सिटी है, हिसार में 2 यूनिवर्सिटीज और मैडीकल कालेज है, करनाल के नजदीक पी०जी०आई० चण्डीगढ़ पड़ता है, हमारा एरिया सबसे दूर है और शहीदों का एरिया है यहां के सैकड़ों जवान कारगिल की लड़ाई में शहीद हुए हैं।

Mr. Speaker : Yadav Ji, don't deliver the speech. Only put the supplementary. You straightway put the question.

श्री नरेश यादव : अध्यक्ष महोदय, शहीदों के इस इलाके की चिरकालीन मांग है कि नारनौल में कोई मैडीकल कालेज और साथ में अस्पताल बनाया जाए। इससे भिवानी के लोगों को भी फायदा हो जाएगा। चूंकि जयपुर के मैडीकल कालेज में बहुत भीड़ हो जाती है इसलिए राजस्थान के लोगों को भी बहुत फायदा हो जाएगा।

Mr. Speaker : Yadav Ji, don't deliver the speech. Only put the supplementary. You straightway put the question.

श्री नरेश यादव : अध्यक्ष महोदय, हमारी यही मांग है कि हमें एक मैडीकल कालेज दे दिया जाए क्योंकि दक्षिणी हरियाणा को अभी तक कुछ नहीं मिला।

श्री रामकिशन फौजी : अध्यक्ष महोदय, अभी यहां भिवानी में मैडीकल कालेज खोलने की बात कही गई है, मैंने पिछले हाउस में भी यह कहा था । (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, भिवानी भी दक्षिणी हरियाणा में आता है और वहां गरीब लोग रहते हैं तथा वहां पर बहुत सी मौतें समय पर चिकित्सा न मिलने के कारण हो जाती हैं।

Mr. Speaker : It is known to everybody. Put the supplementary. (Interruptions) Yadav ji, Take your seat.

श्री राम किशन फौजी : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि हमारी सरकार गरीबों की सरकार है क्या भिवानी में 25 एकड़ जमीन खरीदकर वहां कोई मैडीकल कालेज बनाया जायेगा ? क्योंकि वहां से मरीजों को रोहतक तक लाने में काफी समय लग जाता है और समय पर चिकित्सा न मिलने के कारण कई मौतें हो जाती हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्यमंत्री बड़े फ्राखदिल हैं हमें आशा है कि वे हमारी इस मांग को मानेंगे।

बहिन करतार देवी : अध्यक्ष महोदय, जो पर्टिकुलर प्रश्न था उसका जवाब तो मैं पहले ही दे चुकी हूं। जहां तक मेरे भाई दक्षिणी हरियाणा की बात कर रहे हैं इस बारे में मैं बताना चाहूंगी कि रोहतक भी दक्षिणी हरियाणा में आता है और रोहतक में जो पी०जी०आई० है उसके दर्जे को बढ़ाने के लिए सरकार विचार कर रही है। अध्यक्ष महोदय, डिमांड रखना अलग बात है और प्रश्न पूछना अलग बात है। प्रश्न का जवाब मैं पहले ही दे चुकी हूं। इसके अलावा यादव साहब का एक प्रश्न और लगा हुआ है उसका जवाब भी मैं अभी बता देती हूं।

श्री अध्यक्ष : नहीं नहीं मैडम, उस प्रश्न का जवाब आप उसी समय देना जब संबंधित प्रश्न का नम्बर आये।

बहिन करतार देवी : ठीक है। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ मैं यह भी बताना चाहूंगी कि मैडीकल कालेज बनाने के लिए केवल जमीन की ही बात नहीं है बिल्डिंग बनाने पर भी खर्चा होता है, स्टाफ का भी खर्चा होता है। इसके अलावा दूसरे खर्चे ही होते हैं। अग्रोहा मैडीकल कालेज का काम काफी दिनों से चल रहा है लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ है। केवल हां कह देने से मैडीकल कालेज नहीं बनता। इसमें काफी कुछ देखना होता है।

आई०जी० शेर सिंह : अध्यक्ष महोदय, जैसे मैडीकल कालेज रोहतक में है, आज के युग में पैसा हर जगह अपनी भूमिका अदा कर रहा है इसी कारण अच्छे डाक्टर हमारे मैडीकल कालेजों से अपनी नौकरी छोड़कर दूसरी जगहों पर जा रहे हैं। और जो बचे हैं वे भी जाने की कोशिश में रहते हैं मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार इन डाक्टरों को अपने मैडीकल कालेजिज में ही रोकने के लिए उनकी तनख्वाह बढ़ाने के बारे में विचार कर रही है ? अगर सरकार उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ायेगी तो जो अच्छे-अच्छे डाक्टर हैं वे हमारे मैडीकल कालेजों से नौकरी छोड़कर कहीं दूसरी जगह चले जायेंगे।

Mr. Speaker : It is a suggestion, not the question.

Construction of Tehsil Building in Narnaund city

*25. **Sh. Ram Kumar Gautam:** Will the Minister for Revenue be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct Tehsil Building in Narnaund City, district Hisar ?

राजस्व मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) : जी, हाँ।

Sh. Ram Kumar Gautam: Speaker Sir, I would like to know Form the Hon'ble Minister that how much time will you consume ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय साथी ने समय की बात की है इस बारे में मैं इनको बताना चाहूंगा कि नारनौंद शहर में जहां पर तहसील बनाई जानी है उस जगह पर पानी इकट्ठा होता है और हमें लगता है कि यदि उस जगह पर बिल्डिंग बना दी जायेगी तो वह बिल्डिंग कहीं नीचे न बैठ जाये। इनकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि वहां पर बिल्डिंग बनाने के लिए सरकार की तरफ से 74.82 लाख रुपये रखे हुए हैं और एफ०डी० से भी एप्रूवल मिल गई है। लेकिन जो मेन समस्या इसमें आ रही है वह जगह की है वह जगह जोहड़ टाईप है जहां पानी एकत्रित होता है। विभाग को अंदेशा है कि यदि वहां बिल्डिंग बनाई जायेगी तो कहीं वह बिल्डिंग नीचे न धंस जाये। यदि मेरे साथी की नॉलेज में कोई और जगह है तो ये बता दें, हम वहां बिल्डिंग बनवा देंगे। वैसे हम भी जगह देख रहे हैं।

श्री राम कुमार गौतम : अध्यक्ष महोदय, पानी वहां पर खड़ा रहता है लेकिन वहां ड्रेनेज न होने की वजह से पानी एकत्रित होता है। यह जगह बहुत बढ़िया है और हार्ट आफ सिटी है। ऐसा नहीं है कि वहां से पानी नहीं निकाला जा सकता। दो-चार दिन का काम है वहां से पानी निकल सकता है। यदि वहां से पानी निकाल दिया जाये तो उससे अच्छी और जगह नहीं होगी।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैंने इनको पहले भी बता दिया है कि पैसा हमारे पास है लेकिन साईट की दिक्कत है। वह साईट जहां पर तालाब है, उसका हम भराव करवाएंगे। डिपार्टमैंट को केवल इस बात का अन्देशा है कि कहीं बिल्डिंग की जमीन न बैठ जाए इसलिए उसको ठीक प्रकार से देखकर उस पर कार्यवाही करेंगे।

Widening of Road from Kutub Minar to Aaya Nagar

*48. **Shri Sukhbir Singh Sohana :** Will the Chief Minister be pleased to State—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to widen the road from Kutub Minar to Aaya Nagar Border with the Consultation of Delhi Government; and

(b) if so, the time by which the aforesaid proposal is likely to be materialized ?

Chief Minister (Shri Bhupinder Singh Hooda) :

(a) The road mentioned as Kutab Minar to Aaya Nagar Border falls

under the territorial jurisdiction of National Capital Territory of Delhi and is under the control of Municipal Corporation of Delhi. This road leads to Gurgaon. The State Government has requested the Government of Delhi to further widen it to accommodate the increasing traffic. It has been learnt that the Government of Delhi has appointed M/S RITES as a consultant to prepare a proposal for upgradation of this stretch.

(b) Sine the road falls under the jurisdiction of Government of Delhi, no time frame can be given for completion of the project at this stage. However, matter will be further persued with Government of Delhi.

श्री सुखबीर सिंह सोहना : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मन्त्री महोदय को बताना चाहूंगा कि इस सड़क को चौड़ा न करने से सारी स्टेट को बहुत नुकसान हो रहा है क्योंकि वहां पर सुबह-शाम तीन-तीन घण्टे तक ट्रैफिक का जाम लगा रहता है। अभी पैट्रोल पम्प को एन०ओ०सीज० देने की बात हो रही थी। महरौली-गुड़गांव रोड़ के ऊपर इनके बहुत ज्यादा कमर्शियल लाईसैंस दे दिए गए हैं और कई पैट्रोल पम्पस वहां पर चल रहे हैं। वहां पर ट्रैफिक कण्ट्रोल नहीं होता है। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक ट्रैफिक जाम रहता है तथा शाम को 5 बजे से रात के नौ बजे तक ट्रैफिक जाम रहता है। जो मल्टी नैशनल कम्पनियां हैं वे वहां पर आना-जाना पसन्द नहीं करती हैं। यहां पहुंचने की बजाय नोएडा में आदमी अपने ऑफिस में दस मिनट में पहुंच जाता है। मैं सी०एम० साहब से यह कहना चाहूंगा कि जितनी जल्दी हो सके दिल्ली गवर्नमैंट से बात की जाए। इसके साथ ही रंगपुर राजोखरी की तरफ से एक रोड़ और है उसका भी जल्दी से जल्दी निर्माण करवाया जाए। जब तीन एण्ट्रीज गुड़गांव की हो जाएंगी तो मैं यह समझता हूँ कि इससे ट्रैफिक कण्ट्रोल हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसके लिए जो भी समय निर्धारित किया जाना है वह निर्धारित किया जाए।

मुख्य मन्त्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, जैसे कि मैंने बताया है कि यह मामला दिल्ली गवर्नमैंट से कनैक्टिड है और हमारे पास जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार एम०सी०डी० को राईट्स ने रिपोर्ट दी है और उसके लिए दिल्ली गवर्नमैंट ने जमीन ऐक्वायर करनी है क्योंकि वहां पर कुल 35 मीटर चौड़ी सड़क है उसको बढ़ाकर 90 मीटर तक करना है उसके लिए जमीन ऐक्वायर की जानी है और हम पूरे प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी ही इस काम को पूरा किया जाए। जो ये ट्रैफिक की बात कर रहे हैं वह सारी बात हमारे ज्ञान में है हम इसके लिए दूसरा रास्ता निकाल रहे हैं जैसे 26 और 26-A सैक्टर से एक पेराफेरी रोड़ हमने बनायी है उस पर काम शुरू हो गया है उस पर साढ़े तीन करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। (विघ्न)

Repair of the Distributaries of Mahindergarh Canal

***21. Sh. Naresh Yadav :** Will the Minister for Irrigation be pleased to state whether it is a fact that the distributaries of Mahindergarh Canal in Ateli and Nangal Chaudhary Block has been damaged badly, if so, the steps taken or proposed to be taken to repair these distributaries?

राजस्व मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) : जी हां, श्रीमान् जी।

अटेली डिस्ट्रीब्यूटरी व नोलपुर डिस्ट्रीब्यूटरी जोकि क्रमश: अटेली व नांगल चौधरी खण्ड को पानी देती हैं, महेन्द्रगढ़ नहर से निकलने वाली नारनौल ब्रांच की शाखाएं हैं। दोनों डिस्ट्रीब्यूटरियां व उनकी सहायक प्रणालियां खराब हालत में होने के कारण अपनी अधिकृत क्षमता से प्रवाह करने में असमर्थ हैं । अटेली डिस्ट्रीब्यूटरी, सलीमपुर माइनर, नोलपुर डिस्ट्रीब्यूटरी और नागर माइनर अपनी लम्बाई के कुछ भाग तक ही चलती है। सिंचाई विभाग द्वारा अटेली डिस्ट्रीब्यूटरी, नोलपुर डिस्ट्रीब्यूटरी, सलीमपुर माइनर, अटेली माइनर, अटेली सब माइनर, नागर माइनर, शामपुर माइनर, धनलाल माइनर, बुधवाल सब माइनर, खेडी माइनर, रामपुरा सब माइनर और बेहली सब माइनर की गाद निकालने, तटबन्धों को मजबूत करने तथा लाईनिंग की मरम्मत करने का एक कार्यक्रम बनाया जा रहा है। इस प्रणाली को पूर्ण पुनर्वास की आवश्यकता है।

श्री नरेश यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय का धन्यवाद तो तब करूंगा जब वहां पर काम की कुछ शुरूआत हो जाएगी सबसे पहले मैं सरकार और मन्त्री जी का इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहूंगा कि पहली बार पानी नांगल चौधरी के आखिरी छोर तक पहुंचा है पिछली सरकार ने इसके लिए खूब प्रयास किए लेकिन पानी वहां तक नहीं पहुंचा क्योंकि उस सरकार के प्रयास ईमानदार नहीं थे। पहली बार कांग्रेस की सरकार ने, भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की सरकार ने ईमानदारी से प्रयास किया और दक्षिणी हरियाणा आखिरी छोर तक यानी नांगल चौधरी, नांगल दरगू तक पानी पहुंचा है (इस समय मेजें थपथपाई गई) अब जिस तरीके से, जिस स्पीड से नहरों में पानी बढ़ रहा है, आ रहा है और 20-20 दिन चल रहा है वह बहुत अच्छी बात है, स्पीकर सर, मैं यह पूछना चाहता हूं कि अटेली और नांगल चौधरी में नहरें अटी पड़ी है, दबी पड़ी है वहां पर कैसे काम चलेगा ? यहां पर फाईनांस मिनिस्टर जी भी बैठे हुए हैं, मंत्री जी आप इनसे यहीं पर जितना पैसा चाहिए है वह ले लें। हमारे यहां पर पानी का लैवल 1400 फीट नीचे चला गया है, उसको भी ऊपर लाने का प्रयास करें।

Mr. Speaker : Mr. Yadav, put the supplementary straightway. Don't deliver the speech.

श्री नरेश यादव : अध्यक्ष महोदय, दक्षिणी हरियाणा में वाटर लैवल को ऊपर लाने का एक ही तरीका है कि नहरों में पानी आए। मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से सवाल है कि वहां पर जितनी भी नहरें और नालें टूटे हुए हैं उनकी कब तक रिपेयर हो जाएगी ? आप इसके लिए समय निर्धारित कर दें ?

Mr. Speaker : Mr. Yadav, this is not the way. Please sit down.

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि पिछले 15 सालों से नहरों के रख रखाव का काम नहीं हुआ था और न ही उनकी मरम्मत की गई थी। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि इन्होंने कहा है कि अटेली डिस्ट्रीब्यूटरी, सलीमपुर माइनर, नोलपुर डिस्ट्रीब्यूटरी और नागर माइनर में पानी जा रहा है। पहले तकरीबन इनमें 60 प्रतिशत नहरों में टेल पर पानी नहीं पहुंच रहा था। इस सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से पानी को टेलों तक पहुंचाने की योजना बनाई है लेकिन यह सब फंडज की अवेलेबिलिटी पर निर्भर करता है

यह काम करने में 2 वर्ष लगेगें। हम यह सब काम इन स्टेजिज करेंगे क्योंकि इसमें काफी पैसा इन्वालव्ड हैं, इसमें 2.00 करोड़ रुपए इन्वालव्ड हैं। इसके अलावा एक बात मैं कहना चाहूंगा कि बी०एम०एल० कैनाल से हांसी लिंक ब्रांच के बीच एक लिंक कैनाल बनाने की जो बात है। मैं खासकर उस के लिए मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि इन्होंने यह योजना बनाई है अब बी०एम०एल० कैनाल से हांसी लिंक ब्रांच के बीच इस नयी कैनाल बनाने के बाद नहरों में 24 दिनों तक पानी चला करेगा। उस वक्त दक्षिणी हरियाणा की स्थिति सुधर जाएगी। हम यह सब काम फंडज की अवेलेबिलिटी के आधार पर और योजनाबद्ध तरीके से ही करेंगे।

श्री राधे श्याम शर्मा अमर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने नांगलदुर्ग तक पानी पहुंचाया है। लेकिन मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि वह पानी गांवों में कब पहुंचेगा ? अध्यक्ष महोदय, वहां पर आगे कोई भी नाला खुदा हुआ नहीं है जिसकी वजह से पानी आगे नहीं पहुंच पा रहा है। अब लोग वहां पर यह कह रहे हैं कि यह तो हमारा ड्रामा है। पीछे से तो पानी छोड़ दिया लेकिन आगे नाले खुदे हुए नहीं हैं इसलिए पीछे से पानी छोड़ने का कोई फायदा नहीं है। माननीय मंत्री जी, निजामपुर क्षेत्र, नांगल दुर्ग क्षेत्र और बुरवाल का क्षेत्र है, उसकी नहरों की खुदाई और पाईप लाईन बनाने का काम कब तक शुरू करवाएंगे ? अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं यह कहना चाहूंगा कि यह जो मंत्री जी दो करोड़ और दो साल वाली बात कर रहे हैं तो हम किसी भी एन०जी०ओ० से वह काम दो करोड़ की बजाए डेढ़ करोड़ में करवा देंगे और अगर डेढ़ करोड़ का इसका एस्टीमेटस है तो हम वह काम एक करोड़ में करवा देंगे। इसके अलावा इन्होंने जो टाईम पीरियड दो साल का बताया है तो उसको एक साल में करवा देंगे। क्या मंत्री जी किसी एन०जी०ओज. को यह काम देने का काम करेंगे ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने जवाब में स्पष्ट कर दिया है कि पानी की मात्रा कम है और एस०वाई०एल० का पानी अभी हमें नहीं मिला है। इसके बावजूद मुख्यमंत्री जी की मेहरबानी की वजह से ही बी०एम०एल० कैनाल और हांसी लिंक ब्रांच के बीच कैनाल बनेगी। यह स्कीम 2.60 करोड़ रुपए की है। इसको बनने में 2 वर्ष लगेंगे। मैं यह आश्वासन देता हूं कि जैसे ही हमें फंडज अवेलेबल होंगे तो जिन माईनर्ज का इन्होंने जिक्र किया है उनमें से कुछ माईनर्ज पर हम जरूर काम करेंगे।

श्री दिलू राम : स्पीकर सर, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ये नहरें जब से पक्की बनी हैं तब से किसानों को पानी नहीं मिल रहा है। मेरे हल्के में कम से कम 10 टेलें लगती हैं लेकिन उन टेलों से 10-10 और 12-12 किलोमीटर दूर पानी खड़ा है। आज सरकार कहती है कि हमने टेलों पर पानी पहुंचा दिया है। अध्यक्ष महोदय, हमारे वहां पर पैडी का एरिया है और वहां पर वाटर लैवल इतना नीचे चला गया है जिससे वहां पर किसान बहुत ही दुखी है। 12 सालों से आज तक वहां की नहरों की टेलों पर पानी नहीं पहुंचा है। मैं सरकार से यह आश्वासन चाहता हूं कि क्या वहां टेलों पर पानी पहुंचेगा ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, वैसे तो यह प्रश्न मेन सवाल से रिलेटेड नहीं है लेकिन फिर भी मैं उनको बताना चाहूंगा कि अगर इनको कोई स्पैसिफिक दिक्कत है तो ये लिखकर हमें दे दें, जहां-जहां भी नहरों में टेल पर पानी नहीं पहुंच रहा है वहां-वहां हम कोशिश करेंगे कि उन नहरों में टेल पर पानी पहुंचे।

श्रीमती शकुन्तला भगवाड़िया : स्पीकर सर, यह बात सही है कि पहले नहरों में बहुत कम पानी जाता था और अब नहरों में काफी समय तक पानी चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, सूबासेड़ी, भगवानपुर, खुरमपुर, टीकला, पनवाड़, प्राणपुरा, रानोली, रनसी मानजरी एवं पाँवटी गांवों की नहरें तो पहले से ही खुदी हुई हैं लेकिन ये सारी नहरें अटी पड़ी हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि क्या इनको ठीक करवाकर ये इनमें पानी पहुंचाएंगे ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, पिछले 15 सालों के अंदर जो हालात हुए हैं उसी का परिणाम हैं कि नहरें पूरी तरह से टूटी पड़ी हुई हैं और खास तौर से जे०एल०एन० सिस्टम के अंदर की नहरों में तो बिल्कुल भी पानी नहीं जाता था लेकिन अब पहली बार 250 करोड़ रुपये इस वर्ष में हमने इसके लिए रखे हैं। जहां जहां इनको दिक्कत आ रही है ये हमें लिखकर दे दें, उनको दिखवा लिया जाएगा और जिन नहरों में पानी टेल पर नहीं पहुंच रहा है उन नहरों में हम पानी पहुंचाने का प्रयास करेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Please, take your seat. (Interruptions)

श्री भरत सिंह : अध्यक्ष महोदय, आज केवल दक्षिणी हरियाणा की ही बात की जा रही है, सरकार को बाकी हरियाणा की बात भी सोचनी चाहिए। अम्बाला से लेकर पानीपत जिले तक की नहरों में पहले ताजेवाला से पानी छोड़ा जाता था। हजारों जंगली जानवर आज यमुना में नहाना चाहते हैं लेकिन वे परेशान हैं क्योंकि यमुना सूखी पड़ी हुई है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जब इतना पानी दक्षिणी हरियाणा के लिए छोड़ा जा रहा है तो क्या दो तीन दिन के लिए पानी यमुना में नहीं छोड़ा जा सकता ताकि वहां के लोग और जानवर इस गर्मी में परेशानी से बच सकें ? **(इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया)**

Merger of Primary School Teachers

***59. Shri Sher Singh :** Will the Minister for Education be pleased to state —

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to merge Primary School Teachers with the Education Department appointment of whom was made by the Zila Parishad, during the last year ; and

(b) whether it is a fact that the teachers mentioned in part (a) above have not paid their salary since January, 2005, if so, the reasons thereof, togetherwith the time by which the payment of the salary is likely to be made to them ?

Education Minister (Sh. Phool Chand Mullana):

(a) The matter is under consideration.

(b) The salary of 3606 JBT teachers appointed by Zila Parishads in July, 2004 has been paid. However, the salary of 2856 teachers recruited by Zila Parishads in December, 2004 has not been paid so far, for want of financial sanction. The issue of payment of salary will be resolved shortly.

आई०जी० शेर सिंह : स्पीकर सर, काफी टीचर अभी जे०बी०टी० में भर्ती किए गए हैं। पिछली सरकार द्वारा भी तथा हमारी इस सरकार द्वारा भी शायद पहली क्लास से अंग्रेजी विषय को पढाना अनिवार्य किया जा रहा है तो मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या ये सभी टीचर अंग्रेजी पढ़ाने के लायक हैं और अगर पढ़ाने लायक नहीं है तो क्या इनके लिए इस बारे में कोई कोर्स करवाने का प्रावधान किया जाएगा ?

श्री फूलचन्द मुलाना : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। अंग्रेजी तो हम पहली क्लास से पढाना शुरू कर रहे हैं और यदि अध्यापक अंग्रेजी पढ़ाने के काबिल नहीं है तो सरकार ने विचार किया है कि जे०बी०टी० की ट्रेनिंग करने के लिए प्लस टू के बजाए बी०ए० पास बच्चों का जे०बी०टी० में दाखिला करेंगे।

Setting up of 33 kv Sub-station, Sherla and Singhani

***39 Shri Somvir Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the time by which the 33 kv Sub-station, Sherla in district Bhiwani will be started/completed the foundation stone of which was laid down on 16-12-2004; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to set up 33kv Sub-station at Singhani in district Bhiwani; if so, the time by which said proposal is likely to be implemented ?

Chief Minister (Shri Bhupinder Singh Hooda):

(a) The 33kv Sub-station, Sherla is likely to be commissioned by December 2006.

(b) There is a proposal under consideration to create 33kv Sub-station at Singhani in district Bhiwani.

श्री सोमबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस सब-स्टेशन का फाउंडेशन स्टोन 2004 के दिसम्बर महीने में रखा गया था। करीब 6 महीने इस काम को हो गये हैं। मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि इस देरी का क्या कारण है ? इसके अलावा जो भिवानी जिले में सिंघानी के अंदर 33 के०वी० सब-स्टेशन बनाने के लिए प्रपोजल भेजी हुई है। चीफ इंजीनियर, हिसार को यह प्रोपोजल भेजे हुए 2 साल से ज्यादा समय हो गया है मैं जानना चाहूंगा कि इस प्रोपोजल को मंजूर करने में कितना समय और लगेगा ? इसके अलावा जो ढिगावा से सिंघानी गांव को बिजली आती है उसका पावर स्टेशन कितना ओवरलोडेड है ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : स्पीकर साहब, जैसा इन्होंने जिकर किया है तो इसका Foundation stone was laid down on 16-12-2004. It takes one and a half year for commissioning and erection. It will take time. It will be completed by 2006. About Singhani, this is at preliminary stage. Village has offered land but feasibility report has not come . If, we order for the feasibility report, it will take 3 months and if it is found positive then we will take up it.

राव दान सिंह : स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि हमारा क्षेत्र ट्यूबवैल पर कृषि के लिए आधारित है वहां पर एक सेलगं गांव है जो कि कई गांवों का बड़ा समूह है जहां पर काफी लम्बे समय से एक सब-स्टेशन लगाने की मांग चली आ रही है। मुख्यमंत्री जी अभी पिछले दिनों जब वहां दौरे पर थे तब मी उनके समक्ष यह मांग आई थीं। मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या ऐसी कोई प्रपोजल प्रस्तावित है कि आने वाले समय के अंदर वहां पर 33 के०वी० का सब-स्टेशन लगाया जाएगा।

Shri Bhupender Singh Hooda : It is not the part of question.

श्री सोमवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने ढिगावा का 133 के०वी० का पावर हाउस है उसके बारे में पूछा था, यह 1986 के अंदर बना था। वहां से बिजली सिंघानी गांव को आती है, मैंने जानना चाहा था कि ढिगावा का पावर हाउस कितना ओवरलोडिड है ?

Mr. Speaker : It is not possible to tell about a particular station.

Check the Un-employment in the State

***36. Dr. Sita Ram :** Will the Minister for Finance be pleased to state the steps so far taken or proposed to be taken to check the problem of increasing un-employment in the State ?

Finance Minister (Shri Birender Singh) : Sir, a statement is placed on the Table of the House.

Statement

The Government has announced its new Industrial Policy, which has become applicable with effect from 6th June 2005. The basic objective of the Industrial Policy is to create maximum employment opportunities in the manufacturing and service sectors by developing high-class infrastructure, simplification of rules and regulations governing industry and incentives/concessions to the industry in the backward/ rural areas. The State Govenment also plans to develop economic hubs at strategic locations for the overall growth of the economy. It is estimated that these steps would create employment for about one million persons in the next ten years.

The Rural Development Department is implementing various Centrally Sponsored Poverty Alleviation Programmes in the rural areas, under the Swaranjayanti Gram Swarozgar Yojana and Sampooran Grameen Rozgar Yojana (SGRY). The target groups consist of the families living below the poverty line. The programmes are implemented in accordance with the prescribed guidelines issued by the Ministry of Rural Development, Government of India. Under the Swaranjayanti Gram Swarozgar Yojana (SGSY), 14,132 beneficiaries were provied with financial package in the shape of subsidy and bank loan, to the tune of Rs. 1566.71 lacs during 2004-2005. The Govt. of India had merged the schemes of

Jawahar Gram Samridhi Yojana and Employment Assurance Scheme from the year 2001-2002 onwards and had launched a new scheme known as Sampooran Grameen Rozgar Yojana (SGRY). This scheme has been designed to provide additional wage employment in the rural areas and also creation of durable community assets at the village level. The SGRY is open to all rural poor who are in need of wage employment and desire to do manual and unskilled work in the rural areas. During the year 2004-2005, a total number of 18, 135 works were undertaken generating 70.12 lac Mandays on which an expenditure of Rs. 6794.28 lacs was incurred.

The State Urban Development Society, Haryana is implementing Swarna Jayanti Shahari Rozgar Yojana (SJSRY) with the object of providing Self-Employment and Wage-Employment to the Below Poverty Line (BPL) urban people. During the year 2004-2005, 1845 persons were provided loan and subsidy and 0.35 lac Mandays were generated.

From March 2005 to May 2005, the Haryana Scheduled Castes Finance and Development Corporation has assisted, 2,173 Scheduled Caste persons for taking up Self-Employment schemes by providing them financial assistance of Rs. 511 lacs, which includes Rs. 168 lacs as subsidy. The Corporation proposes to assist 15,000 Scheduled Caste persons by providing them a total financial assistance of Rs. 4971 lacs for Self-Employment schemes during the current financial year 2005-2006.

Haryana Backward Classes and Economically Weaker Section Kalyan Nigam proposes to provide self-employment to 5,000 persons during 2005-2006.

Fisheries Department has provided technical and financial assistance to new 116 fish farmers during the year 2004-2005 and also provided indirect part-time employment to 158 persons involved in fish seed supply, fish harvesting and fish marketing activities. The department plans to provide direct full time employment opportunities to an additional 500 persons by adopting fish farming as a profession during the year 2005-2006.

Development and Panchayats Department has spent Rs. 1427.50 lacs approximately for generating 15,86,111 Mandays of employment. The department proposes to generate 30,87,500 Mandays of employment at an estimated cost of Rs. 2778.75 lacs during the year 2005-2006.

Animal Husbandry and Dairy Development Department established 2,112 dairy units during 2004-2005 and a target of 2500 Dairy Units has been laid down for the current financial year involving self-employment of 2500 persons.

The number of job seekers who were placed in gainful employment through Employment Exchanges during 2004-2005 is 2,850. The number of job seekers on the live register of the Employment Exchanges in the State, as on 30-4-2005 was 9,83,553. The number of Conselling/Vocational/Career Guidance Groups organised during the year 2004-2005 is 4,788, in which 2,14,462 participants took part. An amount of Rs. 543.59 lacs was disbursed from 1-4-2004 to 30-4-2005 as Unemployment Allowance. The number of eligible applicants as on 30-4-2005 stood at 1,32,651.

डॉ० सीता राम : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि उन्होंने अपने जवाब में बताया है कि हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम ने 2005-2006 वित्त वर्ष के दौरान स्वरोजगार योजना के लिए केवल 49.71 करोड़ रुपया अनुसूचित जाति के 15 हजार व्यक्तियों की सहायता के लिए रखा है। इन्होंने इसके अलावा कहीं कोई जिक्र नहीं किया कि बेरोजगारी को कैसे दूर किया जाएगा क्योंकि चुनाव के दौरान इन्होंने बड़े जोर शोर से कहा था कि सरकार आने के बाद बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा।

Mr. Speaker : Dr. Sahib, don't deliver the speech. Please put the supplementary.

डॉ० सीता राम : सर, मैं क्वैश्चन ही पूछ रहा हूं। चुनाव के समय यह प्रचारित किया गया था कि सरकार आने के बाद बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा। कृपा करके यह बताने का कष्ट करें कि इसके बारे में कोई अलग से स्टैप्स उठाए गए हैं या नहीं ?

श्री बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, सम्मानित सदस्य ने जानना चाहा था कि अनइम्प्लौयमैंट को चैक करने के लिए सरकार क्या-क्या प्रयत्न कर रही है। इसके बारे में मैंने जो ब्यौरा दिया है इन्होंने उसमें से केवल एक पार्ट का हवाला दे दिया कि शिडयूल्ड कास्ट्स के लोगों की सहायता के लिए 49.71 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया है। ये सारी स्टेटमैंट को जब पढ़ेंगे तो उससे इनको पता लगेगा कि हर क्षेत्र के अंदर बेरोजगारी की जो समस्या है वह किसी एक साधन से नहीं निपटी जा सकती। हमने 6 जून को जो औद्योगिक नीति की घोषणा की है, उसमें अगर ये झांककर देखेंगे तो पाएंगे कि उससे 10 लाख के करीब रोजगार उपलब्ध होंगे। इनके समय में उद्योग पलायन कर गए थे और उद्योगपतियों के घरों के या बिल्डिंगों के सामने 4-4 फुट गहरी खालियां खुदवा दी गई थीं ताकि उनका सामान न जा सके, न आ सके। जब तक पैसे की बात तय नहीं हो जाती थी तब तक उनके साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाता था। आज हम हरियाणा के अन्दर एक ऐसा वातावरण तैयार कर रहे हैं जिसमें उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और बाहर से निवेश के लिए हमारा अन्दाजा है कि नई औद्योगिक नीति के अनुसार 2 लाख करोड़ रुपये तक के निवेश की हम कोशिश करेंगे। यह तो एक पक्ष है दूसरी तरफ कृषि को उन्नत बनाने के लिए, कृषि के धन्धे को एक लाभकारी धन्धा बनाने के लिए भी हमने पग उठाये हैं। जैसे डाईवर्सीफिकेशन है और अच्छी मार्कैटिंग फैसिलीटीज हैं उनको हम बढ़ावा दे रहे हैं क्योंकि ये दो क्षेत्र ऐसे हैं जिनसे कि मैं समझता हूं कि 70 प्रतिशत तक बेरोजगारी की समस्या हल हो सकती है। इसके अलावा जो सरकारी नियुक्तियां हैं उनमें जिस प्रकार से पहले धांधलेबाजी होती थी, उसको खत्म करने के लिए और पारदर्शिता स्थापित करने लिए हमने हरियाणा स्टाफ सिलैक्शन कमीशन को भंग कर दिया है। इसकी वजह से एक अशांन्ति और एक ऐसा वातावरण नौजवानों में पैदा हो गया था कि उनको यह लगता था कि हमारा नम्बर नौकरी के लिए कभी नहीं आयेगा। इस सरकार ने आश्वासन दिया है और आज के हमारे जो मुख्यमंत्री हैं जब ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष होते थे तब भी यह कहते थे कि हमारा यह लक्ष्य है कि हर हाथ को काम मिले और इस बात को हमने अपने चुनाव घोषणा-पत्र में भी रखा था। हम अपने निश्चय पर आज भी दृढ़ है। आप देखेंगे कि आने वाले समय में बेरोजगारी को दूर करने के लिए हम काम करेंगे और इसमें हम कामयाबी हासिल करेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है।

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से वित्त मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि अभी-अभी इन्होंने बेरोजगारी को दूर करने के बारे में कहा है। दो-तीन दिन पहले एक लेडी कांस्टेबल ने आत्महत्या की थी क्या यह भी इनके आश्वासन का हिस्सा है या नहीं ?

श्री बीरेन्द्र सिंह : अगर ऐसा कोई आत्महत्या का दोष किसी पर जाता है तो वह श्री ओमप्रकाश चौटाला और उसकी पार्टी पर जाता है आज की कांग्रेस की सरकार पर नहीं जाता।

श्री राधेश्याम शर्मा अमर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस तरह जो आत्म हत्याएं हुई हैं वह इसलिए हुई है क्योंकि पिछली सरकार ने भर्तियों में गड़बड़ी की थी। क्या मंत्री जी या सरकार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी या नहीं ?

श्री बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, जब इस वर्ष का बजट पेश हुआ था उस दिन प्रैस के सामने मुख्यमंत्री जी ने सरकार का पक्ष रख दिया था। आज भी हमारा वही पक्ष है। मैं सदन को बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से और हड़बड़ाहट से एवं जिस राजनीतिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर वोट हासिल करने के लिए थे नियुक्तियां की गई थी, उसमें पूरी पद्धति को अडोप्ट नहीं किया गया था इसलिए यही कारण है कि हमें इन नियुक्तियों को विदड्रा करना पड़ा।

मुख्यमन्त्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, जो यह चर्चा की गई है इस बारे में मैं सदन को बताना चाहूंगा। मैं इस बारे में पहले भी कह चुका हूं कि जिस प्रकार से ये भर्तियां की गई हैं उससे इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है इसलिए श्री ओमप्रकाश चौटाला को पूरे हरियाणा से और उन लोगों से माफी मांगनी चाहिए। उस बिल के ओबजैक्टस और रीजन्ज में यह लिख दिया कि एच०आई०एस०एफ० का यह खर्चा इण्डस्ट्रीज, बैंक, बोर्ड और कारपोरेशंज वहन करेंगें और जब एक्ट रखा गया और वह पास किया गया तो उसमें यह लिखा कि नोटिफिकेशन होगी, एक डी०जी०पी० बनेगा, रूल्ज बनेंगे लेकिन कोई कुछ प्रोवीजन नहीं किया गया। यह सरकार आने के बाद हमने पूरा प्रयास किया कि इन बच्चों के भविष्य के साथ जो पहले खिलवाड़ किया गया है वह आगे न हो। हम किसी के बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहते। हमारी सरकार ने पूरा प्रयास किया और सारी इण्डस्ट्रीज, बैंक, बोर्ड और कारपोरेशंज को लिखा और उनसे पूछा कि क्या उनको इस फोर्स की जरूरत है या नहीं ? लेकिन किसी की तरफ से कोई रिक्वायरमैंट नहीं आई। हमारी सारी कोशिश करने के बाद भी सरकार के पास कोई रास्ता नहीं निकला इसलिए हमें इस भर्ती को निरस्त करना पड़ा। उस समय मैंने कहा था कि हम जल्दी ही पुलिस रिक्रुटमैंट करेंगे, दूसरे विभागों की भी रिक्रुटमैन्ट करेंगे। उस भर्ती में इन बच्चों को जिनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, उनके साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। उनको इस भर्ती में लीयरेज दी जायेगी। पहली सरकार ने कभी लीवरेज नहीं दी थी, यह बात सारी असैम्बली को पता है कि जब श्री ओमप्रकाश चौटाला ने यह बात असैम्बली में कही थी कि इस भर्ती का खर्चा इण्डस्ट्रीज, बैंक, कारपोरेशंज वहन करेंगी। परन्तु बहुत से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। इसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए। यह सरकार किसी के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करेगी। यह सरकार जो कार्य करेगी, पक्के करेगी। ये बच्चे हमारे बच्चे हैं हम उनके हितों का पूरा ध्यान रखेंगे।

Mr. Speaker : This is the last supplementary. I will not allow after that. Indora Ji, please go ahead.

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि हम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। अगर मुख्यमंत्री महोदय को यह विसंगतियां लगती थीं तो बजाय इन विसंगतियों को दूर करने के सरकार ने क्यों ऐसा कदम उठाया कि उन बच्चों को आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ा ? (विघ्न)

Mr. Speaker : Dr. Sahib, it is not the supplementary. Please take your seat. Mr. Indora, it is not the way.

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : इन्दौरा साहब, आप लोगों ने ही उनको बाहर निकाला और उनको आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया। यह सब तुम्हारी कार्यवाही है। चुनाव से पहले लोगों को झूठे सपने दिखाकर हरियाणा के लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम आप लोगों द्वारा ही किया गया है। (शोर एवं व्यवधान)

परिवहन मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि माननीय इन्दौरा जी और उनके नेता की आत्मा आज उनको कचोटती जरूर होगी क्योंकि इन्होंने 27 हजार कर्मचारियों की बर्खास्तगी की । उन कर्मचारियों के परिवार आज दयनीय हालत में दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। इन्दौरा जी और उनकी पार्टी के नेता आज तो मगरमच्छी आंसू बहाते हैं लेकिन उस वक्त ये कहां गए थे जब कर्मचारी उनके पास आते थे ? इन्दौरा जी और उनकी पार्टी के नेता और इनकी पार्टी के लीडर उनको लाठियों से पिटवाते थे। 27-27- हजार कर्मचारियों की बर्खास्तगी इन्होंने की । I am on the floor, you have been in the Parliament. I am still speaking. I have not said down earlier. (Interruptions) मगरमच्छी आंसू अगर किसी ने बहाए, हरियाणा के लोगों के साथ अगर किसी ने अन्याय किया तो वह लोकदल के साथियों ने किया, इन्दौरा जी और इनके नेता ने किया, जिससे स्टेट एक्सचैकर पर 47 करोड़ रुपये का खर्च पड़ा। इन्होंने बच्चों की नियुक्तियां की और उनको बहकाया, इसलिए इनको खुद को, इनकी पूरी पार्टी को उन अभिभावकों से, हरियाणा के नौजवानों से और उन बच्चों से माफी मांगनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

तारांकित प्रश्न संख्या-49

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री उदयभान सदन में उपस्थित नहीं थे।)

Cooperative Sugar Mill, Panniwala Mota

*4. **Shri Karan Singh Dalal :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the year-wise total quantity of sugar produced by the Cooperative Sugar Mill, Panniwala Mota in district Sirsa, since its inception;

(b) the year-wise number of crushing days of the aforesaid Sugar Mill since its inception till to-date;

(c) the year-wise details of the sugarcane growing area of Sirsa district bonded to the Sugar Mill referred to in part (a) above since its inception ;

(d) the year-wise details of the income earned and expenditure incurred by the Sugar Mill referred to in part (a) above since its inception till to-date; and

(e) whether there is any proposal under consideration of the Government for closing the Sugar Mill as referred to in part (a) above ?

Chief Minister (Shri Bhupinder Singh Hooda) : Statement is laid on the table of the House.

Statement

(a) Total quantity of Sugar produced by the Coop. Sugar Mill Panniwala Mota in district Sirsa since inception of the Mill is given as under :—

Year	Quantity of sugar produced in Qtls.
2001-02	83,694
2002-03	1,32,820
2003-04	47,780
2004-05	Nil
Total	**2,64,294**

(b) The year-wise crushing days of the mill till to-date are given as under:—

Year	Crushing days by Mill till date.
2001-02	66
2002-03	86
2003-04	40
2004-05	Nil
Total	**192**

(c) The year-wise details of the sugarcane growing area of Sirsa district bonded to the Sugar Mill Panniwala Mota since its inception given below :—

Year	Sugar cane growing area (in Acres)
2001-02	4,831
2002-03	16,372
2003-04	4,220
2004-05	342
2005-06	200
Total	**25,965**

(d) The year-wise details of income earned and expenditure incurred by the Sugar Mill Panniwala Mota since its inception till to date are given below :—

Year	Amount in Lacs Rs.	
	Income earned	Expenditure incurred
2001-02	1189.60	1245.62
2002-03	2862.14	3306.00
2003-04	2842.89	3465.55
2004-05	2128.13	2263.93
2005-06 (Upto 31-5-2005)	591.92	659.66
Total	**9614.68**	**10940.76**

(e) Not yet, Sir.

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, जो जानकारी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सदन के पटल पर रखी है उससे यह साफ प्रतीत होता है कि यह जो पन्नीवाला मोटा, सिरसा में चीनी की मिल लगाई गई है उस मिल के लिए न गन्ना था और उस वक्त कृषि विभाग, जो कि चीनी मिल लगाने के लिए अपनी राय देता है, के अधिकारियों ने साफ तौर पर कोओपरेटिव मिनिस्टर और मुख्यमंत्री महोदय को लिखकर कहा कि यह जगह चीनी मिल लगाने के लिए ठीक नहीं है क्योंकि उस एरिया में गन्ना नहीं होता। उस वक्त जानबूझकर केवल अपने राजनीति के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए वहां मिल लगाई गई। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से 2-3 बातें पूछना चाहता हूं। पहला तो यह कि इस मिल पर कितना पैसा खर्च हुआ, दूसरा जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने सदन के पटल पर जानकारी दी कि वर्ष 2004-2005 में चीनी की मिल में कोई पिराई नहीं हो रही तो कितने मुलाजिम इस मिल के अन्दर सरकारी खजाने से तनख्वाह ले रहे हैं ?

Mr. Speaker : Do not combine all those. You will get another opportunity. Do not connect all these questions.

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहता हूं कि यह मिल 126 एकड़ जमीन पर है और इसकी कोस्ट आफ प्रोजैक्ट 46.71 करोड़ आई है। जैसा कि कर्ण सिंह दलाल ने कहा और पहले सवाल भी उठा था कि पिछली सरकार ने ऐसे कई कार्य किए। उस सरकार में न केवल बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया बल्कि हरियाणा के राजकीय कोष के साथ भी खिलवाड़ किया गया। इसलिए आज वह चीनी मिल 43 करोड़ रुपये का कुल घाटा अब तक दे चुकी है। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि जहां कहीं भी चीनी मिल लगाई जाती है वहां कम से कम साल में 180 दिन गन्ना आना चाहिए, 160 दिन से कम तो बिलकुल भी नहीं होना चाहिए। लेकिन उस चीनी मिल में कभी भी 86 दिन से ज्यादा गन्ना नहीं आया। 2003-04 में तो केवल 40 दिन ही गन्ना पिराई के लिए आया और वह भी बाहर से

लाया गया था। अध्यक्ष महोदय, जहां तक कर्मचारियों का प्रश्न है, उस चीनी मिल में 312 कर्मचारी हैं जो इस समय अपने घर पर बैठे हुए हैं। सरकार ने फैसला लिया है कि उन कर्मचारियों को कहीं दूसरी चीनी मिलों में एडजैस्ट किया जायेगा और इस मिल को कोई प्राईवेट पार्टी लीज पर लेने के लिए तैयार होगी तो यह मिल लीज पर दे दी जायेगी।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, एक तो यह चीनी मिल कानून को ताक पर रखकर बिना जरूरत के लगायी गई जिससे सरकारी खजाने पर बहुत भारी बोझ पड़ा। कुल मिलाकर पिछली सरकार की इस तरह की करतूतों से हरियाणा की जनता पर 22.50 हजार करोड़ रुपये का कर्ज खड़ा हो गया। अध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से यह चीनी मिल पिछली सरकार ने स्थापित की, इसमें कर्मचारियों की भर्ती की जो घर बैठे तनख्वाह लेते रहे और जिससे सरकारी खजाने पर बोझ पड़ा तो क्या मुख्यमंत्री जी बतायेंगे कि क्या इसके लिए उस वक्त के दोषी कोओपरेटिव मिनिस्टर, मुख्यमंत्री और जो अधिकारी इसमें शामिल थे उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ?

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, This is not a part of the question. लेकिन जहां तक इस मिल का सवाल है हमारे काबिल दोस्त बैठे हुए हैं अगर चौधरी देवी लाल ट्रस्ट इस मिल को लेने के लिए तैयार है तो सरकार पांच करोड़ रुपये के घाटे तक कर्मचारियों सहित यह मिल उनको देने के लिए तैयार है।

श्री एस०एस० सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, पिछली सैप्लीमैंट्री के सवाल में मुख्यमंत्री जी ने बताया कि पिछली सरकार के मुख्यमंत्री ने स्टेट को बहुत सी जगहों पर चुना लगाया है। चाहे पश्चीवाला मोटा चीनी मिल का मामला हो, चाहे सिरसा यूनिवर्सिटी का मामला हो या कोई और मामला हो, हर जगह पिछली सरकार के मुख्यमंत्री ने हरियाणा की जनता को चुना लगाने का कार्य किया। मेरा प्रश्न यह है कि पिछली सरकार के मुख्यमंत्री ने अपने राजनैतिक स्वार्थ को साधने के लिए कानून को ताक पर रखकर गैर कानूनी तरीके से जो कार्य किये जिससे सरकारी खजाने पर और प्रदेश की जनता पर भारी बोझ पड़ा तो क्या हमारे मुख्यमंत्री महोदय उन सभी प्रकरणों की इन्क्वायरी करवाकर जो भी दोषी हैं, उनकी जायदाद से नुक्सान की रिकवरी कराने का कार्य करेंगे ताकि भविष्य में कोई इस तरह का कार्य न करे ?

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मेरे भाई ये जो सवाल उठा रहे हैं इनका मैं एक ही जवाब दे सकता हूं कि **हाल न पूछो मेरे कारोबार का, इस अन्धी नगरी में आईना बेच रहा हूं।**

Small Scale Industries

***10. Shri Dharam Pal Singh Malik :** Will the Minister for Industries be pleased to state—

(a) the names of places in urban and rural areas in the State separately where new Small Scale Industries were established during the year 2000 to 2005;

(b) the details of the Government financial assistance to the aforesaid industries ; and

(c) the number of industries out of those referred to in part (a) above are in working condition ?

श्री अध्यक्ष : इस क्वैश्चन के बारे में मन्त्री जी की तरफ से टाईम एक्सटैंड करने के बारे में रिक्वैस्ट आई है जो ग्रान्ट कर दिया गया है। लैटर इस प्रकार है :—

Interim Reply

Lachhman Dass Arora

Industries & Urban Development
Minister, Haryana, Chandigarh.

Dated 8-6-2005

Sub : **Exemption of reply to Started Question No. 10.**

Dear Bhai Sahab,

I would like to draw your kind attention to the Starred question No. 10 asked by the Hon'ble MLA, Sh. Dharam Pal Singh Malik regarding names of places in the urban and rural areas in the State, separately where new small scale industries were established during the year 2000-2005 alongwith details of financial assistance provided by the Government and the number of such industries which are now in working condition.

The information to this question is voluminous as more than 5000 SSI units were established in the urban and rural areas of the State in the last five years. To know how many of these are working at present, it needs a survey. Therefore, for giving comprehensive and correct reply, it is necessary to make collection of complete information which would require a survey to be conducte. Thus, at present it is not feasible to give proper reply to this question and atleast a period of six months is required to complete and compile this voluminous information. Under the circumstances, I request you to please grant exemption for giving reply to this question.

Yours sincerely,

(Lachhman Dass Arora)

Sh. Harmohinder Singh Chatha, Speaker,
Haryana Vidhan Sabha, Chandigarh.

Consstruction of Bus Stand in Narnaund City

***26. Shri Ram Kumar Gautam :**—Will the Minister for Transport be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct bus stand in Narnaund City, district Hisar ?

Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Yes, Sir.

श्री राम कुमार गौतम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि नारनौंद में इस बस अड्डे की आधारशिला रखे हुए दस साल हो गये लेकिन आज तक भी इस का निर्माण नहीं हुआ है इसलिए मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह बस अड्डा कब तक बनकर तैयार हो जायेगा ? समय सीमा के बारे में बताया जाये कि इसका काम कब शुरू किया जायेगा और कब तक यह बनकर तैयार हो जायेगा, वहां जगह भी मौजूद है ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने साथी को बताना चाहूंगा कि इनसे पहले जो वहां से विधायक थे वे इनके पडोस में बैठी पार्टी से थे और उन्होंने नारनौंद बस अड्डे का काम रूकवा दिया था। यह रिकार्ड की बात है। यह पहली बार नहीं हुआ, यह उनकी रिवायत का एक हिस्सा है। हमने इसकी जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया था, उस कमेटी की रिपोर्ट आ चुकी है। हम जल्दी से जल्दी इसका निर्माण कार्य शुरू करवाकर अगले वर्ष के अंत तक इसका निर्माण कार्य पूर्ण करवा देंगे। सरकार की तरफ से इस बस अड्डे का ठेका देने की प्रक्रिया शुरू करवा दी है।

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय परिवहन मन्त्री जी से यह जानना चाहती हूं कि क्या कलायत में बस स्टैंड के निर्माण का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्या को यह बताना चाहूंगा कि कलायत में बस स्टैंड बनाना मन्जूर कर लिया गया है और इसके कार्य को प्राथमिकता के आधार पर हम करवाएंगे और जल्दी ही यह बस स्टैंड बन कर तैयार हो जाएगा।

Setting up of a Medical College or Hospital

***22. Shri Naresh Yadav :** Will the Minister for Health be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to set up a Medical College or Government Hospital on the pattern of All India Institute of Medical Sciences (A.I.I.M.S.) Delhi in district Mohindergarh?

स्वास्थ्य मन्त्री (बहिन करतार देवी): नहीं, श्रीमान् जी।

श्री नरेश यादव : अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मन्त्री महोदया से महेन्द्रगढ़ जिले में एक मेडीकल कॉलेज बनाने के बारे में सवाल पूछा था लेकिन मन्त्री महोदया ने केवल 'नो सर' कह कर जवाब दे दिया । मैं माननीय मन्त्री महोदया से यह पूछना चाहता हूं कि क्या वहां पर मेडिकल कालेज बनवाया जाएगा ?

बहिन करतार देवी : अध्यक्ष महोदय, मैंने भिवानी में मेडकल कालेज खोलने से संबंधित प्रश्न पर जवाब देते समय ही बता दिया था कि महेन्द्रगढ़ में कोई मेडिकल कॉलेज बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन हैं ।

श्री नरेश यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय हैल्थ मिनिस्टर महोदया को बताना चाहता हूं कि मन्त्री महोदया ने केवल 'नो सर' कह दिया। अध्यक्ष महोदय, हमारा पूरा दक्षिणी हरियाणा सैनिकों का इलाका है और हमारे काफी भाई फौज, पुलिस तथा फोर्सिज में काम करते हैं। वहां पर उनके बच्चे अकेले रहते हैं और इलाज के अभाव में उन्हें बहुत मुश्किल होती है। हमारे यहां पर अगर किसी व्यक्ति का कोई एक्सिडैंट हो जाता है तो इलाज के अभाव में वे व्यक्ति दम तोड़ देते हैं। इसके साथ ही मैं यह कहना चाहूंगा कि वहां पर मेडिकल कॉलेज तथा मेडिकल होस्पीटल की मांग वर्षों से चली आ रही है। हमारा इलाका सबसे ज्यादा दूर है। हमारे चारों तरफ राजस्थान का इलाका लगता है। दक्षिणी हरियाणा के बीच के क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज तथा मेडिकल होस्पीटल अगर बन जाए तो हमारे लोगों का बहुत ही भला होगा। हमारे दक्षिणी हरियाणा के साथ-

[श्री नरेश यादव]
साथ उत्तरी-पूर्वी राजस्थान का ऐरिया भी कवर हो जायेगा। सारे अस्पतालों में मरीजों की भीड़ बहुत बढ़ गई है। हमारे ऐरिया के लोग मरीजों को जयपुर या रोहतक लेकर जाते हैं जो कि 150 किलोमीटर दूर पड़ते हैं। मैं माननीय हैल्थ मिनिस्टर साहिबा से यह जानना चाहता हूं कि वहां पर मेडीकल कॉलेज तथा मेडीकल होस्पीटल क्यों नहीं बन सकता है ? क्या वे वहां पर मेडीकल कॉलेज तथा मेडीकल होस्पीटल बनवाने का कष्ट करेंगे (विघ्न) क्या इस मामले में सरकार की कोई कमी है या पैसे की कमी है ?(विघ्न)

Providing of Text Books

***60. Shri Sher Singh :** Will the Minister for Education be pleased to state :—

(a) whether the text books prescribed for April, 2004 under the Sarva Shiksha Abhiyan was being supplied upto February, 2005; if so, the action taken against the Agency who supplied the text books lately; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to provide the text books in time (April) in future ?

शिक्षा मंत्री (श्री फूलचंद मुलाना) :

(क) मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हरियाणा द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत मुफ्त पाठ्य-पुस्तकें अधिकतर मुद्रित करके फरवरी, 2004 से जुलाई, 2004 तक सप्लाई की गई यद्यपि कुछ पुस्तकों की सप्लाई बाद में जारी रही ।

(ख) वर्तमान वर्ष के लिए मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग ने कक्षा 2 की एक पाठ्य-पुस्तक तथा कक्षा 4 की एक पाठ्य पुस्तक जिसकी सप्लाई 15-7-05 से पहले होने की उम्मीद है को छोड़कर 5वीं कक्षा तक की सभी पुस्तकों की सप्लाई कर दी है। छठी से आठवीं तक की कक्षाओं के लिए निजी पार्टियों से मुद्रण करवाने की निविदा अनुमोदित कर दी गई है तथा सप्लाई जुलाई 2005 की समाप्ति से पूर्व होने की उम्मीद है।

श्री अध्यक्ष : अब क्वैश्चन आवर समाप्त होता है।

नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Vacant Posts of Lineman, A.L.M., A.F.M. etc.

***40. Shri Somvir Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that some posts of Lineman, A.L.M., A.F.M., A.S.S.A., U.D.C. and S.D.O. are lying vacant in the Bhiwani Sub-Division; and

(b) If so, the time by which the aforesaid posts are likely to be filled up?

मुख्य मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) :

(क) हां श्रीमान्, एक विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(ख) कुछ रिक्तियां अन्य उप-मण्डलों के फालतू स्टाफ में से समजंन करके भरी जाएंगी। बाकी स्टाफ की भर्ती के लिए कार्यवाही यथा समय की जाएगी।

विवरण

कार्यकारी अभियन्ता सिटी मण्डल भिवानी के अधीन 5 परिचालन उप-मण्डल हैं जिनमें से 3 उप-मण्डल जिनके नाम हैं सिटी उप-मण्डल भिवानी, सब-अर्बन नं० 1 भिवानी तथा सब-अर्बन नं०2 उप-मण्डल भिवानी, भिवानी शहर में स्थित है।

सिटी उप-मण्डल भिवानी तथा सब-अर्बन उप-मण्डल नं० 1, भिवानी, भिवानी शहर के शहरी क्षेत्र को बिजली की आपूर्ति करते हैं जबकि सब-अर्बन उप-मण्डल नं० 2 भिवानी सिटी के सीमावर्ती ग्रामीण क्षेत्रों को बिजली की आपूर्ति करता है।

उप-मण्डल अनुसार खाली पदों की स्थिति निम्न प्रकार से है :—

पद	सिटी उप-मण्डल, भिवानी				सब-अर्बन उप-मण्डल नं० 1 भिवानी				सब-अर्बन उप-मण्डल नं० 2 भिवानी			
	एस	डब्लयू	रिक्त	फालतू	एस	डब्लयू	रिक्त	फालतू	एस	डब्लयू	रिक्त	फालतू
एल०एम०	11	23	-	12	12	27	-	15	30	29	1	-
ए०एल०एम०	24	24	-	-	27	35	-	8	71	41	30	-
ए०एफ०एम०	5	6	-	1	5	7	-	2	7	1	6	-
ए०एस०एस०ए०	3	4	-	1	5	11	-	6	-	3	-	3
यू०डी०सी०	4	3	1	-	4	5	-	1	4	2	2	-
एस०डी०ओ०	1	1	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-

'एस' स्वीकृत पद दर्शाता है।

'डब्ल्यू' कार्यरत दर्शाता है।

Cases of Looting, Murder, Arson and Rape in the State

*37. **Dr. Sita Ram :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the district wise number of incidents of looting, murder, arson and rape occurred in the State to-date since the formation of this Government; and

(b) the number of cases in which the offenders have been apprehended together with number of such cases which have not been solved so far ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : (क) व (ख) वांछित सूचना सदन के पटल पर रखी जाती है।

सूचना

(क) राज्य में इस सरकार के गठन से अब तक लूट, हत्या, आगजनी एवं बलात्कार की घटनाओं की जिलावार संख्या।

जिला	लूट	हत्या	आगजनी	बलात्कार
पंचकूला	1	2	0	4
अम्बाला	6	5	1	5
यमुनानगर	2	8	3	5
कुरुक्षेत्र	6	5	2	7
कैथल	1	5	0	4
हिसार	11	5	3	4
सिरसा	8	4	2	5
भिवानी	9	16	3	2
जीन्द	8	9	2	2
फतेहाबाद	2	7	1	2
गुड़गांव	20	21	2	12
फरीदाबाद	8	15	3	12
नारनौल	4	2	1	8
रिवाड़ी	9	11	5	3
रोहतक	15	13	2	3
सोनीपत	7	18	2	4
करनाल	10	17	1	11
पानीपत	14	8	2	18
झज्जर	14	12	3	3
रेलवेज़	5	2	0	0
कुल	**160**	**185**	**38**	**114**

(ख) उन मुकदमों की संख्या जिनमें दोषी पकड़े गए व जो हल नहीं हुए।

जिला	मुकदमे जिनमें अपराधी पकड़े गए				मुकदमे जो हल नहीं हुए			
	लूट	हत्या	आगजनी	बलात्कार	लूट	हत्या	आगजनी	बलात्कार
पंचकूला	0	2	0	4	1	0	0	0
अम्बाला	6	5	0	4	0	0	1	1
यमुनानगर	1	5	3	5	1	3	0	0
कुरुक्षेत्र	5	5	1	6	1	0	1	1
कैथल	1	5	0	4	0	0	0	0

जिला	लूट			हत्या		आगजनी		बलात्कार	
हिसार	9	5	2	4	2	0	1	0	
सिरसा	6	4	0	5	2	0	2	0	
भिवानी	9	11	2	2	0	5	1	0	
जीन्द	3	9	2	2	5	0	0	0	
फतेहाबाद	1	7	1	2	1	0	0	0	
गुड़गावां	12	17	1	7	8	4	1	5	
फरीदाबाद	5	13	3	10	3	2	0	2	
नारनौल	3	2	1	5	1	0	0	3	
रिवाड़ी	9	8	3	3	0	3	2	0	
रोहतक	7	10	1	3	8	3	1	0	
सोनीपत	4	14	0	4	3	4	2	0	
करनाल	5	15	0	11	5	2	1	0	
पानीपत	5	7	0	15	9	1	2	3	
झज्जर	8	9	3	3	6	3	0	0	
रेलवेज	3	1	0	0	2	1	0	0	
कुल	102	154	23	99	58	31	15	15	

Power Generating Capacity of Power Plant Mujeri

*50. **Shri Udai Bhan** : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the power generating capacity of the power plant set up by the NTPC in village Mujeri of district Faridabad;

(b) the total quantum of power being purchased by the Haryana Government; and

(c) whether the Haryana Government has made any correspondence with the Central Government or the management of NTPC for increasing the capacity of the said plant; if so, the details thereof?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) :

(क) जिला फरीदाबाद के मुजेड़ी गांव में एन०टी०पी०सी० द्वारा स्थापित पावर प्लान्ट की बिजली उत्पादन क्षमता 432 मैगावाट है।

(ख) इस प्लान्ट द्वारा उत्पादित शतप्रतिशत बिजली हरियाणा राज्य द्वारा खरीदी तथा प्रयोग में लाई जाती है।

(ग) इस प्लान्ट की निश्चित क्षमता 432 मैगावाट की है। इस परियोजना की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने का प्रस्ताव है। इस मामले को भारत सरकार के साथ लिया जा रहा है।

वर्ष 2005-2006 के बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा

Mr. speaker : Hon'ble Members, Now, discussion on Budget Estimates will start.

डॉ० रघुबीर सिंह कादियान (बेरी) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का समय दिया इसके लिए आपका धन्यवाद।

चौ० धर्मपाल सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। एक बहुत ही आपत्तिजनक बात मैं उठाना चाहता हूं। यह ठीक है कि we can not take any action against him क्योंकि ये आर०एस०एस० के चीफ हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं उनके बारे में सब जानते हैं। उन्होंने एक बहुत ही गलत बयान दिया है कि politics is like prostitution. उन्होंने हमारे डैमोक्रेटिक सैटअप पर अटैक किया है। इससे ज्यादा गलत बात कुछ और नहीं हो सकती है। उन्होंने सारे डैमोक्रेटिक सैटअप पर और हमारे सारे इन्स्टीच्यूशन पर अटैक किया है। मैं यह चाहता था कि यह सब रिकार्ड में आए और इस किस्म की बात जो उनके द्वारा दी गई है वह बहुत ही आपत्तिजनक और चिन्ताजनक बात है । उन द्वारा ऐसी गलत बातें न की जाएं जिससे हमारा सारा ढांचा हिलता हो। यही मेरी आपसे प्रार्थना है।

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। सुबह जब मुख्यमंत्री महोदय शोक प्रस्ताव लेकर आए थे तो उसी विषय में मैंने एक कालिंग अटैंशन मोशन दिया हुआ है। वहां पर जो नुक्सान हुआ था उस बारे में मैंने आपके पास एक कालिंग अटैंशन मोशन दिया है। मैं उस बारे में आपकी रूलिंग चाहता हूं।

Mr. Speaker : You have received the reply. Now I will not allow you.

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस बारे में स्टेटमैंट देने को तैयार है ?

Mr. Speaker : You have received the reply.

उद्योग मन्त्री (श्री लक्ष्मण दास अरोड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इनको बताना चाहूंगा कि सी०एम० साहब खुद वहां पर जाकर आए हैं क्या आज से पहले ऐसा कभी हुआ है ? वहां पर मरने वालों के परिवारों को वित्तीय सहायता भी दी गई है। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Mr. Indora, continuing talking like this is not going to favour you.

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ यही जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस बारे में स्टेटमैंट देने को तैयार है ? (शोर एवं विघ्न)

Mr. Speaker : Everybody to take seat. Discussion on Budget has already taken place. R.S. Kadian, you may continue your speech.

डॉ० रघुबीर सिंह कादियान : स्पीकर साहब, इस महीने की 9 तारीख को वित्तमंत्री श्री बीरेन्द्र सिंह जी ने वर्ष 2005-06 के लिए जो बजट पेश किया उस पर डिस्कशन के लिए सर्वप्रथम मुझे बोलने के लिए समय दिया है इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष

महोदय, मैं सबसे पहले वित्तमंत्री जी का और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को मुबारिकबाद देना चाहता हूं कि उनको इन बजट अनुमानों को तैयार करने के लिए बहुत भारी मशक्कत करनी पड़ी। उन्होंने बजट की अच्छी बातों को और छोटी मोटी कमियों को बहुत ही बोल्डली तरीके से दर्शाया है । स्पीकर सर, मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि पहले जब कभी भी बजट पेश होता था तो डिस्कशन के लिए 12-14 घंटे से ज्यादा का समय नहीं दिया जाता था। उस वक्त हर मैम्बर की रिक्वैस्ट आती थी कि बजट की डिस्कशन पर और समय दिया जाना चाहिए। **(इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए।)** उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी आनरेबल मैम्बर को इतनी महारत हासिल नहीं है कि वह एक दिन में ही बजट पर डिस्कशन में भाग ले सके। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि बजट पर होने वाली डिस्कशन के लिए अध्यक्ष महोदय ने 4 दिन का समय दिया है और इसके लिए अध्यक्ष महोदय बधाई के पात्र हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बजट के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। किसी भी सरकार का बजट उस सरकार का आईना होता है। इस बजट के पढ़ने से यह साफ तौर पर जाहिर होता है कि सरकार एक सही दिशा में काम करने के लिए तत्पर है।

परिवहन मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के नोटिस में लाना चाहता हूं कि हमारा विपक्ष सदन में बजट पर हो रही डिस्कशन के प्रति कितना गम्भीर है क्योंकि बजट पर डिस्कशन के लिए तीन-तीन दिन रखे गए हैं और विपक्ष सदन से अभी से गायब है।

डॉ० रघुबीर सिंह कादियान : उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार इस प्रदेश को ठीक दिशा में ले जाएगी जहां न भय होगा, न भूख होगी, न भ्रष्टाचार होगा, न भेदभाव होगा और पूरा प्रदेश चहुंमुखी विकास की दिशा में आगे बढ़ेगा। डिप्टी स्पीकर सर, किसी बजट की फाउंडेशन या उसकी आधारशिला का उसकी रिसीटस से पता चलता है। वर्ष 2004-05 के बजट में रेवैन्यू रिसीटस 11388 करोड़ रुपये थीं जिनमें अब 649 करोड़ रुपये की और बढ़ोत्तरी हो गयी है और अब ये 12037 करोड़ रुपये तक चली गयी हैं। कैपीटल रिसीटस में भी 1427 करोड़ रुपये की जबदस्त बढ़ोत्तरी हो गयी है क्योंकि वर्ष 2005-06 के लिए 1082 करोड़ रुपये बढ़ाकर 2509 करोड़ रुपये बजट ऐस्टीमेटस में किए गए हैं। जहां तक टोटल रिसीटस का मामला है वर्ष 2004-05 में पिछले वर्ष के बजट में 12470 करोड़ रुपये की टोटल रिसीटस थीं और 2005-06 में इन रिसीटस में 2077 करोड़ रुपये की इंक्रीज हुई है यानी अब यह 14547 करोड़ रुपये तक हो गयी हैं । डिप्टी स्पीकर सर, इस तरह से टोटल पैसा जो आया है उसमें भी रुपी अकाउंट में साफ नजर आ रहा है कि टोटल बजट का 34.04 परसैंट पैसा सेल्ज टैक्स के माध्यम से, रिकवरी के माध्यम से और टैक्स कम्पलायन्स को मजबूत करने के माध्यम से आता हुआ दिखाई दिया है जबकि वर्ष 2004-05 में यह सिर्फ 25 परसैंट था। इसका मतलब पुरानी सरकारों की जो नीयत टैक्स कम्पलायन्स के प्रति थी वह साफ झलकती है। डिप्टी स्पीकर सर, रुपी कम्ज में ही 2004-05 के बजट में 39 परसैंट भरपायी की गयी थी लेकिन इस बार पब्लिक डैब्टस में सिर्फ 24.16 परसैंट जो पैसा है वह आता हुआ दिखाई दिया है। यह साफ दर्शाता है कि सरकार की नीयत इस बजट को कर्जों के माध्यम से पूरा करने की नहीं है बल्कि अपने साधनों से पूरा करने की है। डिप्टी स्पीकर सर, जो मेजर ऐलोकेशंज कंसोलिडेटेड फंडज की हैं उसमें इरीगेशन हैड के अंदर जहां 2004-05 में 749 करोड़ रुपये रिवाइज्ड ऐस्टीमेटस के लिए खर्च हुए वहीं 2005-06 के प्रपोज्ड बजट में 173 करोड़ रुपये और बढ़ाकर 922.68 करोड़ रुपये कर दिए गए। यह 23 परसैंट की बढ़त

[डॉ० रघुबीर सिंह कादियान]

है। पावर सैक्टर की तरफ अगर हम देखते हैं तो वर्ष 2004-05 का जो बजट था उसमें 1487 करोड़ रुपये रिवाइज्ड ऐस्टीमेटस में खर्च हुए जबकि इस बार के बजट ऐस्टीमेटस में 221 करोड़ रुपये बढ़ाकर ये 1708 करोड़ रुपये तक ले गए। इस तरह से पावर सैक्टर में पिछले वर्ष के मुकाबले में 15 प्रतिशत की इंक्रीज है। एजुकेशन में 1847 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2180 करोड़ रुपये किये गये हैं। यह 18 प्रतिशत की बढ़त है। हैल्थ और फैमिली वैलफेयर में 393 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 468 करोड़ रुपये किये गये यानी इसमें 75 करोड़ रुपये पिछले वर्ष के मुकाबले इस साल के प्रपोज्ड बजट में बढ़ाए गए। इस तरह से यह 19 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी है। सोशल वैलफेयर में 609 करोड़ रुपये में 128 करोड़ रुपये की और बढ़त करके 737 करोड़ रुपये बजट ऐस्टीमेटस में रखे गए। यह 21 प्रतिशत की बढ़ोतरी है। ऐग्रीकल्चरल और एलाइड सर्विसेज में 475 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 558 करोड़ रुपये किये गये। यह 18 परसैंट की बढ़त ऐग्रीकल्चर सैक्टर में दिखाई दी जोकि बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसी तरह से पब्लिक वर्क्स डिपार्टमैंट के लिए 2004-05 में 442 करोड़ रुपये रखे गए थे जिसे इस साल 2005-06 में 194 करोड़ रुपये बढ़ाकर 636 करोड़ रुपये कर दिया गया है यह 44 प्रतिशत की इन्क्रीज की गई है। रूरल डिवैल्पमैंट प्रोग्राम में 152 करोड़ रुपये 2004-05 में रखे थे जिसे 125 करोड़ रुपये बढ़ाकर 277 करोड़ रुपये किया गया है यह 82 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी है। यह सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस तरह से सभी हैड्स में कहीं 25 प्रतिशत, कहीं 44 प्रतिशत तो कहीं 82 प्रतिशत की इन्क्रीज है। उपाध्यक्ष महोदय, बजट की वार्षिक योजना का आकार उस प्रदेश के विकास की गति का आईना होता है। बजट अनुमानों से साफ दिखाई दे रहा है कि वार्षिक योजना तैयार करते समय विकास की गति को तेज करने और समाज के सभी वर्गों के उत्थान का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2004-05 की 2236 करोड़ रुपये की वार्षिक योजना के स्थान पर इस वर्ष 3000 करोड़ रुपये की वार्षिक योजना रखी गई है जो कि 34 प्रतिशत अधिक है। इसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। जहां तक वार्षिक योजना में डिफरैंट हैड में एलोकेशन का सवाल है, ऐग्रीकल्चर हैड में 2004-05 में 117 करोड़ रुपया रखा गया था जबकि प्रपोज्ड आउटले में 2005-06 में 30 प्रतिशत पैसा पिछले वर्ष से ज्यादा रखा गया है। रूरल डिवैल्पमैंट के लिए 2004-05 में जहां 100 करोड़ रुपये का रिवाइज्ड आउट ले था उसके मुकाबले वर्ष 2005-06 में 70 करोड़ रुपये की बढ़ोत्तरी करके उसे 170 करोड़ रुपये किया गया है। इरीगेशन और फ्लड कंट्रोल हैड के लिए वर्ष 2004-05 में 298 करोड़ रुपये रखे गये थे जिन्हें इस साल 2005-06 में 65 करोड़ रुपये बढ़ाकर 363 करोड़ रुपये का किया गया है जो कि 32 फीसदी इंक्रीज है। पावर सैक्टर में जहां 380 करोड़ रुपये 2004-05 के रिवाइज्ड आउट ले में रखे गए थे वहीं वर्ष 2005-06 में इसमें 65 करोड़ रुपये की बढ़ोत्तरी करके 445 करोड़ रुपये रखे गए हैं जो कि 16 प्रतिशत ज्यादा है। ट्रांसपोर्ट के हैड में वर्ष 2004-05 में रिवाइज्ड आउटले 251 करोड़ रुपये रखे गए थे लेकिन इस वर्ष 2005-06 में 93 करोड़ रुपये बढ़ाकर 344 करोड़ रुपये इस साल के लिए रखे गए जो कि 37.5 परसैंट की बढ़ोत्तरी है। उपाध्यक्ष महोदय, सोशल सर्विसिज में जनरल ऐजुकेशन, हैल्थ, टैक्नीकल ऐजुकेशन सैक्टर्ज आते हैं। इनमें वर्ष 2004-05 में रिवाइज्ड आउटले 977 करोड़ रुपये खर्च हुआ था जबकि वर्ष 2005-06 में इनमें 375 करोड़ रुपये बढ़ाकर 1352 करोड़ रुपये तक ले गए हैं, यह 38.4 परसैंट की इन्क्रीज है जो कि एक उपलब्धि है। उपाध्यक्ष महोदय, अगर टोटल बजट अनुमानों का मूल्यांकन किया जाए तो आप पाएंगे कि कर्जे से नहीं बल्कि अपने साधनों

से विकास करने की सरकार की नीयत झलकती है। इससे यह दर्शाता है कि हरियाणा की वर्तमान सरकार बुनियादी ढांचे में सुधार करने और संतुलित विकास करने की ओर अग्रसर होगी। हरियाणा सरकार द्वारा लिये गये अहम, फैसले इस बात को सिद्ध करते हैं कि वर्तमान सरकार लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं पर खरा उतरेगी। अपने 100 दिन के टाईम में जिस ढंग से इस सरकार द्वारा फैसले लिये गये हैं उसमें सरकार की उपलब्धियों का एक शीशा नजर आता है पिछले 100 दिनों में वर्तमान सरकार की कुछ मुख्य उपलब्धियां हैं मैं सदन की जानकारी के लिए आपके माध्यम से उनके बारे में बताना चाहता हूं। वैसे तो हर आदमी इन उपलब्धियों के बारे में अखबारों और दूसरे माध्यमों द्वारा जानता ही है। सदन के पटल पर भी ये उपलब्धियां रखी गई हैं। लेकिन जिस ढंग से पिछली सरकार किसानों की हितैषी बनने का ढिंढोरा पीटती थी और जिस ढंग से उसने किसानों के खिलाफ राजद्रोह के मुकदमें दर्ज किये तथा किसानों को बदनाम करने के लिए सरकार की तरफ से निर्णय लिये गये, यह कोई छोटी बात नहीं थी बल्कि यह एक बहुत बड़ी बात है। हमारी सरकार ने किसानों को राहत देने की जो बात की है। यह तो उनके जख्मों पर मरहम लगाने की बात है। हमने उनके जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश की और किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उनके खिलाफ दर्ज सारे मुकदमें प्राथमिकता के तौर पर वापस लेने का फैसला किया। हरियाणा में मुआवजा देने के नाम पर गेहूं की फसल पर 50 रुपये और अन्य फसलों पर 25 रुपये की बढ़ोत्तरी की गई है। गेहूं को 640 रुपये प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य के हिसाब से खरीदा गया है। इसी प्रकार से सरसों को 1700 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है। इस प्रकार से अब सरसों की 2.90 मीट्रिक टन की खरीद की जायेगी जोकि अब तक की सर्वाधिक खरीद होगी। इसी तरह से फसल के लिए लेने वाले सरकारी ऋण पर ब्याज दर कम की गई, ट्रैक्टर की लाईसैंस फीस खत्म कर दी गई है। तथा अब खाद और जिप्सम पर भी कोई कर नहीं लगेगा। दूसरे करों में भी कोई वृद्धि नहीं की गई है। यह अब 12 प्रतिशत रहेगा। ट्रैक्टर के पुर्जों पर कर और भूमि उपकरण के लिए भूमि निर्धारण फार्म बनाया गया है उससे किसानों के एक बड़े वर्ग को फायदा होगा जैसे गुड़गांव में विकास योजना और शहरी किसानों के भूमि अधिग्रहण में 15 लाख रुपये प्रति एकड़ भूमि का भाव निर्धारित किया गया है। एन०सी०आर० और हरियाणा के बड़े शहरों पंचकुला और चण्डीगढ़ में 12.5 लाख रुपये प्रति एकड़ का भाव रखा गया है और अन्य जमीन का 5 लाख रुपये प्रति एकड़ का भाव रखा गया है। कर्मचारियों को उन्नति और तकनीकी जानकारी देने के लिए हरियाणा में पंचकुला में प्रशिक्षण कम्पनी की स्थापना की गई है। नहरी पानी के बटवारे के लिए समान वितरण प्रणाली के तहत नहरी पानी सभी क्षेत्रों में उपलब्ध करवाया जायेगा। इस योजना के अन्दर लिफ्ट कैनाल सिस्टम और भाखड़ा मेन लाईन और हांसी ब्रान्च लिंक नहर का निर्माण करने की एक लिंक नहर योजना विचाराधीन है इस पर लगभग 250 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। इसी प्रकार से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1,2,8 व 10 को जोड़ने के लिए 135 किलोमीटर लम्बा वेस्टर्न पैरीफेरी एक्सप्रैस हाईवे बनाने की प्रक्रिया हरियाणा सरकार ने शुरू की है। इस एक्सप्रैस हाईवे के बनने से हरियाणा प्रदेश का बहुमुखी विकास होगा। दिल्ली मैट्रो को गुड़गांव तक बढ़ाने के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। प्रदेश में औद्योगिक निवेश का माहौल प्रदान करने के लिए नई औद्योगिक नीति लागू की गई है। जिसने एक उद्योग विकास के प्रति रास्ता हरियाणा में खोलने का काम किया है। जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। उपाध्यक्ष महोदय हम किसानों को हर कीमत पर बिजली उपलब्ध करवाने के लिए वचनबद्ध हैं। बिजली निगम धान की फसल लगाने के लिए बिजली के व्यापक प्रबन्ध

[डॉ० रघुबीर सिंह कादियान]

कर रहा है। सामान्य वर्षा की सम्भावना को ध्यान में रखते हुए कृषि क्षेत्र को कम से कम 8 घण्टे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। हरियाणा सरकार की जो पौलिसियां हैं, सरकार ने जो फैसले लिए हैं, सरकार की जो उपलब्धियां हैं वह बहुत अच्छी हैं। अब बिजली के बकाया बिलों की समस्या का समाधान भी निकाला जाएगा। इसका समाधान सुझाने के लिए तथा बिजली क्षेत्र में अतिरिक्त वित्तीय संसाधन तलाशने के लिए वित्त मंत्री की अध्यक्षता में मंत्रियों की 5 सदस्यीय समिति गठित की गई है। उपाध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार अभियान हरियाणा सरकार की तरफ से चलाया गया है जिसमें हरियाणा प्रदेश के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलेगा। परिवहन में यात्रियों की सुविधाओं के लिए बस स्टैंडों का आधुनिकीकरण करना तथा उनमें उपलब्ध जन सुविधाओं में सुधार की ओर विशेष ध्यान दिया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षकों की भर्ती में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण करने का निर्णय भी लिया गया है। इस तरह से शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता को भी चरणबद्ध ढंग से बढ़ाया जाएगा। JBT शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता 10+2 की जगह बी०ए० या बी०एस०सी० कर दी गई है। शिक्षा में श्रेष्ठता के लिए 'राजीव गांधी छात्रवृति' नाम की नई योजना शुरू की गई ताकि प्रतिभावान छात्रों को सरकारी स्कूलों की ओर आकर्षित किया जा सके। इस स्कीम के तहत स्कूलों के 50 हजार प्रतिभाशाली छात्रों को पुरस्कृत किया जाएगा। उपाध्यक्ष महोदय, युवाओं को उच्च कोटि की शिक्षा देने के लिए राज्य में ओक्सफोर्ड यूनीवर्सिटी की पद्धति पर 'राजीव गांधी एजूकेशन सिटी' स्थापित की जाएगी। इसमें हरियाणावासियों के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित होंगी। शैक्षणिक वर्ष 2005-2006 से राजकीय महाविद्यालयों में जोब ओरियंटिड नए पाठ्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, आबकारी नीति को पारदर्शी बनाकर अब ठेकों की नीलामी खुली नीलामी से की गई है। हरियाणा सरकार इस बात के लिए बधाई की पात्र है। इसका परिणाम यह रहा कि ठेकों की नीलामी के इस वर्ष प्रदेश को पिछले साल की तुलना में 120 करोड़ 24 लाख रुपये ज्यादा राजस्व प्राप्त हुआ है। राजस्व में यह वृद्धि 16.75 प्रतिशत है। इसी तरह से व्यापारियों को भी सुविधाएं दी गई हैं। हरियाणा सरकार ने वैट प्रणाली को जनता, व्यापारी वर्ग और उद्योगपतियों के लिए सरल व तर्कसंगत बनाने का प्रयास किया है। जनहित को ध्यान में रखते हुए दवाईयों पर कर की दर 10 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत कर दी गई है। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत बेचा जाने वाला मिट्टी का तेल, एवं तारकोल, कागज, खेलों का सामान, लैण्ड लाइन टेलीफोन, सिलाई मशीन और पत्थर की खुरदरी स्लैब पर पहले जो कर 10 से 12 प्रतिशत था, उसे घटाकर 4 प्रतिशत कर दिया गया है। हलवाईयों से लिया जाने वाला एकमुश्त भट्ठी कर भी समाप्त कर दिया गया है। इस प्रकार से अब जिन हलवाईयों की वार्षिक आय 5 लाख से कम है, उनसे कोई कर नहीं लिया जाएगा। इस तरह से उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार ने समाज कल्याण की तरफ भी एक साहसी कदम उठाया है इससे सरकार की हमदर्दी कमजोर वर्गों की तरफ दिखाई देती है। दृष्टिहीन विकलांग व्यक्ति जो केनर के पद पर कार्य कर रहे हैं, उन्हें दी जाने वाली राशि 1500 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये मासिक कर दी गई है। दृष्टिहीन मानसिक रूप से विकलांग और बधिर विकलांगों और शारीरिक रूप से विकलांगों को दी जाने वाली मासिक पैंशन 300 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये कर दी गई है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जातियों के परिवारों की लड़कियों के विवाह पर दी जाने वाली राशि 5100 रुपये की बजाय 15000 रुपये देने की एक योजना शुरू की गई है। जिसे 'इन्दिरा गांधी प्रियदर्शनी

विवाह शगुन' योजना कहा जाएगा। उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार प्रदेश में घटते लिंग अनुपात के प्रति भी चिन्तित है और इसके लिए भी बहुत सी स्कीमें हरियाणा सरकार ने बनाई हैं। हमारे मुख्यमंत्री महोदय भी खुद एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हैं इसलिए स्वतंत्रता सेनानियों और सैनिकों को सुविधा देने के लिए सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों की पैंशन 1400 रुपये से बढ़ाकर 3500 रुपये प्रति माह कर दी है। सैनिकों व भूतपूर्व सैनिकों द्वारा CSD से खरीदी जाने वाली वस्तुओं को कर से मुक्त रखा गया है। भूतपूर्व सैनिकों को आबकारी कर में 25 प्रतिशत की छूट दी गई है। उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार ने अर्ध सैनिक बलों के सभी रैंको को सेना के रैंकों के बराबर अनुग्रह अनुदान देने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त कर्मधारियों को भी बहुत सी सविधाएं दी हैं। हमारी सरकार ने कर्मचारियों को अपनी लड़की और बहन की शादी के लिए मिलने वाले 30,000 रुपये के लोन को बढ़ाकर एक लाख रुपये तक किया है और लड़के की शादी के लिए मिलने वाले 20 हजार रुपये के लोन को बढ़ाकर 60 हजार रुपये किया है। यह सुविधा अब तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के साथ-साथ द्वितीय श्रेणी के कर्मचारी भी ले सकेंगे। इसका भुगतान अब 70 किस्तों की बजाय 100 मासिक किस्तों में होगा। हमारी सरकार ने कर्मचारियों की भलाई के लिए चिकित्सा खर्च प्रतिपूर्ति की एक अनूठी योजना भी लागू की है। इसके अलावा 1 अप्रैल, 2005 से आंगनवाड़ी के कार्यकर्ताओं का मानदेय 200 रुपये और आंगनवाड़ी हैल्परों का मानदेय 100 रुपये प्रति मास बढ़ाया है। उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह हरियाणा सरकार की वार्षिक योजना और नीतियां यह दर्शाती हैं कि हरियाणा की वर्तमान सरकार बुनियादी ढांचे को सुधारने के साथ-साथ स्वच्छ और कल्याणकारी शासन की तरफ अग्रसर है। उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार द्वारा लागू अहम फैसले इस बात को सिद्ध करते हैं कि वर्तमान सरकार लोगों की आशाओं और आंकाक्षाओं पर खरी उतरेगी। उपाध्यक्ष महोदय, वर्तमान सरकार का यह पहला बजट है इसलिए पिछली सरकार की वार्षिक योजनाओं का यहां जिक्र करना मैं जरूरी समझता हूं। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, मेरी दिली इच्छा थी कि अगर आज हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और रोड़ी हल्के के विधायक भी इस अवसर पर सदन में उपस्थित रहते तो वे स्वयं महसूस करते कि वे अपने आपको किस आधार पर किसान का बेटा होने का दावा करते थे और अपने को किस आधार पर किसान हितैषी कहते थे ? क्योंकि उनकी सरकार के समय में जन विरोधी और किसान की कमर तोड़ने वाली वार्षिक योजनाएं तैयार की गई थीं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वे उनको अतिशीघ्र स्वास्थ्य लाभ देकर लम्बी उम्र दें ताकि वे खुद देख सकें कि सही मायने में किसान हितैषी कौन है ? उपाध्यक्ष महोदय, उनकी पांच साल तक सरकार रही, मैं उनकी सरकार के समय की पांच साल की वार्षिक योजनाओं का जिक्र करूंगा। क्योंकि हमारी सरकार का यह पहला बजट है। इसलिए उनकी सरकार के समय की वार्षिक योजनाओं का जिक्र करना बहुत जरूरी है। हमें पिछली सरकार से जो व्यवस्था मिली है, जो ढांचा मिला है उसकी जानकारी उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को देना चाहूंगा। **(इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए)** अध्यक्ष महोदय, 2000-01 में वार्षिक योजना का आकार 1815 करोड़ रुपये था लेकिन 2001-02 में 1.5 प्रतिशत बढ़ाकर 1838 करोड़ रुपये पिछली सरकार ने किया। उसके बाद 2002-03 में वार्षिक योजना का आकार 2.1 प्रतिशत कम करके 1800 करोड़ रुपये रखा गया। अध्यक्ष महोदय, वार्षिक योजना का आकार इससे पहले हमारे देश में किसी भी राज्य में नहीं घटाया गया। लेकिन पिछली सरकार के समय हमारे राज्य में यह कम किया गया। उसके बाद 2003-04 में 2.7 प्रतिशत बढ़ौत्तरी करके वार्षिक योजना का आकार 1850 करोड़ रुपये रखा गया और 2004-05

[डॉ० रघुबीर सिंह कादियान]

में 20.8 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी करके यह 2236 करोड़ रुपये रखा गया। अध्यक्ष महोदय, यदि पिछले पांच साल की वार्षिक योजनाओं का टोटल इन्क्रीज देखा जाये तो यह कुल 23.3 प्रतिशत ही है जबकि वर्तमान सरकार की वर्ष 2005-06 की वार्षिक योजना की एस्टीमेटिड इन्क्रीज ही 34 प्रतिशत है जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए हरियाणा सरकार और वित्तमंत्री चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी बधाई के पात्र हैं। स्पीकर सर, समय के साथ-साथ प्रदेश में पोपुलेशन भी बढ़ती रही है, इन्फलेशन भी बढ़ता रहा है और कीमतें भी घटती बढ़ती रही हैं। अगर इस फैक्टर को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2004-05 की वार्षिक योजना को देखा जाए तो यह 2236 करोड़ रुपये की थी और यदि उसकी एक्चुअल वैल्यू वर्ष 2000-2001 की वार्षिक योजना के 1815 करोड़ रुपये के मुकाबले में आंकी जाए तो वर्ष 2004-05 की वार्षिक योजना भी बढ़ी हुई नहीं है बल्कि घटी हुई ही नजर आएगी। स्पीकर सर, पिछली सरकार अपने पांच साल के कार्यकाल के दौरान वार्षिक योजना के आकार को बढ़ा नहीं पाई जबकि कर्ज का बोझ 12 हजार करोड़ से 28 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच गया, रेवैन्यू एक्सपैंडिचर आठ हजार करोड़ रुपये से 13 हजार करोड़ रुपये हो गया, फिस्कल डैफिशिट कण्ट्रोल से बाहर चला गया; Debt of the State on an average has increased faster than the rate of GDP. Total outstanding arrear of revenue बढ़ता चला गया, टैक्स की कम्पलायंस सैटिस्फैक्टरी नहीं हुई, पिछली सरकार ने सारा टैक्स एकत्रित करने की बजाए अपने समर्थकों के माध्यम से अपनी जेबें भरने का काम किया गया।

Mr. Speaker : Dr. Sahib, Please wind up.

डा० रघुवीर सिंह कादियान : स्पीकर सर, यह पिछले पांच साल के फाईनैंस का ऐनालिसिज हरियाणा प्रदेश के लिए काले अध्याय के समान है। उस समय प्रदेश में चारों तरफ हाहाकार मची हुई थी। प्रदेश में गलत कामों का बोलबाला था। अपहरण, डकैती और बलात्कार का बोलबाला था, भेदभाव की राजनीति से पूरा प्रदेश ग्रसित था और उस समय की सरकार की दमनकारी नीतियों की वजह से हरियाणा प्रदेश का हर नागरिक भय के वातावरण में जीने के लिए मजबूर था वहीं दूसरी तरफ अपनी सस्ती लोकप्रियता के लिए पूरे प्रदेश में वॉल राईटिंग, कट-आउट्स और रोड़ होर्डिंग्ज लगा कर सरकारी खजाने का करोड़ों रुपया बर्बाद करने का काम हुआ था स्पीकर साहब, अगर मैं चौटाला साहब के पांच वर्षों के सारे कारनामों की चर्चा करूं तो शायद किसी और माननीय साथी को बोलने का अवसर नहीं मिलेगा। मेहम काण्ड बहुत ही चर्चित काण्ड था। मैं इस बात को इस लिए कह रहा हूं क्योंकि चौटाला साहब ने चंगेज खां के अन्दाज में सद्दाम हुसैन के नजरिये से हरियाणा प्रदेश के साथ खिलवाड़ किया। मेहम काण्ड के दौरान चौटाला साहब के जुमले आज भी लोगों के होठों पर कायम हैं। चौटाला साहब कहा करते थे, 'मैं तो भगवान से भी नहीं डरता', 'शमशान तक दोस्ती निभाता हूं'। चौटाला साहब यह बात बड़े गर्व से कहते थे कि 'उस इन्सान का क्या जीना जिसके भय से डर कर लोग नींद से न उठ जाएं', जिसके भय से डर कर चारपाई पर न उछलने लगें। (विघ्न) उन दिनों वे इस प्रकार की बातें आम कहा करते थे। स्पीकर सर, मेहम काण्ड के प्वांयट को मैं दर्ज करना चाहता हूं। उस चुनाव में आजाद उम्मीदवार अमीर सिंह की हत्या की गई। उसकी जांच के लिए केन्द्र सरकार द्वारा गठित न्यायमूर्ति के०एन० सैकिया आयोग की जांच रिपोर्ट का मैं जिक्र करना चाहूंगा। उन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट में लिखा है कि needle of suspicion, points towards men and circumstances around Chief Minister Shri Om Parkash Chautala.

अध्यक्ष महोदय, ओम प्रकाश चौटाला के शासनकाल में जिस तरह से निर्दोष और शान्तिप्रिय लोगों पर गोलियों की बौछार हुई थी मैं उसका जिक्र करना चाहूंगा 30 जनवरी, 2002 में छोटी-मोटी बातों को लेकर किसानों और सरकार के बीच समझौता हुआ था और उस समझौते को लागू करवाने के लिए 19 मई, 2002 को कण्डेला में एक पंचायत बुलाई गई थी। उस पंचायत में जब कैथल की तरफ से किसान शिरकत करने के लिए आ रहे थे तो शिमला गांव के किसान राम सरूप की नगूरा गांव के अन्दर गोली मार कर हत्या कर दी गई। स्पीकर सर, उसकी पोस्ट मार्टम रिपोर्ट को बदला गया और जब पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट बदली गई तो आन्दोलन की लपटें गुलकनी और शाहपुर गावों तक चली गई। 29 मई को एक किसान राजबीर की हत्या हुई और 31 मई को फिर 6 किसानों को मौत के घाट उतार दिया गया। स्पीकर सर, उस समय जिस ढंग का वातावरण था मैं उसको ब्यान कर रहा हूं। आज सब लोग यह अन्दाजा लगाएं कि धरती आसमान मिलते हैं जब एक बूढ़े बाप के बेटे की लाश उसके घर से निकलती है या जब एक जवान बहन जिसने अपने खान्विद के शरीर को भी नहीं देखा था, उसके खान्विद की लाश उसके आंगन से उठी थी। स्पीकर सर, 6 किसानों की मौत हुई। कहीं उनकी पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट न बदल जाए इसलिए लोग उन शवों को पोस्ट मार्टम के लिए मैडिकल कॉलेज, रोहतक ले गए थे। स्पीकर सर, भूपेन्द्र सिंह हुड्डा को उनका टेलीफोन गया। जब हम लोग वहां पर पहुंचे तो बहुत दर्दनाक और मार्मिक सीन वहां पर था। सैकड़ों किसान वहां पर खड़े थे। 80-80 साल के बूढ़े लोगों की सफेद मूंछों में से आंसू जा रहे थे । जब भूपेन्द्र सिंह जी अपने साथियों के साथ वहां पर जा कर गाड़ी से उतरे तो गुलकणी और शाहपुर गांवों के सरपंच रामदीया और टेकराम ने हुड्डा साहब को जफ्फी में भर लिया और छौली में लेकर दहाड़ मार कर रोने लगे और कहने लगे कि लूट लिया ओम प्रकाश चौटाला ने । स्पीकर सर, 6 किसानों की लाशों पर कफन ढके हुए थे। उस समय हरियाणा प्रदेश की कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने कहा था कि ऐ किसान मैं तेरी लड़ाई लड़ूंगा, चौटाला की फैक्टरी में कोई ऐसी गोली नहीं बनी है जो किसान की छाती में लगेगी, अगर कोई गोली बनी है तो वह गोली भूपेन्द्र सिंह हुड्डा और उनके साथियों की छाती में लगेगी। स्पीकर सर, उसके बाद एक आन्दोलन शुरू हुआ। चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी और चौधरी जय प्रकाश जी वहां पर आए थे। स्पीकर सर, वहां पर आनन्द सिंह डांगी और शादी लाल बत्रा भी थे। इन्होंने जींद में पहुंचकर आन्दोलन शुरू किया तथा शहीद हुए किसानों के आश्रितों को कांग्रेस पार्टी की तरफ से 1-1 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई। उसके बाद भी जब चौटाला की जालिम सरकार नहीं झुकी तो 9 जून से 21 जून तक चिलचिलाती धूप में दिल्ली तक की पद यात्रा करने का फैसला लिया गया। जब पद यात्रा चरम सीमा पर थी तो 19 जून को सरकार समर्थकों के बीच में एक समझौता हुआ ताकि 21 जून की रैली में लोग दिल्ली न पहुंचें। स्पीकर सर, कितनी खेदजनक बात है कि उस समय एक आला आफिसर जेलों में बंद भारतीय किसान यूनियन के नेताओं को निकाल कर दिल्ली में चौटाला की कोठी पर ले गया और उन पर समझौता करने के लिए दबाव डाला गया लेकिन उन नेताओं ने अपनी पार्टी के साथियों से सलाह मशविरा किए बिना हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। तब सरकार द्वारा कुछ और सरकार समर्थक किसानों से समझौता करवाया गया। इस समझौते का मीडिया के माध्यम से काफी प्रचार किया गया था, यह इसलिए किया गया था कि दिल्ली के राम लीला ग्राउन्ड में 21 तारीख को होने वाली रैली में लोग न पहुंचे। लेकिन इसके बावजूद भी लाखों लोगो वहां पर पहुंचे और हरियाणा सरकार की चूलें हिलाकर रख दी। पूरे उत्तरी भारत का किसान वाजपेयी और बी०जे०पी० के खिलाफ हो गया क्यों कि वह किसानों पर गोलियां चलाने वाले ओम प्रकाश चौटाला का समर्थन कर रहे थे।

श्री अध्यक्ष : डा० साहब, अब आप वाईंड आप करें।

डा० रघुबीर सिंह कादियान : स्पीकर सर, इसी वजह से चौटाला को एक लायबिलिटी समझकर लोकसभा के चुनावों में बी०जे०पी० ने चौटाला पार्टी से कोई समझौता नहीं किया। स्पीकर सर, मैं थोड़ी सी चर्चा कानून व्यवस्था पर भी करना चाहूंगा। चौटाला के समय हरियाणा में जंगल राज था। आए दिन हत्याएं, चोरियां, राजनैतिक अपहरण, बलात्कार और डकैतियां होती थीं। सबसे खेदजनक बात यह थी कि राजनैतिक संरक्षण प्राप्त कैदी जेलों में मोबाईल फोन से लोगों से फिरौती वसूलते थे। पुलिस अधीक्षक से लेकर के पुलिस महानिदेशक सभी आफिसर्ज चौटाला की बेतुकी हाजिरी भरते थे। चौटाला के बेटों को पायलट और एस्कार्ट गाड़ियां दी जाती थीं, उनके लिए स्पैशल अल्फा कोड तय कर रखा था, उनके लिए रूट लगते थे। स्पीकर सर, एक खेदजनक बात मैं आपके माध्यम से सदन में रखना चाहता हूं। स्पीकर सर, सांपला गढ़ी गांव सांपला के नजदीक चौधरी छोटूराम का गांव है। जिस महान शखसियत ने किसानों की महफूजी के लिए अपना सारा जीवन लगा दिया था उसके गांव से जब एक महिला अपने गुम पति को तलाश करने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री के पास फरियाद करने के लिए पहुंची तो स्पीकर सर, बैरिगेट के अन्दर उस समय कई महिलाएं घुस गईं। उस समय उस औरत को पुलिस अधीक्षक ने धक्का मारा जिसके कारण उसका दूध मुआं बच्चा जो कि उसकी गोद में था, हरियाणा के मुख्यमंत्री की गाड़ी के बोनट पर जाकर गिरा। स्पीकर सर, तपतपाते हुए बोनट पर वह बच्चा जब चिल्लाया तो सबसे दुःखद बात यह हुई कि उस समय के हरियाणा के मुख्यमंत्री, नादिरशाह नजरिए के मुख्यमंत्री उस सारे सीन का लुत्फ उठा रहे थे। उस आदमी ने एक बार यह नहीं कहा कि यह औरत क्या कहना चाहती है। स्पीकर सर, इससे दुखदायी बात और क्या हो सकती है ? स्पीकर सर, चौटाला के शासन में न्याय के मन्दिर की अदालतें भी सुरक्षित नहीं थी। जींद, झज्जर, रोहतक, पानीपत और गुड़गांव की अदालतों में गोलीकांड चौटाला के कार्यकाल में हुए थे। स्पीकर सर, हमारा सिर झुक जाता था जब हम यह देखते थे कि चार-चार बार विधायक बने स्वर्गीय चौधरी देवी लाल के साथी रहे इनैलो नेता चौटाला के बेटों के सभारोह में सड़कों पर फूल मालाएं लेकर घंटों-घंटों इन्तजार करते थे। स्पीकर सर, मैं भेदभाव की कहानी भी आपके सामने रखना चाहता हूं। चाहे वह नौकरियों की बात थी, चाहे विकास के पैसे के बंटवारे की बात थी। चाहे पानी की बात थी, पूरे प्रदेश के साथ एक बहुत बड़ा भेदभाव हुआ खासकर विपक्ष के विधायकों के साथ तो बहुत बड़ा डिसक्रिमीनेशन हुआ। स्पीकर सर, बजट का 70 फीसदी हमेशा एक खास इलाके में जाता था, 70 फीसदी नौकरिया एक खास इलाके में जाती थीं, 70 फीसदी बिजली की सप्लाई एक खास इलाके में जाती थी और हरियाणा प्रदेश की नदियों के टोटल पानी का 70 फीसदी एक खास इलाके में चल रहा था। अध्यक्ष महोदय, पिछली विधान सभा की अवधि में 11 सत्र हुए। उनमें हमने एडजर्नमैंट मोशन के माध्यम से जब यह कहा कि पानी के बंटवारे पर सदन में चर्चा होनी चाहिए क्योंकि एस०वाई०एल० तो जब खुदेगी तब खुदेगी लेकिन कम से कम जो इस समय प्रदेश में पानी है, उसका तो सही बंटवारा होना चाहिए लेकिन अध्यक्ष महोदय, हमारे ये सारे एडजर्नमैंट मोशंज उस समय बिना किसी रीजन के रिजैक्ट कर दिए गए। इन सारी बातों को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता इक्ट्ठे हुए और उन्होंने इस बारे में एक संघर्ष करने की बात अपने दिमाग में रखी तथा इस बारे में मीटिंग्ज बुलायी। उसके बाद हरियाणा कांग्रेस पार्टी के उस समय के अध्यक्ष श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में 'जल युद्ध' के नाम से झज्जर के अंदर पहली बार एक बहुत बड़ी रैली रखी गयी । स्पीकर सर, इस रैली के डर से कि कहीं इस इलाके के स्वाभिमानी किसान, इस इलाके का मेहनतकश किसान

इस भेदभाव के प्रति ये सारी बातें न जान लें और तेरी असलियत न पता लग जाए, उन्होंने तीस किलोमीटर दूर रोहतक में प्रदेश स्तर की सरकारी रैली रखी और झज्जर की हमारी रैली को फेल करने के लिए सरकारी बाधाएं डाली गईं, दबाव डाले गये लेकिन मैं मुबारिकवाद देता हूं उस इलाके की हरियाणा प्रदेश की मेहनतकश जनता को कि रोहतक की रैली के मुकाबले में दो या तीन गुना लाखों लोग उस रैली में इकट्ठे हुए।

श्री अध्यक्ष : कादियान साहब, अब आप वाइंड अप करें।

श्री रघुबीर सिंह कादियान : स्पीकर सर, इस बात को लेकर जब किसान आर-पार की लड़ाई लड़ने के लिए खड़ा हो गया और जब किसान ने यह साबित कर दिया कि भूपेन्द्र सिंह हुड्डा बिना ताज के मुख्यमंत्री हैं तो चौटाला डर गया। स्पीकर सर, भ्रष्टाचार पर अगर कोई किताब लिखना चाहे तो ग्रंथ के ग्रंथ लिखे जा सकते हैं। उस समय गुड़गांव और फरीदाबाद में बिल्डरों से बिल्डिंग्ज और शापिंग माल्ज के नक्शे पास करने के लिए पैसे लिए जाते थे। संवैधानिक सत्ता के केन्द्र हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का जनाजा निकाल दिया गया था। दुःख की बात है कि एच०पी०एस०सी० के मैम्बरान सरकारी गाड़ी में खुद आनसरशीट्स लेकर चैक करवाने के लिए जाते थे। एस०एस०एस० बोर्ड में हुई धांधली का जिक्र करने की जरूरत नहीं है। स्पीकर सर, उस समय थाने और तहसील भी बिकते थे। एन०ओ०सी० और सी०एल०यू० के नाम से बड़ा भारी चढ़ावा चढ़ता था। छोटे बड़े उद्योगपतियों से चाहे वह राईस सैलर्ज हो या चाहे पैट्रोल पम्प डीलर्ज ऐसोशिएशन हो या चाहे कोई भट्ठा ऐसोसिएशन हो, सबसे जजिया वसूला जाता था। स्पीकर सर, जिस ढंग से भूमाफिया को ओने पौने दामों में सड़कों के ठेके, शराब के ठेके, खानों के ठेके दिये जाते थे वह बड़े दुःख की बात थी। स्पीकर सर, मैं अर्ज करना चाहूंगा कि चन्दा इकट्ठा करने के लिए मशहूर चौटाला ने फिजी के अपदस्थ प्रधानमंत्री महेन्द्र चौधरी की मदद करने के नाम पर हरियाणा से करोड़ो रुपये का चंदा इकट्ठा करने का काम किया। स्पीकर सर, जो विकास के लिए राशि दी जाती थी, उसका दस फीसदी अफसरों के माध्यम से वह स्वयं उगाता था। चौटाला साहब दांत घिसाई के नाम से भी पैसा वसूलते थे उस समय लाखों रुपया चाय वगैरह पर खर्च किया जाता था। दक्षिणा के रूप में भी पैसा लिया जाता था। स्पीकर सर, कारगिल की लड़ाई के योद्धाओं के कहीं कोई बुत नहीं बने, कोई यादगार उनकी नहीं बनी। भगत सिंह चन्द्रशेखर, महात्मा गांधी, सुभाष चन्द्र बोस और जवाहर लाल नेहरु सरीखे नेताओं के बुत नहीं लगाये गये लेकिन हरियाणा ही नहीं बल्कि दिल्ली और चण्डीगढ़ में भी स्वर्गीय चौधरी देवीलाल के नाम से ट्रस्ट बनाकर अरबों-खरबों रुपयों की सम्पत्ति छीनने का काम हुआ। स्पीकर सर, हर महीने में एक हजार करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार का कारोबार होता था। इसका 80 फीसदी बाप बेटों में जाता था और बीस फीसदी चेहते अधिकारियों और उनके समर्थकों में जाता था। इसका नतीजा क्या हुआ ? इसका नतीजा यह हुआ कि कभी बीड़ी उधार मांगने वाला व्यक्ति, कभी मैक्सी कैब में किराया न देने वाला व्यक्ति, रिक्शा वाले से चार आने और दवन्नी की लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति अरबों-खरबों रुपयों की सम्पत्ति का मालिक बन गया।

श्री अध्यक्ष : कादियान साहब, अब आप वाईंड अप करें।

श्री रघुबीर सिंह कादियान : स्पीकर सर, उसकी सम्पत्ति हरियाणा में ही नहीं बल्कि दिल्ली-चण्डीगढ़ से होती हुई आस्ट्रेलिया, कनाडा और अमरीका तक पहुंच गयी। इन देशों तक उसकी सम्पत्ति का विस्तार हो गया। यह बहुत बड़े दुख की बात है। उन्होंने दलितों और पत्रकारों को भी नहीं बख्शा। दुलीना और बरसौला में दलितों पर जुल्म हुआ। मीडिया प्रजातंत्र का चौथा

[डॉ० रघुबीर सिंह कादियान]

स्तंभ है। सिरसा के पत्रकार छत्रपति और कैथल के पत्रकार परमानंद गोयल की हत्या की गई जो कि चौटाला के माथे पर इतना बड़ा कलंक है जिसे गंगा का सारा पानी भी नहीं धो सकता। रोहतक में पत्रकारों पर झूठे मुकदमें बनाए गए। शर्म की बात है कि जेल में बंद खतरनाक अपराधियों के आगे दुम हिलाने वाले एक पुलिस अफसर के आदेश पर एक पत्रकार को रोहतक शहर की नाकेबंदी करके रात के दो बजे गिरफ्तार किया गया। मैं मीडिया के साथियों को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने तमाम ज्यादतियों के बावजूद भी निर्भीकता से अपनी कलम चलाए रखी। हमारी सरकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का पूरा सम्मान करती है।

श्री अध्यक्ष : डा० साहब, अब आप वाइंड अप करें।

डॉ० रघुबीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, मैं कारगिल की लड़ाई में हरियाणा के हजारों बहादुर जवानों के बलिदान का जिक्र करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, हमें गर्व है कि हमारे जवानों ने अपनी नवविवाहिता दुल्हनों और बूढ़े मां-बाप की चिंता छोड़कर कारगिल की बर्फीली पहाड़ियों पर देश की सीमा की रक्षा हेतु सीने पर गोलियां खाई लेकिन चौटाला सरकार ने उनके बलिदान को यादगार बनाने की बजाए हरियाणा ही नहीं बल्कि दिल्ली और चंडीगढ़ में भी स्वर्गीय चौधरी देवीलाल के नाम से ट्रस्ट बनाकर अरबों रुपये की सम्पत्ति इक्ट्ठी की गई है।

Mr. Speaker : Dr. Sahib, please wind up. (Interruptions) I have got the responsibility. I know the Chief Minister is also sitting. (Interruptions) Why did't you realize at that time ?

डॉ० रघुबीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, ओम प्रकाश चौटाला ने उस समय तो सामाजिक मूल्यों में गिरावट की सारी सीमाएं तोड़ ही दी जब उन्होंने सदन के नेता भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के विधान सभा क्षेत्र किलोई में तब जलसा किया जब हुड्डा साहब हरिद्वार के पास पीली नदी के हादसे से बचकर दिल्ली के राममनोहर लोहिया अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे। तब चौटाला ने किलोई हल्के को डैड हल्का कहकर यह कहा कि हुड्डा कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। यह अलग बात है कि किलोई की स्वाभिमानी जनता ने उप चुनाव में चौटाला के उम्मीदवार की जमानत जब्त करवा दी और उसे मात्र तीन हजार वोट ही हासिल हुए। यहां मैं किलोई के साथ-साथ तोशाम और हिसार विधान सभा सीटों के उप चुनाव जो कि स्व० सुरेन्द्र सिंह और स्व० ओ०पी० जिंदल के एक विमान हादसे में हुए दुखदाई निधन से हुए थे, का जिक्र करना चाहूंगा। हरियाणा के इतिहास में पहली बार इन उप चुनावों में सरकारी मशीनरी का प्रयोग नहीं हुआ। हुड्डा साहब ने तो पूरे उप चुनाव के दौरान अपने चुनाव क्षेत्र में नहीं जाकर एक अनुकरणीय मिसाल कायम की। न ही वहां किसी तरह के माइक थे, न धूतू थे, न पोस्टर थे, न बैनर थे, न कुछ और था। लोगों ने भी अपने प्रेम और स्नेह को दर्शाते हुए उन्हें 1 लाख 3 हजार 635 वोट दिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी की जींद में हुई रैली जिसमें कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी ने प्रदेश की जनता का कांग्रेस को भारी बहुमत से सत्ता में लाने के लिए धन्यवाद किया था, का जिक्र करना चाहूंगा। उन्होंने जींद रैली में कहा कि हरियाणा के विकास के लिए केन्द्र सरकार अपने खजाने की थैलियों का मुंह खोल देगी। श्रीमती सोनिया गांधी ने हरियाणा सरकार द्वारा थोड़े ही समय में प्रदेश की जनता की भलाई के लिए उठाए गए कदमों की सराहना की। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के पास होने के नाते अच्छा प्रशासन देने के मामलों में

हरियाणा दूसरे राज्यों को मार्ग दिखायेगा। मैं सदन के माध्यम से प्रदेश की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री उनकी इच्छा को पूरी करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। अध्यक्ष महोदय, ओम प्रकाश चौटाला ने सदन की मर्यादाओं को तहस नहस करने का भी काम किया था। लोकतंत्र में विपक्ष की प्रभावी भूमिका होती है लेकिन चौटाला ने विपक्ष को अपनी यह जिम्मेदारी भी नहीं निभाने दी। विपक्ष ने जब भी ऐडजर्नमैंट मोशंज दिए, काल अटैंशन मोशंज दिये और उनके माध्यम से जनता पर हुई ज्यादतियों के मामले उठाने चाहे तो उनके प्रस्तावों को बगैर कारण बताएं खारिज कर दिया जाता था, बगैर किसी वजह के मैम्बर्ज को नेम कर दिया जाता था और जब कोई मैम्बर बोलने की कोशिश करता तो बगैर कोई रीजन बताए पूरे सैशन के लिए हाउस से निकाले जाने की प्रथायें भी डाली गयी थीं

श्री अध्यक्ष : डा० साहब, अब आप वाइंड अप करें।

डॉ० रघुबीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, ओम प्रकाश चौटाला के पांच वर्ष के शासन की कार्य प्रणाली पर राजनीति शास्त्र के छात्रों की शोध करने का बहुत बड़ा विषय मिल सकता है, इस पर थीसिज लिखी जा सकती है। किलोई के उप चुनाव में न कोई बैनर थे न पोस्टर थे न कटाउट थे, न कोई झंडे थे, न होर्डिंग थे, न कोई किसी तरह के माइक थे, न चंदा था, न चुटकी थी और न कैंडीडेट वहां गए। वहां की जनता बधाई की पात्र है कि उन्होंने भूपेन्द्र सिंह जी हुड्डा को इतने भारी बहुमत से चुनकर भेजा। पहले जब कोई चुनाव होता था तो तीन दिन पहले जीप पकड़ी जाती थीं।

Mr. Speaker : Dr. Sahib, please wind up now.

डॉ० रघुबीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, बेरी हल्के की पिछले पांच सालों की बहुत सारी समस्याएं हैं उनकी लिस्ट मैं आपको दे दूंगा। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार को गली सड़ी व्यवस्था विरास्त में मिली है जिसे सुधारने में समय लगेगा। भगवान श्री कृष्ण ने इस धरती पर गीता का उपदेश दिया था। हरियाणा प्रदेश जहां दूध दही की नदियां बहती थी वहां शराब माफिया, खान माफिया, भू माफिया, ट्रांसपोर्ट माफिया पैदा किये गये राजनेता और पुलिस अपराधियों से मिलीभगत देखने को मिली और एक ऐसा ताकतवर माफिया पनपा जिसने अपने धन और बाहुबल के दम पर प्रदेश की मेहनती, ईमानदार और स्वभिमानी जनता का जीना दूभर कर दिया।

Mr. Speaker : Thank you, Dr. Sahib, please take your seat. Thank you very much.

डॉ० रघुबीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार सभी माफियाओं को उखाड़ फैंक कर जनता को भ्रष्टाचार रहित, भयमुक्त, भूख मुक्त और एक पारदर्शी प्रशासन देने के लिए वचनबद्ध यह एक यज्ञ है जिसकी सफलता के लिए सरकार तो हर संभव प्रयास कर रही है और करती रहेगी। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा हरियाणा प्रदेश की बहादुर जनता, को नौजवानों को, मजदूरों को, व्यापारियों को, उद्योग पतियों को, कर्मचारियों को और सभी विपक्ष के साथियों को कि वे इस यज्ञ में अपनी-अपनी आहुति दें तभी हमारे प्रदेश का चहुमुखी विकास संभव होगा। इसमें हम सबकी जिम्मेवारी भी है और नैतिकता भी है। हरियाणा विकास और जवाबदेह प्रशासन के मामले में देश के दूसरे राज्यों के लिए पथ-प्रदर्शन का काम करेगा।

Mr. Speaker : Thank you, Dr. Sahib, please take your seat.

डॉ० रघुबीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय मैं वित्त चौधरी बीरेन्द्र सिंह को और हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा को एक बिजनरी बजट पेश करने के लिए मुबारकबाद देना चाहता हूं। वे एक अरमान को लेकर चले हैं। एक विश्वास हरियाणा की जनता में जगा है और उसे ऐसा लग रहा है कि यह सरकार 20-25 साल तक चलेगी।

Mr. Speaker : Dr. Sahib, please take your seat.

डॉ० रघुबीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

Mr. Speaker: Thank you very much, Kadian ji. Now, I call upon Mr. Sushil Kumar Indora.

डॉ० सुशील इन्दौरा (ऐलनाबाद, एस०सी०) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं। और शुक्र गुजार हूं कि आपने मुझे इस बजट पर चर्चा में भाग लेने के लिए समय दिया। यह इस सरकार का पहला बजट है और मैं भी पहली बार इस चर्चा में हिस्सा ले रहा हूं। इसलिए मैं पिछली सरकार के बजट को ध्यान में रखते हुए सदन में अपनी बात रखना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, पूरे बहुमत से साथ कांग्रेस पार्टी ने पिछले चुनाव में जीत कर सरकार बनाई। लोगों ने इन में इसलिए विश्वास जताया कि कांग्रेस पार्टी की सरकार उनके लिए अच्छे काम करेगी। कांग्रेस पार्टी के लोगों ने, मेलाओं ने एक नारा दिया था कि कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ और यह कहा था कि हम भय मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देंगे। माननीय बीरेन्द्र सिंह जी, वित्त मंत्री हरियाणा सरकार ने जो बजट पेश किया है उस बजट को जब मैं देख रहा था और पढ़ रहा था तो यह बात सत्ता पक्ष चाहे माने या न माने लेकिन यह बात अन्दरूनी तौर पर साफ झलक रही थी कि कहीं न कहीं यह पिछली सरकार चौधरी ओमप्रकाश चौटाला के नेतृत्व वाली सरकार के कायल हैं। वे बाहरी तौर पर तो जनता के सामने निन्दा कर रहे हैं। लेकिन बजट बनाने में उनकी झलक उन्होंने जरूर दी है। वित्तीय प्रबन्धन में सुदृढ़ आर्थिक ढांचे के अन्तर्गत वर्ष 2003-2004 और 2002-2003 में जो बताया गया है उस समय किसके नेतृत्व वाली सरकार थी ? उस वक्त चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व की सरकार थी। हरियाणा सरकार ने अपने इस बजट में माना है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार में अच्छा वित्तीय प्रबन्धन हुआ। इसकी तारीफ मैं नहीं करता बल्कि इसकी तारीफ स्वयं प्लानिंग कमीशन, भारत सरकार ने की अध्यक्ष महोदय, इसकी तारीफ योजना आयोग ने भी की, रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने भी की कि हरियाणा में वित्तीय प्रबन्धन बहुत अच्छा रहा। बजट एक ऐसा प्रस्ताव है जिसके माध्यम से सरकार अपनी नीतियां, अपने कार्यक्रम जनता के सामने पेश करना चाहती है कि वह जनता को क्या देना चाहती है या जनता पर क्या खर्च करना चाहती है, उनकी नीतियां क्या हैं या किन नीतियों के तहत प्लान करके वे खर्चा करेंगे और अगर कोई आपदा आ जाती है या कोई जरूरत पड़ जाए तो उसको नान-प्लान में कैसे खर्च करेंगे यह सारी तस्वीर बजट के माध्यम से दिखाई जाती है। (विघ्न) हमने क्या दिया और आप क्या देंगे तथा क्या दिया है आपने, इन सारी बातों का मैं जिक्र करूंगा अगर आप मुझे कहने का मौका देंगे। (विघ्न) माननीय सुरजेवाला जी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी तो मेरे लिए परमात्मा से भी बड़े हैं क्योंकि उन्होंने ही मुझे पार्लियामैंट में पहुंचाया और यहां विधान सभा में भी आने का मौका मुझे उन्हीं की वजह से मिला। हर आदमी का अपना नेता या गुरू होता है इसलिए मेरे लिए

तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी भगवान के समान हैं। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि सरकार अपनी नीतियां बजट के माध्यम से दर्शाती है, प्रदेश के लोगों को बताती है कि किस किस मद पर कैसे कैसे खर्च करेंगे और कहां से सरकार पैसा जुटाएगी, कर्जा लेगी या कर लगाएगी, यह सारी बातें विस्तार से बजट के माध्यम से सरकार बताती है। पिछली बातों को देखें तो सत्ता पक्ष के लोगों ने, बुरा न मानना, मैं 9 तारीख को भी यहां था और आज भी यहां हूं, सिवाय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को गालियां निकालने के या उनके कार्यक्रमों को गलत बताने के अलावा यहां कोई काम नहीं किया। कोई संदेश इन्होंने ऐसा नहीं दिया जिससे जनता को ये पता चल सके कि इनकी सरकार प्रदेश के लोगों के लिए यह-यह कार्य करना चाहती है। लोगों को इनसे बहुत उम्मीदें हैं तभी उन्होंने इनको भारी बहुमत से जिताया है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि बजट के माध्यम से हरियाणा सरकार ने लोगों को एक ऐसा सपना दिखाया जिसे पूरा करने के लिए शायद बहुत मशक्कत करनी पड़े और शायद ये कर भी न पाए। बजट में यथार्थ दिखना चाहिए और दिखना चाहिए कि उस सपने की नींव जो आप रखना चाहते हैं तो उस नींव में ईंट, गारा और मिट्टी लगाएंगे तो मजबूती आएगी या नहीं आएगी। पिछले बजट के प्लान के हिसाब से हम देखें तो पिछले रिवाइज्ड प्लान में 2237 करोड़ के मुकाबले में इस सरकार ने 3000 करोड़ का प्रावधान रखा है। 3000 करोड़ रुपये की इन्होंने प्लानिंग की है लेकिन कुछ खर्चे ऐसे हैं जिनका बजट में कोई जिक्र नहीं है लेकिन उन्होंने होना ही है। अगर खर्चे 3000 करोड़ से ज्यादा हो जाएंगे तो कहां से पैसा लाएंगे ? अध्यक्ष महोदय, इन सारी बातों को मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने सरकार सम्भाली थी तो उस वक्त प्रदेश की क्या हालत थी यह सबको मालूम है कि उस समय किस तरह से हमारे प्रदेश का आर्थिक ढांचा था ? बड़ी खुशी की बात है और आप तो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि पिछली सरकार के मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के कारण आपकी सरकार को प्रदेश की बहुत सुदृढ़ अर्थ व्यवस्था मिली है। अध्यक्ष महोदय, मौजूदा सरकार ने जो घोषणाएं की हैं उनके बारे में मैं धीरे-धीरे बताऊंगा। 2003-04 में नान-प्लान में जो खर्चा था वह 10563 करोड़ रुपये थे यानि की हमारी सरकार ने पहले जो खर्चा बढ़ गया था, उसको धीरे-धीरे कम करके काफी कम कर दिया था और अब नान प्लान में 11160 करोड़ रुपये खर्चा बनता है। यदि इसको पिछले प्लान के और इस प्लान के रिवाइज्ड एस्टिमेटस के हिसाब से देखें तो इसमें 1159 करोड़ रुपये फालतू खर्चा होता है जबकि पिछली बार 572 करोड़ रुपये था। इसी प्रकार से राजस्व घाटे की जहां तक बात है। जिस समय हमारी सरकार ने सत्ता संभाली थी उस समय यह 1998-99 में 1540 करोड़ रुपये था और हमारी सरकार आने के बाद यह हमारा 2004-05 में घटकर 226 करोड़ रुपये रह गया था। 2005-06 का जो अनुमानित राजस्व घाटा है वह 948 करोड़ रुपये है यानि कि हमारी सरकार को जो 1540 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा मिला था और जिसको कम करके हमने 226 करोड़ रुपये किया था, उसको यदि हम मौजूदा सरकार का बजट देखें, सरकारी नीतियां देखें तो पता चलता है कि यह सरकार राजस्व घाटे को फिर से बढ़ाकर वहीं पहुंचा देगी जो पिछली सरकारों के समय हो गया था। अध्यक्ष महोदय, यह तो मौजूदा सरकार का पहला बजट है यदि ऐसी ही सोच सरकार की रही तो प्रदेश की अर्थव्यवस्था आने वाले पांच सालों में चरमरा जायेगी और दोबारा से हमारी सरकार आने पर भी हम उसे नहीं संभाल पायेंगे। जहां तक राजकोषीय घाटे का सवाल है, इस बारे में मैं बताना चाहूंगा कि 1998-99 में राजकोषीय घाटा 2240 करोड़ रुपये था जिसे हमारी सरकार कम करके वर्ष 2004-05 में 1026 करोड़ रुपये तक ले आई थी लेकिन मौजूदा सरकार ने जो प्लान

[डॉ० सुशील इन्दौरा]

बनाये हैं उनसे राजकोषीय घाटा 2323 करोड़ रूपये होने जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मौजूदा सरकार कह रही है कि प्रदेश के विकास के लिए वित्त के बड़े अच्छे और सुदृढ़ प्रबन्धन किए गए हैं लेकिन आंकड़े तो कुछ और ही बताते हैं। जहां तक ब्याज के भुगतान की बात है इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि सरकार अपने आर्थिक ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए, प्रदेश की जनता को सुविधाएं देने के लिए लोन लेती है, सभी सरकारें लेती हैं और हर साल लेती हैं तथा उनका भुगतान भी किया जाता है। 2003-04 में हमारी सरकार के समय में ब्याज भुगतान 2113 करोड़ रुपये था, 2004-05 में यह 2166 करोड़ रुपये था और यदि इस बजट में देखें तो यह बढ़कर 2354 करोड़ रुपये आने वाले समय में हो जायेगा। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से सरकार हरियाणा के लोगों को सुविधाएं दे पायेगी, किस तरह से हरियाणा के लोगों की आंकाक्षाओं पर यह सरकार खरी उतर पायेगी ? जहां तक कर्ज की देनदारी का सवाल है 2003-04 में हमारी सरकार के समय में कर्ज की देनदारी की सीमा 21616 करोड़ रुपये की थी, 2004-05 में यह देनदारी की सीमा 22902 करोड़ की हो गई और आने वाले वक्त में कर्ज की देनदारी की सीमा बढ़कर 25619 करोड़ रुपये हो जायेगी। ये लोग हमारी सरकार को कहते थे कि हमने प्रदेश को कर्जा लेकर देनदारी में डुबो दिया। अध्यक्ष महोदय, यह इतनी ज्यादा देनदारी तो एक साल में होने जा रही है अगर खुदा न खास्ता यह सरकार पांच साल तक चली तो पता नहीं प्रदेश के क्या हालात होंगे ? हुड्डा साहब, ध्यान रखिये कई दफा अपने लोग ही चकमा दे देते हैं इसलिए मैं कह रहा हूं कि यदि पांच साल तक यह सरकार चली तो प्रदेश की अर्थव्यवस्था इस तरह के बजट से चरमरा जायेगी और हर आदमी कर्ज के नीचे पूरी तरह से दब जायेगा। जहां तक पैंशन एवं सैलरीज के खर्च की बात है, सरकार इसके लिए हमेशा प्रबन्ध करती है कि उसके इम्लाईज को सुविधाएं मिलें। माननीय वित्त मन्त्री जी ने अपने अभिभाषण में कहा था कि कर्मचारियों के कार लोन बढ़ाएं जाएंगे, कर्मचारियों के हाउस लोन बढ़ाए जाएंगे और दूसरी सुविधाएं भी उनको दी जाएंगी। सरकारी कर्मचारियों को यह सब सुविधाएं दी जाती हैं क्योंकि यह सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार द्वारा इन जिम्मेदारियों का प्रबन्ध इस तरह से किया जाता है कि आमदनी भी बढ़े और विकास कार्य भी हों। अगर खर्चा बढ़ता है तो आमदनी बढ़ाना भी जरूरी है। अगर आमदनी बढ़ेगी तो खर्च को नियन्त्रित किया जा सकता है। राजस्व प्राप्तियों के मुकाबले में अगर हम आमदनियां बढ़ी हुई दिखा दें तो उससे काम नहीं चलता । अगर हम तुलना करके देखें तो वर्ष 1998-99 में 59.03% राजस्व प्राप्तियां थीं और वर्ष 2004-05 में 40.2% राजस्व प्राप्तियां थीं और अब जो सैलरी देंगे और दूसरे खर्चे करेंगे उसमें आधारभूत ढांचे पर तो कुछ भी खर्च नहीं होगा। यानि 1998-99 में हमारे पास इतना पैसा था कि अगर हम 100 रुपये कमाए और उसमें से हम पैंशन दे दें, सैलरी दे दें और जो बच जाए उसको आधारभूत ढांचे पर खर्च कर दें तो भी दिक्कत नहीं थी लेकिन इसके मुकाबले में हमारे पास वर्ष 2005-06 में पैसा कम बचेगा। वर्ष 2004-05 में जहां हम 60 रुपये आधारभूत ढांचे पर तथा 40% सैलरी और पैंशन पर खर्च कर सकते थे वहीं अब वह पैसा घट कर 60 में से 58 रुपये रह गया है। हम इसमें और बढ़ौतरी कर देते हैं यदि हम लोगों के बीच में भाषण दे कर आते हैं, जनता में कुछ कह आते हैं कुछ वायदे कर आते हैं और कुछ लुभावने वायदे कर आते हैं क्योंकि इन पर खर्च होने वाले पैसे को हम यहां पर नहीं दिखा पाते हैं। लेकिन इस बजट में जो दिखाया गया है, दर्शाया गया है वह सब सरकार की खर्च और राजस्व प्राप्तियां ही हैं। राज्य की अर्थ-व्यवस्था का सही रूप अगर हम मानते हैं तो राजस्व प्राप्ति में

बढ़ौत्तरी खर्च के मुकाबले में ज्यादा होगी तभी प्रदेश की अर्थ-व्यवस्था सुधरेगी। (विघ्न) स्पीकर सर, इस बजट में पहली बार ऐसा हो रहा है। कि जो राजस्व प्राप्तियां 2004-05 में 1138.52 करोड़ रुपये थीं वह वर्ष 2005-06 में 1237.27 करोड़ रुपये हो गई यानि कि इन्क्रीज 5.7% की है और जो खर्च बढ़ेगा, वह भी मैं यहां पर बता देता हूं। वर्ष 2004-05 में खर्च 11614.2 करोड़ रुपये था अब वह बढ़ कर 12985.49 करोड़ रुपये हो जाएगा यानि कि खर्च में इन्क्रीज 11.8% बढ़ गई। यह सरकार इसको कैसे सम्भालेगी ? यह बजट में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि सरकार कैसे इस खर्च को सम्भालेगी ? जहां तक जनता को सुविधाएं देने की बात है, आधारभूत ढांचे पर जो हम खर्च करते हैं वह हम जनता को सुविधाएं देने के लिए ही खर्च करते हैं। जैसे कि बिजली की व्यवस्था करने की बात है, पानी की बात है, सड़क की बात है परिवहन और यातायात के साधन सुचारू रूप से देने की बात है, कोई भी सरकार चाहे वह राज्य की सरकार है और चाहे वह केन्द्र की सरकार है, उसकी अपनी प्राथमिकताएं होती हैं कि हम अपने देशवासियों को ये चीजें देंगे। हमारे पास आमदनी का अगर 100 रुपया आयेगा तो उसमें से फर्स्ट तो हम सैलरी और पैंशन का खर्च निकाल दें और उसमें से बाकी बचे पैसे को अगर हम इन्फ्रास्ट्रक्चर पर लगाएं तो हम काम कर सकते हैं। लेकिन अगर पिछली बार को देखा जाए तो परिवहन आदि पर हमारा जो खर्च होता है वह तकरीबन 45% होता है। स्पीकर सर, यह सारी बातें ऑन दि रिकार्ड की बातें हैं। सरकार के पास सारे रिकार्ड होते हैं। अब जो हम इन्फ्रास्ट्रक्चर में खर्च कर पाएंगे वह हम 39% ही ज्यादा खर्च कर पाएंगे यानि कि 6% का डिफरैंस है जो यहां पर हो गया है। अगर 6% का डिफरैंस हो जाता है तो आप कैसे इस प्रदेश का विकास कर पाएंगे ? स्पीकर सर, इसका मतलब यह है कि सरकार का ध्यान विकास की तरफ से हट रहा है और घोषणाओं की तरफ बढ़ रहा है। सरकार ने इस तरह की घोषणाएं की थीं कि ' **कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ**' आज गरीब की हालत आपके सामने है ? भय और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की बात इस सरकार ने कही थी अध्यक्ष महोदय, जो मेरी जानकारी में है उसके मुताबिक माननीय मुख्यमंत्री जी के मोहल्ले में ही इन दिनों 10-10 चोरियां हुई हैं। मेरे जिले में से भी एक 4 क्विंटल की तिजोरी ही चोर उठाकर ले गए। पता नहीं वे उस तिजोरी को क्रेन से उठाकर ले गए या कैसे ले गए लेकिन ले गए हैं। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा था कि अगर कांग्रेस का राज आया तो हम हरियाणा में भय मुक्त राज देंगे और ला एंड आर्डर सुधरेगा। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से सदन में बताना चाहूंगा कि मेरा एक दोस्त नरवाना में इन्वयोरैंस कम्पनी में लगा हुआ है वहां पर उससे कुछ लोगों ने उसकी कार छीन ली थी। उस दोस्त ने मुझे कहा कि आप जींद के एस०पी० को कह दो। जब मैंने वहां पर एस०पी० को फोन किया तो उसने मुझे कहा कि मुझे मालूम है कि उसकी कार चोरी हो गई है। अध्यक्ष महोदय, मैंने एस०पी० साहब को कहा कि आपने छीनी हुई गाड़ी को चोरी हुई कह कर इस केस की धारा ही बदल दी है। अध्यक्ष महोदय, एक गाड़ी चोरी हो गई हो और दूसरी गाड़ी छीनी गई हो और जिले के एस०पी० को यही नहीं पता हो इन दोनों में क्या फर्क है तो ये हालात तो इनके राज में है कि इतना सीनियर आफिसर इस तरह की बात करता है ? इनके राज में आज क्राईम रेट बहुत बढ़ा है।

शिक्षा मंत्री (श्री फूल चन्द मुलाना) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आप आर्डर है। अध्यक्ष महोदय, मैं इनसे यह जानना चाहूंगा कि इनके राज में कितना क्राईम रेट था और आज कितना क्राईम रेट है ?

श्री अध्यक्ष: मुलाना जी, क्यों पूछते हो ! क्या यह किसी से छिपी हुई बात है ?

श्री फूल चन्द मुलाना : अध्यक्ष महोदय, इनके राज में तो जी०टी० रोड़ भी सेफ नहीं थी। आज तो क्राईम रेट घटा है। अध्यक्ष महोदय, एक शायर के शब्दों को मैं कोट करना चाहूंगा--

इनके राज के हालात बताने लगेंगे, तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे।

कहां खो गई इनकी असलियत, उसे ढूंढने में जमाने लगेंगे।।

श्री अध्यक्ष: मुलाना साहब, आप बैठ जाएं। प्लीज बैठिए।

डॉ० सुशील इन्दौरा : मुलाना साहब, आज आपकी सरकार है और आप के पास सारे आंकड़ें है, आप अपनी सरकार के इन तीन महीनों के आंकड़े और उस वक्त के आंकड़ों को भी देख लें। आपको अपने आप ही पता चल जाएगा। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और वित्तमंत्री जी ने कहा कि प्राकृतिक आपदा से हुए नुक्सान के लिए मुआवजा देंगे। स्पीकर सर, हमारे उपर अभी लांछन लगाया गया था कि हमारे समय में बहुत कम प्रतिशत राशि मुआवजे की बढ़ाई गयी थी। अध्यक्ष महोदय, हमारे से पहले की सरकारों ने इस राशि को कभी एक रुपया बढ़ाया था तो कभी 50 पैसे बढ़ाया था। अध्यक्ष महोदय, यह ऑन रिकार्ड की बात है और यह सरकार भी इसको जानती है कि हमारे वक्त में जब ओलावृष्टि से फसलों का नुक्सान हुआ था तो चौधरी देवी लाल जी ने 17 अप्रैल 2001 को यह मुआवजा 600 रुपए से बढ़ाकर 2000 रुपए कर दिया था। उस वक्त तकरीबन 233 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया था। लेकिन आज यह सरकार हमारे उपर लांछन लगाती है कि हमने मुआवजा नहीं बढ़ाया था। आज यह सरकार किसानों की हितैषी होने का दावा तो करती है लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि कांग्रेस उंगली कटा कर शहीद होने वाली बात का दावा तो कर सकती है लेकिन किसानों के बारे में कुछ नहीं कर सकती है। अब इस सरकार ने बजट में कहा है कि गुड़गांव में किसानों की जो लैंड एक्वायर की जाएगी उसके लिए उनको 15 लाख रुपए प्रति एकड़ मुआवजा देंगे, एन०सी०आर० के एरिया में साढ़े बारह लाख रुपए प्रति एकड़ देंगे और राज्य के अन्य क्षेत्रों के लिए पांच लाख रुपए प्रति एकड़ मुआवजा देंगे। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारी सरकार के वक्त में 8-10-2001 को गुड़गांव के सैक्टर 37के लिए जब खांडसा गांव की जमीन के मुआवजे के लिए अवार्ड हुआ था तो उस वक्त वहां पर 15 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया गया था। उसके बाद कितना इंफ्लेशन हुआ था यह सब तो आप जानते हैं। स्पीकर सर, उसके बाद फिर गुड़गांव जिले के सिरहोल गांव में 12-3-2004 को जब अवार्ड दिया था तो उसमें भी 20 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया गया था। That was the decision not of the Government, that was the decision of the Land Acquisition Officer. उस वक्त 20 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया गया था और आज यह सरकार किसान की हितैषी होने का दावा करती है। ये आज गुड़गांव के हालात देखें तो इनको पता चलेगा कि किसानों को कितना पैसा मिला है ? जहां करोड़ों की जमीन है और पहले की सरकार जहां पर 15 लाख और 20 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दे चुकी है उसके बदले में आज ये 15 लाख रुपए देकर यह कहते हैं कि इनकी सरकार किसानों की हितैषी सरकार है।

स्पीकर साहब, अभी 9 तारीख को भी एक हादसा हुआ और माननीय मुख्यमंत्री जी सिरसा में भी गए थे, मैं उसके लिए इनका धन्यवाद करता हूं। ये केवल छतरीया गांव में और उतावड़ गांव में गए थे। हालांकि हमारे यहां पर कई ऐसी जगह थीं जहां पर कई बड़े-बड़े हादसे हुए थे, मकान

भी ढह गए थे और तूड़ी जल गई थी। स्पीकर सर, इतनी बुरी हालत हुई थी कि आज वहां पर नरमा कपास की फसल दोबारा से नहीं बोई जा सकती है। (विघ्न) अगर यह सरकार किसानों की इतनी ही हितैषी है तो इनको इस बारे में कुछ करना भी चाहिए। (विघ्न) अगर सही मायनों में ये किसान के हितैषी हैं तो इनको इसी सत्र में ही इस बारे में घोषणा करनी चाहिए क्योंकि अब नरमें की बिजाई नहीं हो सकेगी। (विघ्न) नरमें की फसल का जो नुक्सान हो गया उसके लिए कम से कम बीस हजार रुपये किल्ला भी देने की अगर सरकार घोषणा करे तो हम उसका स्वागत करेंगे। (विघ्न) सत्ता पक्ष की तरफ से यह बात जरूर आती है चौधरी कि देवीलाल के बूल लगा दिए। अध्यक्ष महोदय, हर आदमी अपने नेता का मान-सम्मान करता है। श्रीमती सोनिया गांधी हमारे लिए भी सम्माननीय हैं हालांकि वे कांग्रेस पार्टी की नेता हैं लेकिन हम भी उनका मान करते हैं। मैं एक बात को जरूर कहूंगा कि हर सरकार अपने नेता का सम्मान करती है, हमारी पार्टी भी अपने नेता का सम्मान करती थी और ये भी अपने नेता का सम्मान करते हैं लेकिन कम से कम इनको कुछ तो ऐसा करना चाहिए की इनके नेता का भान सम्मान तो बढ़े। सिर्फ जींद में एक महिला कालेज श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम से खोलने की ये बात कर रहे हैं जोकि बड़े दुख की बात है। कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी मैजोरिटी से आयी है इसलिए इनको अपने नेता का उचित ढंग से सम्मान करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इतनी बड़ी पार्टी की वे नेता रही हैं, वे देश की भी प्रधानमंत्री रही हैं एवं वे इस देश की सम्मानित नेता रही हैं लेकिन अगर उनके नाम से सिर्फ एक छोटा सा महिला कालेज जींद में खोला जाता है तो इसी से इनकी मंशा जाहिर हो जाती है इसी से पता चलता है कि ये कितने बड़े हित चिन्तक हैं।

Mr. Speaker : Mr. Indora, please take your seat. Your time is over now.

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, मैं हकीकत बता रहा हूं। चौधरी देवीलाल के बुतों के बारे में तो यहां पर कह दिया जाता है। मैं इनको एक बात और बता देना चाहता हूं। सरकार ने फैसला लिया है कि स्वर्गीय राजीव गांधी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, के नाम से एक एजुकेशन सिटी स्थापित किया जाएगा। (विघ्न)

Mr. Speaker : Hon. members take your seats. Let him proceed . Let him conclude. He is not going to say Irrelevant thing Let him conclude his speech. (Interruptions) Dr. Sahib, Please be relevant. Only 2 minutes are left. I am not going to extend your time, because everybody wants to speak on Budget.

डॉ० सुशील इन्दौरा : सर, मैं पांच या सात मिनट और लूंगा।

श्री अध्यक्ष : आप दो मिनट में अपनी बात खत्म करें।

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, राजीव गांधी के नाम से एक एजुकेशन सिटी बनाने की बात इस बजट में कही गयी है लेकिन इससे बुरी और क्या बात होगी कि इसके लिए बजट में केवल पांच लाख रुपये का प्रावधान किया गया है ? अध्यक्ष महोदय, ये उनके नाम से एक आक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं लेकिन बजट में इसके लिए केवल पांच लाख रुपये का ही प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री बीरेन्द्र सिंह जी नहीं है उनको यह बात देखनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में बजट में काफी ढूढंता रहा क्योंकि यह काफी बड़ी यूनिवर्सिटी होगी लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। मैमोरैंडम, 2005 में नॉन प्लान ऐक्सपैंडीचर स्कीम

[डॉ० सुशील इन्दौरा]
में इन्होंने पेज नं० 226 पर यही लिखा है कि इस लिए केवल पांच लाख रुपये ही खर्च करेंगे। अध्यक्ष महोदय, इससे सरकार की मंशा का पता चल जाता है। पता नहीं इतने रुपयों से ये कैसे आक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी यहां खोलेंगे ?

Mr. Speaker : Mr. Indora Your time is over. Please conclude.

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से हर जिले में एक माडल स्कूल खोलने की बात बजट में कही गयी है। अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से माननीय वित्त मंत्री जी ने बर्बली कहा था कि एक स्कूल के लिए तीन करोड़ रुपये खर्च करेंगे। उन्होंने केवल 18 जिलों का ही जिक्र किया था जबकि मैं समझता हूं कि हरियाणा में 20 जिले है। खुदा न खास्ता अगर कांग्रेस पार्टी मेवात जिले को जिला नहीं मानती है तो भी 19 जिले बनते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि ये माडल स्कूल खोलने की बात आज की नहीं है। इसका उदाहरण है कि वर्ष 2003-04 के बजट में भी पंचकुला में एक माडल स्कूल खोलने की बात कही गयी है।

Mr. Speaker : Thank you Mr. Indora.

डॉ० सुशील इन्दौरा : सर, मैं पांच मिनट और लूंगा।

Mr. Speaker : No, no. Please take your seat.

डॉ० सुशील इन्दौरा : सर, अभी तो एस०वाई०एल० का मुद्दा और है।

Mr. Speaker : I say no. Your time is over. Shri K.L. Sharma, you may start now.

श्री खैराती लाल शर्मा (शाहाबाद) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। वर्ष 2005-06 का जो बजट माननीय वित्त मंत्री महोदय ने 9 जून, 2005 को इस महान सदन में प्रस्तुत किया, मैं उसका अनुमोदन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। सच बात तो यह है कि अगर विरोध करने के लिए ही इस बजट का विरोध किया जाए तो अलग बात है परन्तु ध्यान से पढ़कर समझने की कोशिश की जाए तो इससे बढ़िया और प्रशंसनीय बजट कोई दूसरा नहीं हो सकता। मैंने पिछले भी 3-4 साल के बजट पढ़े हैं सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस चीज को ये बार बार कह रहे हैं कि 3 हजार करोड़ रुपये के वार्षिक प्लान से कैसे काम चलाएंगे तो ये पहले अपना पिछला बजट उठाकर देखें। इन्हें वर्ष 2004-05 के लिए वार्षिक प्लान के रूप में 2100 करोड़ रुपया मिला था। बाद में उसमें संशोधन करके इनको 2236.72 करोड़ रुपया मिला था। इस तरह से उससे 34 परसैंट ज्यादा पैसा हमने लिया है और ये साथी बार बार कह रहे हैं कि यह पैसा कम पड़ जाएगा। यह बड़ी सोच की बात है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने भय भ्रष्टाचार मुक्त शासन तंत्र देने की बात की थी। विपक्ष के साथी आज यह कह रहे हैं कि हमारे मोहल्ले से साइकिल चोरी चली गई, हमारे वहां एक दुकान से गल्ला चोरी हो गया, मैं इन साथियों को बताना चाहूंगा कि जब किसी सरकार की ला एंड ऑर्डर की बात करते हैं तो वह चीज कहनी चाहिए जिसके पीछे कोई बात नजर आती हो। अध्यक्ष महोदय, अब मैं अपने इलाके की बात कहना चाहता हूं। मेरा इलाका आपके इलाके के साथ-साथ लगता है। पिछले सात आठ साल से जी०टी० रोड़ के साथ लगता

हुआ एरिया जैसे शाहबाद मारकंडा का एरिया पिपली का एरिया और उधर अम्बाला तक का एरिया अपराध की स्थली के रूप में पनप गया था। यहां तस्करी और नशीले पदार्थों की बिक्री होती थी। पिछले आठ साल के अंदर किसी सरकार के कान में जूं नहीं रेंगी, किसी ने कुछ नहीं किया। जो जी०टी० रोड़ पर ढाबे थे वहां जाकर सरकार के एम०एल०ए० हार डलवाया करते थे। चण्डीगढ पुलिस ने वहां जाकर छापे मारकर ऐसी तस्करी करने वाले लोगों को पकड़ा। अभी थोड़े दिन पहले पेपर में था कि कोई मि० यादव, एस०पी०, चण्डीगढ़ के हैं, उन्होंने कहा है कि हरियाणा सरकार को हमने इस बारे में दो बार पहले भी इन्फार्म किया था। अध्यक्ष महोदय, मुझे याद है कि मैं एक डैथ केस के सिलसिले में शमशान भूमि में गया था वहां एक बुढ़िया रोती हुई मिली और मुझे कहा कि परमात्मा ने आपको मौका दिया है आप कुछ कर सकते हैं उसने मुझे रिक्वैस्ट की कि आप इस तस्करी की बीमारी को और नशे की बीमारी को दूर कीजिए। उसने कहा कि इस बीमारी से मेरे दो बेटे थे, दोनों गुजर चुके हैं अब मुझे कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं है। मैंने इसके लिए आई०जी०, सी०आई०डी० श्री परमिन्द्र सिंह राठी से टैलीफोन पर बात की । आई०जी०, अम्बाला से भी मिला और मुख्यमंत्री जी से भी मिला। मैं इनको बधाई देना चाहता हूं कि पिछले दो महीने से वहां पर इस तस्करी पर पूर्ण विराम लगा हुआ है। वहां पर एक भी तस्कर नहीं पकड़ा गया। ऐसा हुआ है। लेकिन मैं इसके साथ एक बात कहना चाहूंगा कि यह सोच लेना कि यह काम बन्द हो गया है, ठीक नहीं होगा। इसके लिए हमें और वाच करना होगा क्योंकि दो महीने का कोई सफीशियंट टाईम नहीं है। हां अगर 6 महीने तक अंकुश लगा कर रखें तो ठीक रहेगा। जो आफिसर्ज वहां पर लगाकर रखे हैं वे वहीं रखे जायें तो शायद वे लोग अपना स्थान बदल लेगें। वरना वे वहां पर फिर से पनप सकते हैं। (विघ्न) यह अगर लॉ एण्ड आर्डर को कंट्रोल करने की बात नहीं है तो और क्या हो सकती है ? बजट के पैरा 9 में पैंशन की बात कही गई है। स्पीकर सर, आपको याद होगा, चुनाव के समय में जब हम गांवों में जाते थे तो बड़ी भारी भ्रान्ति फैलाई गई थी। लोगों को कहा जाता था कि अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो वृद्धा पैंशन और जो सो काल्ड कार्यक्रम हैं जो वे कहते थे कि हमने शुरू किए हैं, उन पर विराम लग जायेगा और वृद्धा पैंशन बन्द कर दी जायेगी। लेकिन जैसे ही हमारी कांग्रेस की सरकार आई तो आते ही न केवल वृद्धा पैंशन बल्कि उस के साथ-साथ विकलांगों, विधवा और निराश्रितों को दी जाने वाली पैंशन की पुष्टि भी की गई। इससे एक तो हमारा नैतिक कार्य पूरा हुआ तथा जिन आखों में विश्वास अविश्वास में बदल गया था और इन बातों को सुन करके जिनको अविश्वास की एक परछाई नजर आती थी कि शायद कांग्रेस के टाईम में कहीं हमारी पैंशन कट न जाये उनको भी अब कृतज्ञता के भाव नजर आने लगे हैं। स्पीकर सर, थोड़े दिन पहले की बात है कि एक बुजुर्ग आदमी हमारे पास आया था। उस समय आप भी वहीं थे मैं भी वहीं था क्योंकि उस दिन कुरुक्षेत्र में महाराणा प्रताप जयन्ती मनाई जा रही थी। एक व्यक्ति स्टेज पर चढ़कर अपनी खुशी का इजहार करता हुआ दुहाई दे रहा था। उसके वर्डिंग थे कि 'पहले भूपि, फिर भूपेन्द्र और अब भूप' बना हरियाणा का। आपने अगर उस आदमी के भावों को पढ़ा होता, उस बुजुर्ग की लैंग्वैज को अगर समझा होता। तो आपको पता लगता कि जो इन लोगों द्वारा बातें कही गई थीं, उनका असर आज लोगों के अन्दर क्या आया है ? जब आखें दुआ के लिए उठती हैं तो इसे आप समझ सकते हैं। उस व्यक्ति की आखें भी दुआ के लिए ही उठी थीं और उसी का परिणाम हुआ कि तीन उप-चुनावों में रिकार्ड कायम हुआ। जो पहले कभी नहीं हुआ था और न ही आगे कभी आने वाले समय में टूटता हुआ नजर आता है। स्पीकर सर, बजट में पैरा 14 में गरीब और किसान की हितैषी सरकार की बात कही गई है। स्पीकर सर, इसके बारे में मैं एक

[श्री खैराती लाल शर्मा]

बात कहना चाहूंगा कि जो आर्थिक सर्वेक्षण दिया हुआ है, सरकार ने उसमें मैंनशन किया है कि अन्त्योदय अन्न योजना केन्द्र सरकार ने चालू की है उसके अन्दर अत्यंत गरीब परिवारों के लिए 35 किलों गेहूं दो रुपये प्रति किलो के हिसाब से दिया जायेगा। जो परिवार पावर्टी लाईन से नीचे हैं, उन परिवारों को इस योजना के तहत अन्न देने की बात कही गई है। इसके साथ यह भी कहा गया है कि इसमें जो 3.80 करोड़ का खर्चा होता था और जो लाभ मिलता था, वह लाला लोग ले लेते थे लेकिन अब वह भी सरकार द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा। जिनको लाल और गुलाबी कार्ड दिए गये हैं उनको 6353 मीट्रिक टन गेहूं का आबंटन प्रति मास हरियाणा में होता है। 1,92008 अन्त्योदय परिवारों को गुलाबी कार्ड दिए जा चुके हैं। स्पीकर सर, इसके बारे में भी मेरा कहना है कि अन्धा बांटे रेवड़ी मुड़-मुड़ कर अपनों को दे तो यह बात इसमें होती है। आप भी गावों में जाते हैं और हम भी गावों में जाते हैं तो वहां एक ही बात सुनने को मिलती है कि गुलाबी कार्ड उन्हीं व्यक्तियों को दिए गये हैं जो इसके पात्र नहीं है। स्पीकर सर, अगर कोई अच्छी योजना है, गरीब लोगों की योजना है तो सरकार उसको चलाए। जिन गरीब लोगों तक लाभ पहुंचाने के लिए योजना बनाते हैं अगर उस योजना का लाभ उन गरीब व्यक्तियों तक नहीं पहुंच पाये और भाई-भतीजावाद को सामने रखकर सो-काल्ड अपने लोगों की बात की जाए तो वहां पर कैसे लोगों का भला हो सकता है ? मेरी मुख्यमंत्री महोदय और वित्त मंत्री महोदय से गुजारिश है कि जब वे कुरुक्षेत्र में गए थे तब भी हमने यह बात कही थी कि इसका सर्वे कराया जाए क्योंकि तब ही पता लगेगा कि किन लोगों को ये दिये गये हैं, कौन इसके पात्र हैं, किसको इनकी जरूरत है, किसको इनसे फायदा हो सकता है ? अभी यहां किसान के हित की बात की जा रही थी। अभी भाई इन्दौरा जी बता रहे थे कि हमारी सरकार किसान के हित की सरकार थी लेकिन यह बात तो सामने आ चुकी है। यह कहने का फैसला हमने और आपने नहीं करना, यह फैसला किसान के बेटे ने कर दिया कि किसान के हितैषी कौन है ? किसान का हितैषी वह कैसे हो सकता है क्योंकि जिसको किसान ने कुर्सी पर बिठाया उन्होंने उसी किसान पर देशद्रोह का मुकदमा चलवाया और उन पर गोलियां चलवाई। भारतवर्ष की संस्कृति रही है कि अगर किसी ने किसी महिला या माता पर आंख उठाई तो उसको बक्शा नहीं जाता। रावण जैसे व्यक्ति को यहां बख्शा नहीं गया, लेकिन हमारे यहां के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने किसान की बेटी और बहू को नहीं बक्शा और उनको जेल में भेजने का काम किया। ऐसा व्यक्ति किसान का सिपाही या हितैषी कैसे हो सकता है ? इन्दौरा जी, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। मेरे इलाके में एक गांव खड़नी है जब मैं वहां एक रैली में गया तो वहां एक व्यक्ति महमा सिंह जो पहले आपके साथ जाया करता था, हरे रंग का साफा पहना करता था, 4-4 ट्रक खाने के बनवाकर आपकी रैली में जाया करता था मुझे मिला इस बार वह सफेद साफा और गले में कांग्रेस का पट्टा डालकर बैठा था। मैंने उससे पूछा कि आपका हरा साफा कहां गया तो उसने कहा कि मैंने उस हत्यारे का हरा साफा फाड़कर फैंक दिया। भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी की सरकार ही सही मायनों में कांग्रेस की हितैषी सरकार है। उनका अंगवस्त्र मैंने पहन लिया है और मैं यहां आपके सामने बैठा हूं । इस तरह से कांग्रेस की हितैषी सरकार मेरे कहने या आपके कहने से नहीं है बल्कि हरियाणा की जनता ने, किसान के बेटे ने इस बारे में फैसला कर दिया है कि किसान का हितैषी कौन है। बजट के पैरा नं० 17 पर सिंचाई और सतलुज यमुना लिंक कैनाल की बात की गई है। इससे पहले वाले पैरा में जमीन के मुआवजे की बात आई है। अध्यक्ष महोदय आपको याद होगा जब शुरू में यह सरकार बनी ही थी और आपने इस गरिमामय पद को सम्भाला ही था तभी

टेलीफोन पर इन्फर्मेशन आई कि हमारे इलाके में बहुत भारी वर्षा के साथ ओलावृष्टि हुई है। बाद में पता लगा कि बहुत भारी मात्रा में हमारा नुकसान हो गया। आप रात को ही वहां चले गए और सुबह आए। सैशन चल रहा था, मैं भी वहां गया। अभी हमारे भाई कह रहे थे कि हम तो मुआवजा मांगते नहीं । और हमारे टाईम में ज्यादा मुआवजा दिया गया है। इस बार जब हम मुआवजे की लिस्ट मुख्यमंत्री जी के पास लेकर गए और डिस्कस किया तो पता लगा कि इनके सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड से जब किसी की भरपाई नहीं हो पाएगी। तो उस किसान की भरपाई कैसे हो पाएगी ? यह उस वक्त पहला सैशन था, और उस वक्त मुख्यमंत्री अभी ओथ लेकर बैठे ही थे लेकिन उन्होंने उसी समय फैसला लिया कि भरपाई का पैसा पूरा करने के लिए 50 प्रतिशत कम से कम गेहूं की फसल के लिए वृद्धि की जाएगी और 25 प्रतिशत दूसरी फसलों के लिए वृद्धि की जाएगी यह रिकार्ड की बात है जो आपकी समझ में नहीं आएगी। पता नहीं कब का आप 6000 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा सुना रहे हैं ? आप कभी 600 से 6000 की बात करते हो। आपको 4 दिन पहले की बात तो समझ में नहीं आती, पता नहीं कौन सी पुरानी बातों को कहते जा रहे हो। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं वित्तमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। कि इन्होंने बजट में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए 124.37 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। प्राकृतिक आपदाओं के लिए यह पर्याप्त राशि है और इस राशि के एक साल में जो भी आपदाएं आयेंगी उनसे निपटा जा सकेगा। इसके साथ-साथ मैं सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण के बदले में मिलने वाले मुआवजे का जिक्र करना चाहूंगा। मेरे विपक्ष के साथी कह रहे थे कि उनकी सरकार के समय में गुड़गांव में 15 लाख या 20 लाख रुपये भूमि अधिग्रहण करने पर प्रति एकड़ सरकार ने किसानों को दिया। इस बारे में मैं विपक्ष के साथियों को बताना चाहूंगा कि किसी बिजनैस सैंटर के अधिग्रहण पर 20 लाख रुपये मुआवजे के दिए होंगे लेकिन बाकी जमीन के अधिग्रहण के मापदण्ड स्थापित नहीं किए। जबकि हमारी सरकार ने अधिग्रहण की जाने वाली भूमि के मुआवजे के मापदण्ड स्थापित किए हैं। केवल एक शहर के लिए नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के लिए किए हैं। अगर गुड़गांव की बात आती है तो गुड़गांव में भूमि अधिग्रहण करने पर न्यूनतम 15 लाख रुपये प्रति एकड़ मुआवजे के दिए जायेंगे। इसके अतिरिक्त पंचकुला तथा चण्डीगढ़ के निकट के क्षेत्रों समेत शेष एन०सी०आर० में 12.5 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जायेगा और राज्य के अन्य क्षेत्रों में पांच लाख रुपये भूमि अधिग्रहण करने पर मुआवजे के दिए जायेंगे। इस तरह के मापदण्ड हमारी सरकार ने स्थापित किए हैं। जो बहुत ही सराहनीय कार्य है। इंदौरा साहब, आपकी सरकार ने गुड़गांव में किसी बिजनैस सैंटर को 15 या 20 लाख रुपये मुआवजा दिया होगा लेकिन आपकी सरकार के बाकी क्षेत्रों के लिए मापदण्ड नहीं थे कि गुड़गांव में जो भी जमीन एक्वायर की जायेगी उसको 15 या 20 लाख रुपये मुआवजे के दिए जायेंगे। आपकी सरकार के समय में यदि कहीं पर पांच लाख रुपये भी डी०सी० रेट के हिसाब से दिए हों तो आप बतायें कहीं नहीं दिए गए। इंदौरा साहब, कमियां छुपाने से छुपती नहीं हैं। जबकि हमारी सरकार ने जो सलम एरियाज हैं यदि वहां भी भूमि अधिग्रहण की जायेगी तो उनके लिए भी पांच लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब मुआवजा देने के मापदण्ड निर्धारित किए हैं। अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त एक बहुत ही अच्छी बात छुपे शब्दों में वित्तमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने मानी है कि यह सरकार समझौते और बातचीत की नीति में विश्वास रखती है। पिछली सरकार ने लोगों को बरगलाया कि वे उनके बिजली के बिल माफ कर देगी। पांच साल तक उनका राज रहा लेकिन उन्होंने बिजली के बिल माफ नहीं किए। पिछली सरकार ने लोगों को खूब मुर्ख बनाया लेकिन हमारे वित्तमंत्री जी ने पूर्ण ढके-छुपे शब्दों में इस बारे

[श्री खैराती लाल शर्मा]

में कहा है। मैं उनकी लाईनें पढ़कर सुनाता हूं। उन्होंने कहा है कि "वर्तमान सरकार समझौते और बातचीत की नीति में विश्वास रखती है। सरकार ने किसानों के बिजली के बकाया बिलों के संवेदनशील मुद्दे के समाधान के लिये, मेरी अध्यक्षता में (मेरी यानि उनकी अध्यक्षता में) एक समिति गठित की है। हमारी सरकार सत्ता के विकेन्द्रीकरण के सिद्धांत में विश्वास रखती है। ग्राम विकास समितियों जैसी असंवैधानिक संस्थाओं को भंग करके पंचायती राज संस्थाओं जैसी संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्ता बहाल की गई है"। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ मैं यह भी बताना चाहता हूं कि वित्त मंत्री जी कुरुक्षेत्र में बताकर आये हैं कि किसानों के बकाया बिजली के बिलों की किस्तें बना दी जायेंगी। जो भी किसान अपने बिल की एक किस्त का भुगतान करेगा उसकी एक किस्त उसके साथ माफ कर दी जायेगी। अध्यक्ष महोदय, यह प्रैक्टिकल बात है और बड़े सुचारू ढंग से की जाने वाली बात है। इस स्कीम से किसानों को माफी भी मिलेगी और समस्या का भी समाधान होगा। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ वित्तमंत्री जी ने कुरुक्षेत्र में एक और बात यह भी कही थी कि कोई किसान यदि यह कहे कि हमने तो पहले सारे बिल भरे हैं तो हमें तो बिल भरने का जुर्माना हो गया। इस बारे में वित्त मंत्री जी ने यह माना था कि जिन्होंने बिल भरे हैं उनको भी कंसीडर करके उनकी भरपाई की जायेगी। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है जबकि पिछली सरकार सिर्फ एनाउंसमैंट्स करती थी, उन्हें पूरा नहीं करती थी जबकि हमारे वित्तमंत्री जी ने पूरा करके दिखा दिया । अध्यक्ष महोदय, अब मैं सतलुज यमुना लिंक नहर के बारे में बात करना चाहूंगा जो कि हमारी सिंचाई नीति का केन्द्र बिन्दु हैं। अध्यक्ष महोदय, सिंचाई की बात पिछले अधिवेशन में भी चली थी। जो सबसे बड़ी बात हमारे इलाके की है वह यह है कि हमारे इलाके शाहबाद को दादूपुर-नलवी नहर ट्रीट करती है। पिछले अधिवेशन में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भी इसकी चर्चा की गई थी कि शाहबाद के इलाके से दादूपुर-नलवी नहर गुजरती है। अभिभाषण में कहा गया था कि उनकी सरकार की यह प्रतिबद्धता है कि इस नहर को वह बनवायेगी। स्पीकर सर, इसके लिए टाइड बान्ध बनाने की भी बात थी। हालांकि अभिभाषण में पूरी तरह से उसका जिक्र नहीं किया गया है। परन्तु मैंने दादूपुर नलवी नहर के लिए न्यू एक्सपैंडिचर में देखा है उसमें लिखा है कि Dadupur-Nalwi irrigation scheme, an amount of Rs. 43.04 crores has been proposed for 2005-2006. This also includes establishment expenditure of Rs. 11.04 crores. स्पीकर सर, इसके लिए यह सरकार बधाई की पात्र है। इस स्कीम के लिए वर्षों से केवल घोषणाएं ही घोषणाएं होती चली गई और हर कोई इस नहर को बनाने की बात कहता रहा, हमें लालीपॉप देता रहा तथा हम लोग देखते रहे। पहली बार यह योजना अमल में आ रही है और हमारी सरकार ने इसको अपने प्लान में लिया है। अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में मैं थोड़ी सी बात कहना चाहता हूं। इसका पहला जो ओरिजनल ऐस्टिमैटस बना था वह 167 करोड़ रुपये का था। अब इसके बारे में लिखा हुआ है कि इसके टैण्डर लगाए जा चुके हैं और भुगतान चालू कर दिया गया है। मैं इनसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है ? इसमें शुमार किया गया है और किसी जगह पर भी कहीं एक एकड़ का भुगतान हुआ है, इसमें केवल ऐसा लिखा हुआ है इसके अन्दर वास्तव में कुछ किया हुआ नहीं है। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मन्त्री महोदय से एक बात कहना चाहूंगा कि अगर इसमें से ऐस्टेब्लिशमैंट का खर्चा निकाल दिया जाए तो यह 32 करोड़ रुपया बचता है। मेरे हिसाब से यह 32 करोड़ रुपये इस स्कीम के लिए थोड़े कम हैं। मेरी यह गुजारिश है कि इस

पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए और यदि इसको जल्दी से जल्दी कम्पलीट करना है तो इसके बजट को थोड़ा सा और बढ़ाएं। माननीय मुख्यमन्त्री तथा वित्तमन्त्री महोदय से मेरी यह अपील है कि इस पर जरूर गौर फरमाएं। अध्यक्ष महोदय, जहां तक राज्य के प्रत्येक जिले में मॉडल स्कूलों को खोलने की बात का सम्बन्ध है, इन्दौरा साहब कह रहे थे कि तीन करोड़ रुपया खर्च किया गया है। यदि उन्होंने यह किताब लेकर पढ़ा होता तो उनको जवाब मिल गया होता। इसका जवाब इसमें लिखा हुआ है। मॉडल स्कूल खोलने के साथ ही साथ उन्होंने लिखा हुआ है। मॉडल स्कूल सब जगह पर हैं, इसमें इसका पूरा ब्यौरा दिया हुआ है। ये कह रहे हैं तीन करोड़ रुपये का स्कूल बनाया गया है। मैंने सारा भाषण पढ़ कर देख लिया है इसमें कहीं पर यह नहीं लिखा है कि तीन करोड़ रुपये के स्कूल की एनाउंसमैंट वित्त मन्त्री महोदय ने की है। इसमें यह लिखा हुआ है कि One such school at Panchkula started functioning from 2003-2004 academic session. It is proposed to set up 18 model schools. One school of each district will get @ Rs. 15.00 lacs for furniture and setting up of computer lab and to provide infrastructure thereof. यानि की कम्प्यूटर लैब और फर्नीचर के लिए यह राशि रखी गई है। मॉडल स्कूलों को शेप देने के लिए मेरे ख्याल से यह बहुत राशि है लेकिन यह इन्हें पता नहीं है कि जो तीन करोड़ रुपये की राशि है यह सारे स्कूलों के लिए हैं और उन्होंने इसे सारे स्कूलों की बजाए एक स्कूल के साथ जोड़ लिया और इसके बारे में कहना शुरू कर दिया । स्पीकर सर, स्वास्थ्य सेवाओं की बात बहुत बड़ी बात है। यहां पर इसका भी पूरा ब्यौरा दिया गया है। स्पीकर साहब, मैंने पहले भी रिक्वैस्ट की थी। हमारी हैल्थ मिनिस्टर साहिबा बैठी हुई हैं। मैंने उनसे भी और वित्तमंत्री जी जब कुरूक्षेत्र गए थे उनसे भी तब रिक्वैस्ट की थी। पिछले 7-8 सालों से हम अस्पतालों के आधुनिकीकरण की बात कर रहे हैं, आधुनिक उपकरण प्रोवाईड करने की बात कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारे ठोल गांव में पिछले 10 सालों से हॉस्पिटल की बिल्डिंग बना रखी है। स्पीकर सर, वहां के लोग हर सरकार के वक्त में कहते हैं कि बिल्डिंग हमने बना दी और जगह भी दे दी है। मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि अगर यह सरकार वहां पर थोड़ा सा सामान और एक डाक्टर दे दे तो आपकी बहुत ही मेहरबानी होगी। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्री जी ने कहा है कि 40 हजार की आबादी पर ही प्राईमरी हैल्थ सैन्टर खोल देंगे तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि पिछली सरकारों के वक्त से हमारी यह मांग रही है और आज की सरकार से भी हमारी मांग है कि वहां पर अगर कोई कमी है तो थोड़ी सी रिलैक्सेशन दे दें। वहां पर लोगों की पिछले 10 सालों से पी०एच०सी० बनवाने की मांग है और लोगों ने वहां पर बिल्डिंग भी बनवा रखी है। अगर वहां पर थोड़ी बहुत आबादी कम है तो इसमें उन लोगों का क्या कसूर है ? मेरा हैल्थ मिनिस्टर से निवेदन है कि सरकार अपनी नीतियों में ढील देकर लोगों की इस मांग पर गौर करे।

स्वास्थ्य मंत्री (बहिन करतार देवी) : शर्मा जी, वहां पर हम सब-सैन्टर खोल देंगे।

श्री खैराती लाल शर्मा : मंत्री जी, आपके आश्वासन देने का बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी, आप बहुत ही लिबरल हैं और बहुत ही अच्छे मूड में हैं। मेरी एक बहुत ही पुरानी डिमान्ड है और आप आज देख ही रहे हैं कि जी०टी० रोड पर आज इण्डस्ट्री किस तरह से पनप रही है। आपने तो यह डिसाइड किया है कि गांवों के इन्टीरियर में भी इन्डस्ट्री खोलेंगे और वहां के लोगों को पूरी सुविधा मिलेगी। लेकिन स्पीकर सर, मेरी कांस्टीचुएंसी एक ऐसी कांस्टीचुएंसी है जिसको जी०टी० रोड़ पर होते हुए भी आज तक इन्डस्ट्रियल टाऊन डिक्लेयर नहीं किया गया है। आज

[श्री खैराती लाल शर्मा]

मुख्यमंत्री जी मूड में दिख रहे हैं और मुझे लगता है कि आप मेरी दूसरी डिमाण्ड भी पूरी कर देंगे।

(इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए)

उद्योग मंत्री (श्री लक्षमण दास अरोड़ा) : शर्मा जी, आप जो हुक्म करेंगे हम वैसा ही कर देंगे।

श्री खैराती लाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया और वित्तमंत्री जी तथा मुख्यमंत्री जी को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा बजट पेश किया है। अब यह बजट किसी के समझ में नहीं आए और अगर कोई इसको बुरा कहता रहे तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। जिसकी समझ में आएगा तो वह इसको बहुत ही बढ़िया कहेगा। डिप्टी स्पीकर सर, इसके साथ ही मैं सरकार को इस बजट को पेश करने के लिए बधाई देता हूं और अपना स्थान लेता हूं। जय हिन्द।

श्री राम कुमार गौतम (नारनौंद) : डिप्टी स्पीकर साहब, वित्तमंत्री जी ने बजट को संवारने की कोशिश की है लेकिन उनकी यह कोशिश बहुत ही मामूली सी कोशिश है। जितने दिन हरियाणा में ओम प्रकाश चौटाला का राज रहा है उसके बारे में हमारे कांग्रेस के भाई, हम भी और हरियाणा की सारी जनता यह महसूस करती है कि ओम प्रकाश चौटाला ने हरियाणा को बुरी तरह से रौंदा है, बहुत ही बुरी तरह से बर्बाद किया है लेकिन इस बजट में कोई ऐसी बात दिखाई नहीं देती और न ही 100 दिन की इस सरकार की मंशा झलकती है कि इस सरकार ने यह किया है। इन्होंने एक भी कदम उस लाईन पर चलाया हो, जो इन्होंने चुनाव से पहले कहा था तो आप मुझे बताएं। क्रप्शन जहां थी, ज्यूं की त्यूं ही है। तहसील में थानों में और सभी दफ्तरों में ज्यूं की त्यूं ही क्रप्शन आज भी है। वही पीले कार्डज हैं और वही गुलाबी कार्डज हैं। कोई फर्क आया हो तो आप मुझे बताएं। यह ठीक है कि कई अच्छी बातें इस सरकार ने की हैं मैं उसकी तारीफ भी करता हूं। यह नहीं कि विरोधी हैं तो विरोध ही करेंगे। अच्छी बात की हम तारीफ भी करते हैं। (विघ्न) चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी मेरी बात सुन रहे हैं मैं इनको बताना चाहूंगा कि आज बिजली की समस्या ज्यों की त्यों ही है। डिप्टी स्पीकर सर, एक बात मैं आपके माध्यम से सदन में बताना चाहूंगा कि हमारे जो बहुत ही नजदीकी रिश्तेदार थे, हमारे जो वर्षों से चाहने वाले थे, उन्होंने भी हमारे को वोट नहीं दिए। ये कहते थे कि इस बार कांग्रेस की हकुमत आएगी और कांग्रेस की सरकार औथ लेते ही हमारे को नौकरी में ले लेगी। इन्होंने पहले बार-बार कहा था कि पिछली सरकार ने 27 हजार कर्मचारी नौकरी से निकाल दिए। मैंने पिछले सैशन में भी उस समय कहा था कि बहुत खुशनुमा माहौल है आप इनको वापस नौकरी पर ले लो। लोगों ने इसके बाद मुझसे कहा कि आपने तो शुरू में ही हुड्डा साहब की तारीफ करनी शुरू कर दी। मैंने उनसे कहा कि वह फ्रीडम फाईटर का पोता है उसके दादा फ्रीडम फाईटर रहे हैं वह बड़ी लड़ाई लड़कर आया है इसलिए मैंने क्या गलत कहा है ? मैंने तो उसी दिन कहा था कि इतना खुशनुमा माहौल है इसलिए आज एक फैसला होना चाहिए कि जिनके घरों में चूल्हे नहीं जल रहे हैं जो लोग एम०आई०टी०सी०, कोनकॉस्ट या पुलिस विभाग से निकाले गये हैं उनको फिर से नौकरी पर लेने के लिए आज ही घोषणा होनी चाहिए और कोई समय इसके लिए निश्चित होना चाहिए। लेकिन अभी तक भी सरकार ने इस बारे में कलम नहीं टेकी । इसके लिए कोई न कोई तो समय निश्चित होना चाहिए। इसके अलावा क्लीन एंड बेनेवैलेन्ट गवर्नमेंट यानी स्वच्छ और कल्याणकारी शासन की बात की जा

रही है लेकिन एक बात मुझे बताओ कि अगर इन्होंने स्वच्छता की तरफ एक कदम भी बढ़ाया हो तो आप मुझे बताएं। आप बताएं कि करप्शन कहां खत्म हुआ ? करप्शन तो आज भी यूं का यूं ही है। उपाध्यक्ष महोदय, ओम प्रकाश चौटाला ने जिस तरह से प्रदेश की सारी नदियों पर कब्जा कर लिया था, सारे पहाड़ों पर कब्जा कर लिया था और सारी खानों पर कब्जा कर लिया था तो वैसी की वैसी पोलिसी आज भी हैं यूं ही सारा अमला-असला है, इसमें बाल भी फर्क नहीं हुआ हैं। मुझे बताएं कि सरकार ने इस बारे में क्या किया है ? क्या सरकार ने इस बारे में कोई व्हाईट पेपर जारी किया है ? इसलिए सरकार बताएं तो सही कि उसने किया क्या है ? (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, हरिजन भाईयों ने, बैकवर्ड क्लासिज के भाईयों ने एवं 36 बिरादरी के भाईयों ने कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने में गजब कर दिया लेकिन सरकार ने हरिजन भाईयों के लिए बजट में केवल 51 करोड़ रुपये रखा है जबकि बैकवर्ड क्लासिज के भाईयों के लिए न के बराबर पैसा रखा है और इकोनोमिकली वीकर भाईयों के लिए बजट में कोई पैसा रखा ही नहीं गया है। मुझे बताएं कि सरकार ने इनके लिए कौन सी ऐसी बात की है जिसको हम यहां पर कहें ? अगर ये ओम प्रकाश चौटाला को हथकड़ी लगाकर लाते या उसकी सारी जायदाद कुड़क कर देते तब तो सारे लोग इनके गीत गाते और ये सारे भाई भी खुश हो जाते लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। यहां पर तो सब कहते हैं कि चौटाला ने यह कर दिया वह कर दिया। अरे चौटाला ने तो कर दिया लेकिन सरकार ने इन सौ दिनों में क्या किया ? उपाध्यक्ष महोदय, सब जानते हैं कि चौटाला ने नाश कर दिया लेकिन इन सौ दिनों में आपने एक कदम भी नहीं उठाया। उपाध्यक्ष महोदय, पिछली बार जो 80 एम०एल०एज० के लिए बजट था वह 10 करोड़ 21 लाख 37 हजार रुपये का था और दस मंत्रियों के लिए 11 करोड़ 15 लाख 44 हजार रुपये का बजट था अब यह बजट बढ़ाया गया है। पहले मंत्रियों का डिसक्रिशनरी कोटा 1.52 करोड़ रुपये था और अब की बार मंत्रियों का डिसक्रिशनरी कोटा 3.43 करोड़ तक बढ़ा दिया गया है। 80 एम०एल०एज का पहले बजट 10 करोड़ 21 लाख 37 हजार था इस बार इसको 12 करोड़ 18 लाख 35 हजार किया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रियों के पिछली बार दो करोड़ रुपये बढ़ाये थे और अब कि बार साल करोड़ रुपये से इकट्ठे ही 11 करोड़ रुपये बढ़ा दिए गए। (विघ्न) मेरा कहने का मतलब यह है कि एम०एल०एज० की ग्रांट भी होनी चाहिए। पंजाब में 40 लाख रुपये और दिल्ली में 70 लाख रुपये एम०एल०एज० को ग्रांट दी जाती है । हुड्डा साहब, आप बड़े प्यारे आदमी हो इसलिए आप आज ही इस बारे में अनाउंस करें क्योंकि आज एम०एल०ए० को कोई पूछता नहीं है ये बेचारे लांडे बुचे हांडे गामा में, कोई पूछता नहीं है। इनकी ग्रांट कम से कम चालीस या पचास लाख रुपये तो होनी ही चाहिए। एम०पी० को भी दो करोड़ रुपये की ग्रांट मिलती है इसलिए एम०एल०ए० के लिए चाहे आप 50 लाख रुपये दें या एक करोड़ रुपये दें लेकिन कुछ न कुछ तो आप अनाउंस करें। (विघ्न) मेरे कहने का मतलब यह है कि आज की यह सरकार बड़े चाव से आयी है, लोगों ने बहुत प्यार से इसको चुना है इसलिए इनको कुछ न कुछ तो करके दिखाना चाहिए । मैं तो ईमानदारी से कहता हूं कि जिस तरह से चौटाला साहब को लोगों ने डले मारे, अगर आपने भी कुछ नहीं किया तो आपको भी कुछ दिन बाद उसी तरह से लोग मारेंगे। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : आपका टाईम खत्म हो गया है। अब आप बैठिये।

श्री नरेश मलिक : उपाध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष जी की बात साबित होने लग रही है कि चौटाला साहब को प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरा देश इतनी गाली देने लग रहा है कि हम सारे तो मर लेंगे लेकिन चौटाला नहीं मरेगा।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है, अब श्री धर्मबीर गाबा जी बोलेंगे।

श्री धर्मबीर गाबा (गुड़गांव) : उपाध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया। पहले महामहिम का अभिभाषण और उसके बाद वित्त मंत्री का भाषण ये दोनों हमारे लिए ऐसे अक्ष होते हैं, आईना होते हैं कि गवर्नमैंट क्या पॉलिसी अख्तियार करने जा रही है, क्या बजट होगा, कितना पैसा डिवैलपमैंट के लिए रखा जाएगा यह सारा आइना होता है इसलिए हम इस पर डिसकस करते हैं। सरकार को इस बात की प्रायोरिटी देनी चाहिए कि जहां पर पैसा कम है वहां पर वह इसे बढ़ाये । बजट में यह भी आइना होता है कि गवर्नमैंट की क्या पॉलिसी रहेगी । लोगों की भलाई के क्या काम किये जाएंगे, इस बात का सबूत बजट होता है। मैं समझता हूं कि वित्तमंत्री जी को इसके लिए गाईडैंस भी मिली है और डैडीकेशन भी पूरी है एवं कैपेबिलिटी भी है। आज इन्होंने जो बजट पेश किया है उसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिन पर मैं वित्तमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं और साथ ही सुझाव भी देना चाहता हूं। सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूंगा कि जो फाइनैंस मिनिस्टर साहब ने बजट में प्रोविजन रखी है चाहे वह एजूकेशन के लिए है, चाहे ट्रांसपोर्ट के लिए है, प्लान जो 3 हजार करोड़ की है, उसमें से 45 परसैंट पैसा सोशल ऐक्टीविटीज के लिए रखा है। 2003-04 में 1024 करोड़ रुपया इस काम के लिए रखा गया था लेकिन अब 2180 करोड़ रुपया रखा गया है। यह भलाई का काम है। ऐग्रीकल्चर और रूरल डिवैलपमैंट के लिए 636 करोड़ रुपया रखा गया है। उपाध्यक्ष महोदय, एक बात मैं कहना चाहता हूं। हम कहते हैं कि अमेरिका में सड़कें ठीक हैं और अमेरिकन यह कहते हैं कि हम अमीर इसलिए हुए हैं कि हमारी सड़कें अच्छी हैं। सड़कें ठीक हों तभी इकोनोमी बढ़ती है, मंडियों में एप्रोच होती है, इंकम बढ़ती है, मुल्क खुशहाल होता है इसलिए मैं समझता हूं कि जितनी प्रायोरिटी आप ट्रांसपोर्ट और रोड्स को दे रहे हैं इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। चुनाव के समय हमने बहुत बड़े-बड़े नारे लगाए थे। आज मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं और विपक्ष के साथियों को बताना चाहता हूं कि ये जो गुड़गांव में सरकार द्वारा अधिगृहित की जाने वाली जमीन के मुआवजे की 15 लाख रुपये की बात करते हैं कि 15 लाख रुपये मिलते हैं मैं विपक्ष के साथियों को बताना चाहूंगा कि आपने घर जलते देखे हैं। हमारा घर जला है आपने सिर्फ तपिश महसूस की होगी लेकिन जले तो हम है। इससे बड़ा अनर्थ और कोई नहीं हो सकता कि कॉल सैंटर्ज के अंदर लोगों को पीटा जाए कि हमारी ही टैक्सी रखो नहीं तो और टैक्सी नहीं रख सकते। गुड़गांव के अंदर हालत यह हो गई कि एक घास काटने वाला ठेकेदार भी उन्हीं का आदमी होगा। यह हालत कर दी थी। आप हलवाइयों से जाकर पूछो। जो बड़े-बड़े हलवाई हैं उनके मुंह पर मिठाई का डिब्बा मारा जाता था कि यदि मिठाई खिलानी है और सही भाने में मिठाई देनी है तो डिब्बे को नोटों से भरकर लाओ। इंदौरा साहब जाकर पता कर सकते हैं गुड़गांव में शाम स्वीट्स है और ओम स्वीट्स है, मैं नाम बता रहा हूं। आप उनसे जाकर पूछ लेना कि कितने लाख रुपये उन्होंने दिए हैं। मैं बाकायदा नाम बता रहा हूं। आप 15 लाख रुपये की बात कर रहे हैं। दूसरी जो हमारे को फैसिलिटीज मिली है वह टोटल मिलाकर 22 लाख रुपया बनता है हम किसान से वायदा करके आए थे कि अगर कांग्रेस की हकुमत आती है तो कांग्रेस आपको दिल्ली के मुकाबले में जमीनों का कम्पनसेशन देगी। दिल्ली में 25 लाख रुपया मिलता है और हम हरियाणा में 22 लाख रुपये मुआवजे दे रहे हैं। इससे गुड़गांव का किसान तो बहुत खुश है। यह बात मानकर चलनी पड़ेगी कि हमने वायदा किया था कि हम आपको भय-मुक्त शासन देंगे, क्या आप समझते हैं कि आज ऐसा नहीं है ? आप गलत कहते हैं। आज हम भयमुक्त न होते तो जितनी जोर से बात आज हम कह

रहे हैं कह नहीं सकते थे। आज लोग सड़क पर भी ऐसे ही कहते हैं । ये बात ठीक है कि अभी थोड़ा वक्त और लगेगा। मैं फाइनैंस मिनिस्टर महोदय से अपील करना चाहता हूं कि वित्तमंत्री जी, मैंने आपका बजट देखा है उसमें 40 लाख रुपये पुलिस मॉडर्नाइजेशन के लिए रखे गये हैं। मैं आपसे दरखास्त करता हूं कि जब तक आप पुलिस को पी०सी०आर० नहीं देंगे। तब तक बात नहीं बनेगी आज हर डिस्ट्रिक्ट में चाहे वह फरीदाबाद हो या गुड़गांव उसमें जब तक आप नये थाने नहीं बनाते हैं, नये पी०सी०आर० नहीं देते हैं और 50-50 या कहीं पर 150 पुलिस वाले नहीं देते हैं तब तक बात बननी मुश्किल है। अगर ये चीजें आप कर देते हैं तो यह दो महीने में ही सब ठीक हो जायेगा। इस चीज की बड़ी सख्त जरूरत है। क्योंकि गुड़गांव एक बढ़ता हुआ प्राकृतिक शहर है इसलिए उसको आज नये थानों की जरूरत है। चाहे पालम विहार हो, चाहे सैक्टर 56-57 हो, वहां पर आज इस चीज की बहुत जरूरत है। मेरी आपसे दरखास्त है कि इस पर आप गौर जरूर कीजिए, यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा आज हमारे लिए जिन्दगी और मौत का एक और जो सवाल है वह है वाटर सप्लाई। मैं धन्यवाद करता हूं सी०एम० साहब का जिन्होंने वहां पर दूसरे ट्रीटमेन्ट प्लांट का उद्घाटन किया है 28 तारीख को। अगर हमें 20 मिलियन गैलन पानी मिलता रहेगा तो हमें आशा है कि जो पानी हमें मिलता था वह 40 मिलियन गैलन हो जायेगा जिससे उस इलाके के लोगों की पानी की समस्या दूर हो जायेगी। वह पानी तभी मिलेगा जब कैप्टन साहब, अगर आप उस नहर को 80 क्यूसिक पानी देंगे। अगर इतना पानी नहीं देंगे तो यह बेकार हो जायेगा। हमारी पार्टी ने लोगों से वायदा किया था कि 200 लीटर पर कैपिटा पानी देंगे। उसके लिए अगर आप हमें इतना पानी देते हैं तो कम से कम हम लोगों से यह तो कह सकते हैं कि कम से कम 100 लीटर पर कैपिटा पानी तो उनको मिल ही जायेगा। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है और यह बात मैं फख्र से कहना चाहता हूं कि दो चीफ मिनिस्टर साहब बनने के लिए चुनाव लड़ते है जिन्होंने चुनाव में करोड़ों रुपये खर्च किए वह चुनाव हार जाता है और आज विधानसभा में शक्ल दिखाने के काबिल भी नहीं हैं जबकि एक ऐसा चीफ मिनिस्टर है जो यह कहता है कि एक पैसा किसी से भी नहीं लूंगा क्योंकि मेरा खर्चा नहीं है। वह यह कहता है कि मैं मुनादी भी नहीं करूंगा। सबसे बड़ी बात जो इन्होंने की वह यह कि इस भले आदमी ने किसी से एक पैसा नहीं लिया और उसके बाद भी एक अच्छे मार्जिन से रिकार्ड से चुनाव जीत कर आये। जिसने करोड़ों रुपये खर्च किए वह हार गया। यह फर्क है सोच का, यह फर्क है पर्सनैलिटी का। आज इस सदन में ऐसा बजट पेश हुआ है जिसमें प्लानिंग के लिए तीन हजार करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है। उसमें भी उन्होंने प्रायोरिटी दी है सोशल वर्क को वाटर सप्लाई को, रोड को, ट्रान्सपोर्ट को। लेकिन एक होम महकमा ऐसा है जिसको आप नजर अन्दाज नहीं कर सकते क्योंकि आप सब, सी०एम० साहब और हम सभी जनता से वायदा करके आये हैं कि हम जनता को भयमुक्त हकुमत देंगे लेकिन जब तक प्रदेश की पुलिस को नई टैक्नॉलोजी के साथ, ट्रान्सपोर्ट के साथ हथियारों से लैस नहीं करेंगे तब तक ऐसा संभव नहीं होगा जो पैसा इसके लिए बजट में रखा है क्या यह पैसा सैफीशियंट है ? तब तक हम वह बात पूरी कर नहीं सकते जिसका वायदा हम जनता से करके आये हैं। यह मेरी आपसे रिक्वैस्ट है।

मैं एक बात और जरूर कहना चाहूंगा कि जो 80 और 90 करोड़ रुपये अर्बन डिवलपमैंट के लिए रखे हैं उसमें हर साल 18 करोड़ रुपये लगाने का प्रावधान है। क्या आप समझते हैं कि इतने पैसों में जो 80 म्युनिसिपल कमेटीज हैं उनका डिवलपमेंट हो जायेगा? आप डिवलपमेंट भी चाहते हैं लेकिन पैसा भी पूरा नहीं रखना चाहते। चाहे अर्बन डिवलपमेंट हो, चाहे पंचायत हो, चाहे

[श्री खैराती लाल शर्मा]

म्यूनिस्पिल कमेटीज हों वे ऐसे इन्टीच्यूशंज हैं जो मैं समझता हूं कि डैमोक्रेशी की बुनियाद हैं इसलिए इनको डिवैलप करने के लिए आप पैसा दीजिए। 80 म्यूनिस्पिल कमेटीज में 18 करोड़ रुपये से कुछ नहीं बन पायेगा। आज सबसे बड़ी दिक्कत अबर्न एरियाज के अन्दर है तथा क्योंकि मैं और सदस्य भी ऐसे ही कांस्टीच्यूंशी को रिप्रैजंट करते हैं इसलिए हमें पता है कि आज सबसे बड़ी दिक्कत वहां सीवर की है इसके जो पुराने पाईप हैं उनको बदलना है। जब तक पैसे नहीं देंगे वे बदले नहीं जा सकते। उसके बाद रोड़ की बात आती है पानी के पाईप की बात आती है। मेरी आपसे एक और प्रार्थना है कि जो पब्लिक हैल्थ डिपार्टमैंट है इसको पैसा ज्यादा दिया जाए पब्लिक हैल्थ डिपार्टमैन्ट को पैसा देना बहुत जरूरी है क्योंकि शहरों में बहुत बुरा हाल है। मैं समझता हूं कि आपके डर से कुछ डिवैल्पमैंट अब जरूर हो रहा है लेकिन आज भी इसकी ओर ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इस ओर ध्यान दिया जाए। इरीगेशन के लिए भी बजट में बहुत पैसा रखा गया है। मेरी भी ऐज एम०एल०ए० चौथी टैन्योर है और हर बार हमने यह सुना है कि पानी का वितरण बराबर किया जाएगा लेकिन किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया। शायद यह पहली बार है कि हर हालत में यह काम हो रहा है कि पानी के वितरण में बराबर का हक सबको मिल रहा है। इसमें सबसे बड़ी खुशी की बात यह हुई कि बजट में लमसम 2200 करोड़ रुपये इरीगेशन के लिए रखे गए हैं। मेरी कैप्टन साहब से प्रार्थना है कि हरियाणा में जितनी नहरें हैं, वे कैपैसिटी से भी आधा पानी ले रही हैं इसलिए जब तक आप उनकी सफाई नहीं कराएंगे तब तक उनमें पानी पूरा नहीं आएगा और जब तक उनमें पूरा पानी नहीं आएगा तब तक टेल एण्ड तक पानी कैसे पहुंचेगा ? इसके बारे में आज हाउस में भी काफी शोर हुआ है। तब तक नहरें कैपेसिटी पूरी नहीं लेगी जब तक इनकी सफाई नहीं करवाएंगे इसके बाद ही टेल एण्ड तक पानी पहुंच पाएगा। इसलिए मैं कैप्टन साहब से कहना चाहूंगा कि इस काम को वे प्रायोरिटी पर लें। हमारे हरियाणा प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या पावर की है। मुझे खुशी है कि इस बार बजट में 1847.41 करोड़ रुपये पावर के लिए रखे गए हैं। पावर की आज बहुत जरूरत है। इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं। कि जो इंडस्ट्रीयल पोलिसी 6 जून को आई तो 6 जून को मुख्यमंत्री महोदय ने मारूति की दूसरी फैक्ट्री का फाउंडेशन स्टोन रखा। शर्मा जी भी बैठे हैं वे इसको गौर से पढ़े। इसमें इंडस्ट्री डिपार्टमैंट, गवर्नमैंट आफ हरियाणा ने 88 ऐसे प्वांयट और दिखाए हैं जिसमें इंडस्ट्री को वे डिवैल्प करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि इससे एक इंडस्ट्री जोन हरियाणा में हो जाएगा। कल ही शायद ट्रिब्यून अखबार में मुख्यमंत्री महोदय की स्टेटमैंट आई थी कि इंडस्ट्री लगाने के लिए हम लोगों को इन्वाइट करना चाहते हैं, हम इन्वैस्टमैंट चाहते हैं, हम हर हालत में इंडस्ट्रियल पीस चाहते हैं। खास तौर से गुड़गांव के बारे में लिखा हुआ था कि हम इंडस्ट्री पीस चाहेंगे ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा गुड़गांव में इंडस्ट्रीज एस्टेबलिश कर सकें। मैं समझता हूं कि सारे माहौल को देखकर एक अच्छा बजट रखा गया है चाहे इंडस्ट्रीज हो, चाहे इरीगेशन हो, चाहे पावर हो, चाहे एजूकेशन हो, चाहे अर्बन डिवैल्पमैंट हो या पंचायत डिपार्टमैंट हो, कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं जिसको टच न किया गया हो। मैं वित्त मंत्री महोदय से एक बात कहना चाहता हूं। जैसा कि बजट में भी कहा गया है। अगर सरकार इस पर अमल करती है तो यह भी एक इतिहास बन कर रह जाएगा कि ऐसा बजट कभी हरियाणा में पास हुआ था और हर हालत में यह फुल फलैज्ड तरीके से पास हो जाएगा। मेरी आपसे इतनी प्रार्थना है कि इस बजट में जो जो बातें कही गयी हैं उन पर जरूर अमल किया जाए। धन्यवाद।

चौ० धर्मपाल सिंह मलिक (गोहाना) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं हमारी सरकार की तरफ से जो बजट पेश किया गया है उसका अनुमोदन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मेरे से पहले सभी साथियों ने, बल्कि मैं तो यहां तक कहूंगा कि विपक्ष के साथियों ने भी कोई खास मुद्दे इस बजट की आलोचना के लिए नहीं दिए तथा डायरैक्टली और इनडायरैक्टली सभी ने बजट का समर्थन किया है। 100 दिन के हमारे कार्यकाल में आम आदमी यह महसूस करता है कि आज मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं बिल्कुल आजाद हूं और अपनी बात कह सकता हूं। जो पहले चौटाला साहब के राज में घुटन महसूस करते थे वह घुटन आज नहीं है। कहते हैं कि जब शुरू में आजादी मिली,उस समय हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री स्वर्गीय पण्डित जवाहर लाल नेहरू किसी गांव में गये थे, वहां उन्हें एक साधारण आदमी मिल गया। उस साधारण आदमी ने प्रधानमंत्री जी से पूछा कि कहते थे आजादी मिलेगी, क्या आजादी मिल गयी ? नेहरू जी ने कहा कि भैया यही तो आजादी है कि आप अपनी बात बोल रहे हो और देश के प्रधान मंत्री से बात कर रहे हो। इसी तरह से हमारी सरकार में सभी को अपनी बात कहने का हक है और सभी लोग खुश हैं। उपाध्यक्ष महोदय, कोई भी सरकार हो उसकी सबसे बड़ी दो बातों की जिम्मेवारी होती है। एक तो कानून व्यवस्था को ठीक करके जनता की जानमाल की हिफाजत करने की और दूसरी प्रदेश के नागरिकों को आगे बढ़ने के अवसर दिलाने की। ये दोनों बातें अब हम सबके सामने हैं। यदि इस समय चौटाला साहब यहां सदन में होते तो बहुत अच्छी बात होती और उनको यहां आना भी चाहिए क्योंकि आलोचना तो आदमी को ऊपर उठाने के लिए होती है। लेकिन मैं तो डाक्टर सुशील कुमार इंदौरा जी की बदकिस्मती मानता हूं कि चौटाला साहब यहां पर हैं नहीं और उनके ऊपर उनकी सरकार द्वारा की गई कारगुजारियों की बौछारें हो रही हैं। यदि चौटाला साहब यहां होते तो इंदौरा साहब बच जाते। उपाध्यक्ष महोदय, यह भी इनकी बहुत अच्छी बात है कि ये अपने नेता का पूरा बचाव करने में लगे हैं।

श्री सुखबीर सिंह (सोहना) : उपाध्यक्ष महोदय, डाक्टर इंदौरा साहब को संजय की भूमिका निभा रहे हैं। जिस तरह महाभारत में संजय युद्ध की सारी जानकारी धृतराष्ट्र को दे रहा था उसी तरह सदन की सारी जानकारी इंदौरा जी चौटाला साहब को देते हैं।

परिवहन मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : उपाध्यक्ष महोदय, डाक्टर इंदौरा जी एक इन-डिफैंसिव केस लड़ रहे हैं, ये यह भी जानते हैं कि ये यह केस लड़ने से पहले ही हार रहे हैं। लेकिन हम इनकी काबिलियत की दाद देना चाहेंगे कि ये बहुत काबिल वकील हैं। ये यह जानते हुए भी यह केस लड़ रहे हैं कि this is a lost case before it has even started.

डॉ० सुशील इंदौरा : उपाध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं कि जो हमने भुगता वह ये लोग न भुगतें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक मेरे साथी भुगतने की बात कर रहे हैं इस बारे में मैं सदन को बताना चाहूंगा कि भुगतने का तो इनके यहां रिकार्ड है कि किस तरह से पिछली सरकार के समय में मन्त्रियों को और विधायकों को तेजाखेड़ा फार्म हाउस पर ले जा करके उनके हाथ-पांव तोड़े जाते थे।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेरे विपक्ष के साथियों को आश्वासन देता हूं कि हमने पिछली सरकार के समय में जो भुगता था, वह अब विपक्ष के साथियों को नहीं भुगतना पड़ेगा। इनको बोलने के लिए पर्याप्त समय दिया जायेगा। अब ये चिंता न करें। जितना ये बोलना चाहें उतना बोल लें।

चौ० धर्मपाल सिंह मलिक : उपाध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार के विधायक चौटाला साहब को भगवान के बराबर कहते थे और डाक्टर इंदौरा जी ने तो उन्हें भगवान से भी ऊपर कहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सोनीपत जिले के उस समय के विधायकों की बात बताना चाहूंगा कि इनकी सरकार के समय में एक मास्टर इनके विधायक के पास गया कि मेरा तबादला करवाओ। वह विधायक विभागीय अधिकारियों के पास तबादले के लिए गया। अधिकारियों ने कहा कि तबादले तो बंद हैं और मुख्यमंत्री ही तबादला कर सकते हैं। मास्टर जी ने विधायक को कहा कि मुख्यमंत्री जी के पास चलते हैं। मैं विधायक का नाम नहीं लूंगा लेकिन उस विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री जी तो भगवान हैं और भगवान के पास जो कोई चला जाता है तो वह वापिस नहीं आता। (इसी) उपाध्यक्ष महोदय, यह ठीक है कि अपने नेता की प्रशंसा करो लेकिन प्रशंसा उस हिसाब से करो कि सुनने वाले को भी ठीक बात लगे। उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारी तो यह बदकिस्मती है कि चौटाला साहब यहां नहीं बैठे हुए और हम अपने दिल के अरमान उन्हें नहीं कह सकते तथा इंदौरा साहब, आपकी बदकिस्मती यह है कि जैसा रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने कहा कि आप ऐसा केस लड़ रहे हैं जिसके न तो फैक्टस सही हैं और न लॉ सही है। लेकिन मैं मुद्दे पर आना चाहता हूं। उपाध्यक्ष जी, माननीय चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी ने बजट पेश किया है। यह बजट बहुत ही सरल और सिम्पल बजट है, यह बजट ऐसा कम्पलीकेटिड बजट नहीं है जिसके अन्दर कोई उल्ट फेर हो। सीधे-साधे आम आदमी का जो बजट होता है उस किस्म का यह बजट है और केवल 51 करोड़ 67 लाख का मामूली घाटा इन्होंने दर्शाया है। इन्कम कैसे होगी, खर्च कैसे होगा यह सब इसमें दिया हुआ है। मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि माननीय ओपोजीशन के सदस्य किस ढंग से बजट का विश्लेषण कर रहे हैं और यह कह रहे हैं कि इसमें यह ठीक नहीं है इसमें वह ठीक नहीं है। इस बजट के अन्दर दोनों मद बहुत ही साफ तरीके से दिए हुए हैं। खर्च और आमदनी का भी इसमें पूरा ब्यौरा दिया हुआ है। बजट का दूसरा और कोई तरीका होता ही नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि किसी भी प्रदेश की तरक्की के लिए दो ही रास्ते हैं एक तो खेती और दूसरा उद्योग। इन दोनों को प्रोत्साहन देने के लिए इस बजट के अन्दर पूरे ढंग से पैसे का सिस्टम बनाया हुआ है। खेती के लिए जमीन को बढ़ाया नहीं जा सकता उसके लिए पानी के साधन की जरूरत है। पानी के बारे में मैंने 9 तारीख को कहा था। इन लोगों को इस चीज को महसूस नहीं करना चाहिए। कोई भी माननीय साथी कहीं से भी एम०एल०ए० बन कर आया हो जो लड़ाई हम 40 साल से पंजाब से लड़ रहे हैं वहीं लड़ाई हमें अपने हरियाणा के साथियों के साथ भी लड़नी पड़ रही है, यह कितनी बुरी बात है ? हम कहते हैं कि पंजाब हमारा बड़ा भाई है और हम छोटे भाई हैं उन्हें न्याय करना चाहिए लेकिन यहां पर अपने ही प्रदेश में हम लोग पानी के बराबर वितरण को लेकर ठीक ढंग से नहीं चल पा रहे हैं। प्रदेश का मुख्यमन्त्री प्रदेश की सरकार का मुखिया होता है और उसके लिए सारा प्रदेश बराबर होता है। अगर किसी हल्के से सत्तादल का एम०एल०ए० नहीं भी है तो भी उस इलाके के साथ उन्हें न्याय करना पड़ता है, यह उसकी ड्यूटी है। लेकिन इन्होंने इस बात को माना ही नहीं कि पानी के बंटवारे के अन्दर कोई भेदभाव है, कोई इम्बैलेन्स है। उपाध्यक्ष महोदय, कप्तान साहब बैठे हुए हैं मैं उनका धन्यवाद करता हूं। बार-बार अखबारों ने भी इस बात को दिया है कि इन्होंने इस चीज को माना है कि पानी के बंटवारे में भेदभाव हुआ है। यह भेदभाव थोड़ा सा नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं, कि अगर इसके फैक्टस देखें जाएं तो हैरानगी होती है कि जो टोटल पानी हमें मिलता है वह हमें एक तो मेन भाखड़ा लाईन से मिलता है और दूसरे हमें यमुना वाटर सर्विस सिस्टम से पानी मिलता है। कुछ ऐरिया में हमें लिफ्ट कैनाल से भी

पानी मिलता है। महेन्द्रगढ़, भिवानी, रिवाड़ी और गुड़गांव के एरियाज में जो भाखड़ा मेन लाईन सिस्टम की सप्लाई है वह हरियाणा का केवल 40% हिस्सा है, 60% हिस्से की सप्लाई यमुना वाटर सर्विसिज सिस्टम से है और यमुना वाटर सर्विस का पानी 60% भाग के लिए केवल 2.4 से 3.01 है। 60% हरियाणा की खेती की जमीन के लिए 2.4 से 3.01 है और 40% भूमि के लिए जो पानी अवेलेबल है वह 4.29% से 8.0 है, मतलब यह है कि 70% पानी का फर्क है। उपाध्यक्ष महोदय, अगर थोड़ा बहुत अन्तर हो तो बात समझ में आती है। 70% पानी का जो उनका हक है उससे ज्यादा पानी उनको जा रहा है लेकिन यहां पर पूरा पानी नहीं आ रहा है। इस इलाके के साथ भेदभाव है। जिस इलाके के साथ अन्याय है उस इलाके की जमीन भी थोड़ी है होल्डिंग भी छोटी है और पानी नहीं है। मैं तो यह कहूंगा कि हरियाणा में जो क्राईम बढ़ा है वह सरकारों ने जो ज्यादती की है, इस कारण से ही बढ़ा है। एक बी०ए० पास लड़के को अगर रोजी रोटी मिल जाए तो वह क्राईम नहीं करना चाहेगा। उनके लिए तो सारी चीज मजबूरी हो गई है। एक-एक एकड़ की होल्डिंग हो गई है। मंत्री जी ने इस इलाके के साथ एक नई लिंक कैनाल बनाने के लिए अपनी प्रपोजल तैयार की है। मैं समझता हूं कि कप्तान साहब बहुत जल्दी इस पानी को इस इलाके में लेकर आएंगे। बहुत सारा फर्क तो सरकार की मंशा से पड़ जाता है। आम आदमी को जब हम बताते हैं कि ये हालात थे तो वह अफसोस मनाता है कि हो क्या रहा था। मेरा कहने का मतलब यह है कि हमारे इलाके नहरों में 32 दिनों के बाद 16 दिनों की बजाए केवल 8 दिन ही पानी आता था और दूसरे इलाकों में 32 दिनों के बाद 16 दिनों की बजाए 24 दिन पानी आता था। इस सब के बावजूद वहां पर झगड़े होते थे। आज हमारे इलाके में जो मुख्य समस्या है वह टेल की है। मैं वहां के किसानों की बात खासतौर पर बता रहा हूं कि जितनी भी नदी नालों की टेलें हैं वहां पर रोज किसानों के झगड़े होते हैं। मेरी आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना है कि वहां पर ये यह सुनिश्चित करें कि पानी टेलों पर पहुंचे क्योंकि पानी की चोरी की वजह से टेलों तक पानी नहीं पहुंच पाता है उस पर भी चैक लगे। आप वहां से ब्यौरा मंगवा लें कि कितने केसिज ऐसे हैं जो पानी की वजह से झगड़े के कारण हुए हैं तो आपको ज्यादातर केसिज उन्हीं के मिलेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि कृषि की और उद्योगों की वजह से प्रदेश की उन्नति हो सकती है इसके अलावा कोई तीसरा साधन नहीं है। हम पार्लियामैंट में भी बहुत शोर करते थे कि बड़ी इन्डस्ट्रीज हरियाणा में लगाई जाएं। तो इस विषय में एक ही जवाब आ जाता था कि जो नैशनल कैपिटल रीजन है उसमें बड़ी इन्डस्ट्रिज नहीं लग सकती है। स्पीकर सर, राई में एक इन्टरनैशनल सब्जी मंडी बनाने का प्रस्ताव था उसके लिए जमीन भी एक्वायर हो गई थी और उसकी चार दीवारी भी हो गई थी। वहां पर 20 हजार लोगों को रोजी रोटी मिल सकती थी लेकिन हरियाणा में चौटाला साहब की सरकार आ गई । डिप्टी स्पीकर सर, छोटी-छोटी होल्डिंग के जो किसान हैं वे सब्जियां उगाते हैं। जो सब्जी हिन्दुस्तान में 50 रुपए किलो है उसके बाहर विदेशों में ड्राई एरिया होने की वजह से 500 रुपए किलो के दाम मिलते हैं। चौटाला साहब ने आकर एक ही लाईन में सारी बीमारी का इलाज कर दिया, जो दिल्ली की बीमारी थी, जो दिल्ली के रिहायशी इलाकों में छोटी-छोटी इण्डस्ट्रीज थीं जिनको हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिस देकर यह कहा था कि उन इण्डस्ट्रीज को दिल्ली से बाहर निकालो क्योंकि ये दिल्ली में पोल्यूशन फैलाती हैं, उनको चौटाला साहब ने हरियाणा में बुला लिया कि यह बीमारी हमको दे दो। उन्होंने वहां से उस मण्डी को कैंसिल करके इन इण्डस्ट्रीज को कहीं दो सौ गज का और कहीं पर तीन सौ गज का प्लाट दे दिया। डिप्टी स्पीकर सर, वह मण्डी भी गई और वहां पर इण्डस्ट्रीज भी नहीं लगी। यह तो

[चौ० धर्मपाल सिंह मलिक]

सरकार की मंशा की बात है कि वह किस ढंग से काम करेगी। लेकिन इस पांच साल के अर्से में यह नहीं है कि हम आलोचना के लिए आलोचना करना चाहते हैं। ये खुद अपने दिल पर हाथ रख कर देखें क्योंकि लोगों का फैसला कभी गलत नहीं होता है। एक आध केस में गलत हो सकता है। लेकिन पिछली सरकार का तो बुरी तरह से जनता ने सफाया कर दिया। यह आम तौर पर यूं ही नहीं होता है इसका कोई न कोई कारण जरूर होता है। (विघ्न) 1996 में हमारी ही कोई कमी रही होगी तभी हमारी सरकार नहीं आयी । विधायक जी, किसी भी घटना के बगैर ऐसी चीज नहीं होती है। मेरी भी कोई कमी रही होगी, मेरी सरकार की कोई कमी रही होगी, उसको आज हम छिपाएं और लोगों को बुराई दें कि लोगों का निर्णय गलत है तो ठीक नहीं है। जो डैमोक्रेटिक सैटअप की हाईएस्ट अथोरिटी है हम उनको गलत कैसे बता सकते हैं ? उनका निर्णय हमेशा सही होता है और हमें उनके निर्णय को मानकर चलना चाहिए । हमने तब भी उनके निर्णय को सिर माथे पर रखा था लेकिन आप तो आज भी नहीं मान रहे हैं और यहां पर बैठे-बैठे कुचर-पूचर करते रहते हैं। (विघ्न) हम तो खुद मानते हैं लेकिन आज भी इनके अंदर यह बात मानने की हिम्मत नहीं है कि ये चौटाला साहब की गलती को उसके सामने कह दें इसीलिए ये लोग मरे हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, जिस राजा से उसका डाक्टर या उसके दोस्त डरने लग जाते हैं उसका तो हमेशा नाश ही होता है क्योंकि डाक्टर या साथी तो उसको ठीक ही सलाह देते हैं। (विघ्न) हमारे एक भाई जिनका मैं नाम नहीं लूंगा पिछली बार विधायक थे। डांगी साहब भी उनको जानते हैं उनका हाथ तोड़ दिया गया था जब यह मुझे मिले तो मैंने कहा कि सुना है कि चौटाला साहब के लड़कों ने आपका हाथ तोड़ दिया है वह कहने लगे कि सुना तो मैंने भी है यानी उनकी यह हिम्मत नहीं थी कि वह कह दें कि मेरा हाथ तोड़ा गया है मतलब कहने का यह है कि उस समय कोई भी आदमी चौटाला से खुश नहीं था। ये लोग भी उस समय चुप रहते थे क्योंकि इनकी मजबूरी थी। आज भी इनकी मजबूरी है यह बात मैं मानता हूं। लेकिन इस सरकार में वह बात नहीं है आज हर एक आदमी को पूरा अधिकार है कि वह अपनी मर्जी से अपनी बात कहें। जो यह बजट पेश किया गया है यह बहुत ही सराहनीय है क्योंकि इसमें कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया गया है और ठीक ढंग से संतुलित करके विकास के लिए पैसा बढ़ाया गया है। किसी प्रकार का कोई विशेष घाटा इसमें नहीं दिखाया गया है और जो थोड़ा बहुत घाटा दिखाया भी गया है वह ऐडमिनिस्ट्रेशन को चुस्त दुरूस्त करके पूरा किया जाता है। कोई गलत बात बजट में नहीं कही गयी है। इसलिए मैं इस सरकार को, मुख्यमंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को इसके लिए मुबारिकवाद देता हूं। सारे हरियाणा में इस बात की बहुत ही बढ़िया प्रतिक्रिया आयी है। कि सरकार ने बहुत ही अच्छा बजट बनाया है। डिप्टी स्पीकर सर, मैं एजूकेशन के बारे में कहना चाहूंगा। मुलाना साहब यहां पर बैठे नहीं हैं। एजूकेशन में जो आज स्थिति है उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा । हम जब धन्यवादी दौरे पर जहां-जहां गए तो हमने देखा कि हर गांव में एक भी स्कूल ऐसा नहीं है जहां स्कूल में स्टाफ पूरा हो। यदि हम गलती टीचर्ज की बता दें तो फिर ठीक नहीं होगा। मेरे हल्के में शामड़ी गांव है यह बहुत बड़ा गांव है और इसमें तीन पंचायत है। इस गांव में एक प्लस टू का स्कूल है। जब हम इसमें गए तो हमने देखा कि उस स्कूल में केवल एक ही लैक्चरर है । जिस तरह से भेड़ बकरियों को रोके रखते हैं उसी तरह से उस स्कूल में बच्चों को वह लैक्चरर रोके रखता है। इसके बाद यदि हम यह कहें कि रिजल्ट खराब क्यों आया तो यह ठीक नहीं है। जिस प्रदेश में शिक्षा ठीक होगी, लोग शिक्षित होंगे वहां पर उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा इसलिए सबके लिए शिक्षा का प्रावधान करना हमारी ड्यूटी है। मेरी

शिक्षा मंत्री से प्रार्थना है कि प्राथमिकता के आधार पर स्कूलों में टीचर्ज नियुक्त होने चाहिएं। आई०ए०एस० या एच०सी०एस० में तो सिफारिश चल सकती है लेकिन डाक्टर्ज, इंजीनियर्ज या मास्टर्ज में कभी सिफारिश नहीं चल सकती है क्योंकि इनके हाथों में दूसरों की जानें होती हैं। जो आदमी खुद ठीक नहीं होगा तो उससे दूसरों को नुक्सान ही होगा। इसलिए हमारी शिक्षा को ठीक ढंग से आगे बढ़ाने के लिए बढ़िया किस्म के टीचर्ज की भर्ती करना जरूरी है। आज सारे स्कूलों की बिल्डिंग्ज खराब हैं उनके लिए भी बजट में जो प्रावधान किया गया है तो मैं समझता हूं कि उससे भी काफी सुधार होगा। इसी तरह से होस्पीटल्ज की बात है चाहे वेटैनरी होस्पीटल्ज हों या सिविल होस्पीटल्ज हों, उनमें भी डाक्टर्ज की कमी है। मैं एक जनरल बात कहना चाहता हूं क्योंकि जितने शहरों के नजदीक स्कूल्ज हैं या वैटनरी हॉस्पीटल्ज हैं, सिविल डिस्पैंसरीज हैं वहां तो सरप्लस स्टाफ है लेकिन जो शहर से दूर हैं वहां मास्टर नहीं है और डाक्टर नहीं हैं। इसलिए भर्ती के समय कोई न कोई कंडीशन इस किस्म की रखी जाए कि इतनी नौकरी तो देहात में करनी ही करनी है। हम मशरूम ग्रोथ की तरह स्कूल अपग्रेड करते जा रहे हैं आज से 15 साल पहले मैं इंग्लैंड में गया था। मैं उस समय वहां ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भी गया था। वहां मुझे इंडियन स्टूडैंट्स भी मिले जिनकी पुश्तें दो सौ साल पहले वहां माइग्रेट करके गई थीं। उन्होंने हमें बताया कि पिछले कई सालों से न तो हमने कोई नया स्कूल खोला है न कोई स्कूल अपग्रेड किया है। वे कहते हैं कि नया स्कूल इसलिए नहीं खोला क्योंकि आबादी नहीं बढ़ी। और अपग्रेड इसलिए नहीं करते हैं कि वे कहते हैं प्राइमरी एजूकेशन तो सबको मिले लेकिन हायर एजूकेशन केवल उन लोगों को ही मिले जो उसके काबिल हों। हम कन्वोकेशन में देखते हैं कि वहां गाउन पहनाते हैं। जो एम०ए० कर लेते हैं उनके लिए डिफरैंट ड्रेस है। इसका मतलब यह है कि यह आदमी बहुत बढ़िया है, चरित्रवान है अगर किसी गलत काम में फंस जाए तो उसकी डिग्री भी विदड्रा हो सकती है। कहने का तात्पर्य यह है कि एजूकेशन पर हमें यहां पर जोर देना पड़ेगा। तबादलों के लिए तीन महीने हो गए हैं लोग हमारे पीछे भाग रहे हैं हम उनको बहकाते हैं। वे पूछते हैं कि तबादले कब होंगे, अब हमने कह दिया है कि 20 तारीख के बाद होंगे। हम लोगों से पैंडा छुड़वाते फिर रहे हैं। ट्रांसफर के लिए हमें बाकायदा कोई न कोई परमानैंट पॉलिसी बनानी चाहिए वरना लोग हमसे नाराज होंगे। इसलिए भर्ती के समय यह कंडीशन जरूर लगाई जाए कि इतनी सर्विस कम से कम देहात में जरूर होनी चाहिए। वह नहीं होगी तो हमारे लिए परेशानी की बात आ जाएगी। इस बात के लिए सरकार बधाई की पात्र है कि किसानों के लिए सरकार ने जो वायदे अपने घोषणा पत्र में किए थे उनको पूरा करने के लिए सरकार ने शुरुआत की है। उस समय घोषणा पत्र बनाने वाली कमेटी में मैं भी मैंबर था। जो घोषणा पत्र में किसानों से वायदे किये थे, उनको पूरा करने के लिए सरकार ने शुरूआत की हुई है। उनमें से कुछ वायदे इम्प्लीमैंट हुए हैं जैसे ट्रैक्टर की रजिस्ट्रेशन फीस सरकार ने खत्म कर दी है। चौटाला साहब कहा करते थे कि मैं किसानों का चीफ मिनिस्टर हूं लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाए बल्कि उन्होंने वह फीस बढ़ा दी थी। हमारी सरकार ने आते ही वह फीस खत्म कर दी है। 1947 के बाद से मैंने किसी के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा चलता नहीं सुना है। अंग्रेजों के टाइम में तो केसिज प्रीवि कौंसिल तक जाते थे। 1947 के बाद मैंने तो कोई ऐसी रूलिंग नहीं देखी कि जहां किसी हिन्दुस्तानी पर राजद्रोह का मुकदमा चला हो, लेकिन चौटाला साहब ने अपने साथी जिनके कंधे पर ये बंदूक रखकर चलाते थे उनके खिलाफ ही देशद्रोह के मुकदमें दायर कर दिए। मान साहब यहां बैठे हुए हैं इनकी क्या गलती थी ? इनके खिलाफ भी पूरा तूफान खड़ा कर दिया और गलत मुकदमें बनाये गये। मेरा

[चौ० धर्मपाल सिंह मलिक]

कहने का तात्पर्य यह है कि किसानों के ऐसे-ऐसे केसिज थे कि ओलावृष्टि में मुआवजे में कितना पैसा मिला कि एक रुपया दिया था, उसमें से भी कह रहे थे कि 12 आने लौटा दो और चार आने ले जाओ तो यह हालात थी। यह ठीक है कि गिरदावरी करते वक्त नीचे के एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर छोटी मोटी कमी रह जाती है लेकिन यह सरकार आने के बाद किसानों की मुआवजे की राशि को बढ़ाया गया है। उनको मुआवजा मिला भी है। एक आध जगह कमी आई है। मेरी कान्सटीच्यूएंसी के गांव खानपुर, गामड़ी और चार-पांच दूसरे गावों में पटवारी की कमी पाई गई थी इसलिए उसको सस्पैंड किया गया। उसने क्या किया कि औलावृष्टि में गेहूं की फसल भी 50 प्रतिशत खराब और सरसों की फसल भी 50 प्रतिशत खराब दिखा दी जबकि सभी लोग जानते हैं कि सरसों की फसल पर तो एक ओला लगते ही सारी झड़ जाती है। इसलिए यह तो सैंट-परसेंट खराब हो गयी। इस तरह से यह क्लीयर जाहिर हो गया कि गिरदावरी गलत की गयी है। इसलिए एक दम एक्शन लिया गया और अब यह ठीक होने की उम्मीद है। बहुत सारी बातें हैं जैसे मॉडल स्कूल खोलने की बातें बहुत से साथियों ने कहीं है, मैं उनको रिपीट नहीं करना चाहता। लेकिन एक चीज मैं कहता हूं कि हमारी पापुलेशन के कन्ट्रोल के लिए हमें सोचने की जरूरत है। पापुलेशन की स्थिति इतनी गम्भीर है कि अगर इस को ढंग से नियंत्रित नहीं किया गया तो बड़ा नुकसान हो सकता है। मैंने आंकड़े देखे हैं। 1951 में हरियाणा की हमारी जनसंख्या को देखें तो एक किलोमीटर वर्ग एरिया में 128 आदमी रहते थे और आज 478 आदमी रहते हैं जबकि अमेरिका में 30 आदमी रहते हैं, कनाड़ा में 3 और चाईना जैसे देश में जिसे ज्यादा आबादी वाला देश कहते हैं, वहां 133 आदमी रहते हैं। आज हमारी जो प्रोग्रेस है, डिवलैपमेंट है उसको आबादी खा जाती है इसलिए विकास के साथ-साथ इस संबंध में भी हमें थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा कि देहात की जो जमीन है वह तो बढ़ नहीं सकती। लेकिन उसका इण्डस्ट्रिलाईजेशन किया जा सकता है। देहात की जमीन का इण्डस्ट्रिलाईजेशन होगा तो उससे वहां रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। जितना हम देहात में होस्पिटल और स्कूलों का दायरा बढ़ायेंगे उतना ही जो देहात के लोगों का पलायन शहरों की तरफ हो रहा है वह नहीं होगा। पलायन का कारण यह है क्योंकि देहात में वे फैसिलिटीज नहीं मिल पाती जो शहरों में मिलती है। अगर देहात का शहरों की तरफ पलायन रोकना है तो देहात में सारे इन्फ्रास्ट्रक्चर को तैयार किया जाये। देहात के लोगों को वे सारी फैसिलिटीज दी जायें जो शहरों में हैं ताकि बैलेंस बना रहे। इससे जो मुलाजिम शहर की तरफ दौड़ते है वे भी कम होगें इस तरह से टोटल पलायन रूक जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : मलिक साहब, वाईड अप कीजिए।

चौ० धर्मपाल सिंह मलिक : उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं अपनी कान्स्टीच्यूएन्सी की बात जरूर कहना चाहूंगा क्योंकि फिर पता नहीं बोलने का मौका मिले या न मिले। कई बातें हैं लेकिन सभी बातें सारे स्टेट से संबंधित हैं । लोग हमें कहते हैं, हम आपको बताते हैं इस तरह से ये बातें सरकार तक पहुंच जाती हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि गांव में आबादी में छोटे-मोटे झगड़े चलते रहते हैं चूंकि मैं तो वकील रहा हूं इसलिए मुझे पता है कि जिसके पास लाठी है वह जबरदस्ती गलबाड़े पर घर पर कब्जा कर लेता है और फिर कहते हैं कि सबूत क्या है कि जी सबूत क्या होगा हम तो कदें तैं यहीं रहा करते थे। उनका एक परमानैन्ट रिकार्ड आबादी देह है, उनके नक्शे हैं। चौधरी बंसीलाल जी जब पहले मुख्यमंत्री थे तब इन्होंने इस बारे एक कार्यक्रम बनाया था परन्तु वह फाईनल नहीं हो पाया। ऐसे कार्यक्रम को टाईम बाउंड प्रोग्राम किया जाये ताकि लिटीगेशन का काम

कम हो। देहात के आदमी के पास जमीन नहीं है उसके पास केवल एक घर है लेकिन वह उस घर को रहन नहीं रख सकता और इसलिए वह बैंक से लोन नहीं ले सकता क्योंकि उसके पास उस घर के कागजात नहीं है। सब आदमियों के पास एग्रीकल्चर लैंड नहीं होती वे लोन लेने के लिए बेचारे धक्के खाते हैं, बैंक वाले उन्हें एक्सप्लायट करते हैं कि तेरे कागज में यह कमी है, वह कमी है, तू ये ले आ, वह ले आ। इसलिए टाइम बाउंड प्रोग्राम करके 6 महीने के अन्दर सबकी अपील शपील निपटा दी जाएं। सबके हाउसिज के बकाया नक्शे बन जाएं और उस नक्शे की अटैस्टेड कापी जिस प्रकार से जमाबंदी, खसरा और गिरदावरी की कापी तहसील में होती है। उसी प्रकार इनकी कापी भी तहसील में, बी०डी०ओ० के दफ्तर में और गांव के सरपंच के पास हो ताकि सारी परेशानियाँ दूर हो सकें और ठीक ढंग से काम हो सके। अब रजिस्ट्री करवाते हैं तो गोल मोल करवाते हैं उनके न कोई एरिये का पता है और न उसका कोई खसरा नम्बर है ऐसे ही गाड़ी चल रही है। उपाध्यक्ष महोदय, हम बहुत दिनों से आस लगाए बैठे थे और आम आदमी भी यह समझता था कि एस०वाई०एल० कैनाल का पानी आएगा और गाड़ी चलेगी। लेकिन एस०वाई०एल० कैनाल के पानी ने लोगों को प्यासा मार दिया क्योंकि पानी आज तक नहीं आया। वह पानी आए, इसके लिए हमारी सरकार पूरे ढंग से कोशिश कर रही है और वह पानी मिलेगा। इसके साथ-साथ जो दूसरे साधन हैं जैसे और रजवाहे तैयार कराए जा सकते हैं, जैसे यमुना का पानी है, जहां केसाऊ बांध है जब तक इन साधनों को बाकायदा यूटीलाइज नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बनेगी मैं तो यहां तक कहूंगा कि यमुना को पक्का करें ताकि 35 प्रतिशत पानी सेव हो जाए। जैसा कि इरीगेशन डिपार्टमैंट के लोग कहते हैं कि अगर यमुना को पक्का कर दिया जाए तो 35 प्रतिशत पानी की सेविंग हो सकती है और हम उस पानी को यूटीलाइज कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो बरसात का पानी आएगा और समुद्र में चला जाएगा इसलिए इस पानी को सेव करने के लिए आपको रजवाहे बनाने पड़ेंगे। इस में पानी को रोंके तब यह सिस्टम कामयाब हो सकता है वरना थोड़ा दबाव देंगे तब तो पानी आ जाएगा। थोड़ी सफाई करवाएंगे, थोड़ा डंडा चलाएंगे और अगर पानी की चोरी नहीं होगी तब तो पानी आ जाएगा और पानी की मात्रा बढ़ जाएगी। लेकिन इसका परमानैंट हल डैम बनाने से है। इसके साथ साथ ब्यास नदी पर पौंग और पंडोह दो डैम बनाने की बहुत पुरानी प्रक्रिया बहुत लम्बे अर्से से पैण्डिंग है उसको टाइम बाउंड प्रोग्राम के तहत कम्पलीट करें ताकि उससे लोगों को इमीडिएट लाभ हो और लोगों को नजर आए कि यह काम कर दिया गया है। इसके साथ-साथ बिजली के बारे में मैं कहना चाहता हूं जब बिजली हरियाणा में आई, मेरे ख्याल से 1970-71 में सारे हरियाणा के अन्दर इलैक्ट्रिफिकेशन हुआ था लेकिन उसके बाद से खम्भे और तारें आज तक नहीं बदली गई और वे यूं कि यूं चल रहीं हैं। जिसके कारण दुर्घटनाएं होती हैं। तार बहुत नीचे आऐ हुए हैं। एक-एक गांव का जिक्र करना यहां मुनासिब नहीं है लेकिन यह बहुत जनरल बात है। बहुत लम्बा आदमी हो तो उसके हाथ इन तारों तक चले जाएंगें। खम्भे इतने टूटे हुए हैं कि लोगों ने लकड़ी बांध कर उनको स्पोर्ट दी हुई हैं इसलिए इनको बहुत ही जल्दी बदलवाया जाए क्योंकि इससे बहुत दुर्घटनाएं हो जाती हैं, मवेशी मर जाते हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है कि इस मामले में बहुत इमीडिएट स्टैप उठाने की जरूरत है। उपाध्यक्ष महोदय, एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि गांवों की आबादी बहुत बढ़ गई है, मेरी कांस्टीच्यूएंसी में 7-8 गांव ऐसे हैं जहां हाई टैंशन वायर मकानों के ऊपर हैं।

Mr. Deputy Speaker : Malik Sahib, please wind up. Please take your seat.

चौ० धर्मपाल सिंह मलिक : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी कांस्टीच्यूंसी की बात जरूर कहना चाहूंगा। ट्यूबवैल के केबल कनैक्शन के लिए चौटाला साहब ने 20 हजार रुपये फिक्स कर रखे थे और 7 हजार रुपये प्रति खम्भा फिक्स कर रखे थे तथा 2 हजार रुपये सिक्योरिटी के लिए फिक्स कर रखे थे। वह सिक्योरिटी, सिक्योरिटी भी नहीं थी बल्कि नम्बर दो की ब्लैक मनी थी। वह न सिक्योरिटी थी और न उसका कुछ और नाम था। उसको वैसे ही जमा करवा लेते थे इसलिए उसको भी हटवाया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं अपने हल्के की कुछ बातों का जिक्र आपके माध्यम से यहां करना चाहूंगा। जो बहुत जरूरी हैं। मेरे हल्के का ज्यादातर इलाका देहात का है और कैप्टन साहब के सिंचाई विभाग से संबंधित हैं। मेरे हल्के में मोईहुडा माईनर है जिसकी लम्बाई को 450 फिट आगे बढ़ाना है उसकी वायबिलिटि भी है और इस बारे में सर्वे भी कर लिया गया है। वहां आगे रोड़ आ गई है उसके बीच से यह माईनर निकालना है। इसके अलावा एक रिठाल डिस्ट्रीब्यूट्री एक्टैंशन की कैपेसिटी और लम्बाई को बढ़ाना है। रिठाल डिस्ट्रीब्यूट्री आलरेडी है। लेकिन रिठाल डिस्ट्रीब्यूट्री एक्सटैंशन उसी में से निकाली गई है उसकी थोड़ी सी लम्बाई को बढ़ाने से धीलोड़ और आंवली गांवों में पानी जा सकेगा। उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से धीलोड़ माईनर में जो बैरल सिस्टम लगाया हुआ है। उसके बारे में विभागीय अधिकारी यह कहते हैं कि बैरल सिस्टम जब तक रहेगा आगे पानी नहीं जायेगा क्योंकि बैरल सिस्टम में गाद जम जाती है और पानी ठीक ढंग से फलो नहीं करता इस कारण टेल तक पानी नहीं पहुंचता। विभागीय अधिकारी बताते हैं कि टेल तक पानी तभी पहुंचेगा जब ट्रोफ (trough) सिस्टम लगेगा। इसलिए धीलोड़ माईनर पर आर०डी० 219 पर trough सिस्टम लगवाया जाये और उस माईनर की सफाई भी करवाई जाये तथा जो किनारें टूटे हुए हैं उनकी रिमोडलिंग भी की जाये। मेरे हल्के के लाठ गांव के रकबे के लिए भालोठ सब ब्रांच की आर०डी० 53 से पानी जाता है। उसमें से पहले गांव वाले पानी की चोरी करते हैं जिसके कारण उस गांव में पिछले कई सालों से पानी नहीं गया है। मेरे गांव से डेढ़ कि०मी० की दूरी पर लाठ गांव है उस गांव के लोग कहते हैं कि पिछले 50 सालों से एक बूंद पानी भी उनके यहां नहीं आया है। इस लिए इन गांवों के लिए भी पानी का उचित प्रबन्ध किया जाये। इसके अतिरिक्त जो सिकन्दरपुर माजरा माईनर कप शेप में बनाया हुआ है उसको कप शेप के स्थान पर वर्टीकल वाल शेप में बनाया जाये। जब तक इसका सैक्शन वर्टीकल वाल में नहीं बनेगा और पानी की चोरी नहीं रूकेगी तब तक आगे पानी नहीं जायेगा। इसलिए इस तरफ भी कैप्टन साहब ध्यान दें। इसके अतिरिक्त कटवाल माईनर की रिमोडलिंग करके उसकी कैपेसिटी भी बढ़ाने की आवश्यकता है। इसकी कैपेसिटी बढ़ाने से भैंसवाल कलां जो कि बहुत बड़ा गांव है, उसको फायदा होगा। इसके अलावा भैंसवाल कलां गांव में फरमानाकलां माईनर है, भाई सुखबीर सिंह जी बैठे हुए हैं उनको भी पता है कि उसकी भी रिमोडलिंग करने की आवश्यकता है। वह माईनर इनके गांव तक भी जाता है। इसकी रिमोडलिंग होने से भैंसवाल कलां और फरमाना कलां दोनों गांवों की पानी की भरपाई हो जायेगी। इसके अतिरिक्त सरगथल माईनर भी दो बुर्जी आगे बढ़ाया जाये और गुहणा माईनर की कैपेसिटी 32 क्यूसिक से 38 क्यूसिक की जाये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि यह सब मैं पूरी स्टडी करके बता रहा हूं ताकि कंक्रीट ढंग से बात हो। वैसे कहेंगे तो बात नहीं बनती। इसके अतिरिक्त खूबडू से इसराना डिस्ट्रीब्यूट्री है जिसमें पिछली सरकार के समय में 20 प्रतिशत अतिरिक्त पानी छोड़ने का प्लान बनाया गया था और इस डिस्ट्रीब्यूट्री पर एक करोड़ रुपये खर्च किये गये थे लेकिन आज तक पानी नहीं पहुंचा और वे लोग एक करोड़ रुपये भी खा गये। (विघ्न) इसी तरह से एक रामगढ़ माईनर है। रामगढ़ माईनर मन्जूर

की गई है यह 15 गांवों में पानी देगी। लेकिन हम बहुत दिनों से सुन रहे हैं कि यह माईनर मन्जूर हुई पड़ी है। यह माईनर केवल मन्जूर ही मन्जूर है मौके पर वह बनी नहीं है इसलिए इसको इम्पलीमैंट करने की बात है। इस तरह से भी बहुत सी इम्पोर्टेन्ट चीजें हैं। कप्तान साहब, मेरी कांस्टीच्यूएंसी के ऐरिया में हमें जो पानी मिलता है वह दो जगह से मिलता है एक तो भालोठ सब-ब्रान्च है और दूसरे जे०एल०एन० फीडर है। जे०एल०एन० फीडर का पानी तो आता है गोहाना से लेकिन उसका एस०डी०ओ० पानीपत में बैठता है। (विघ्न) बहन जी, आप वाला भी वहां पर इसराना में गड़बड़ करता है यह सही बात है। लेकिन असली बात यह है कि वहां पर पानीपत के अन्दर दो एस०डी०ओज० हैं। गोहाना के अन्दर जे०एल०एन० फीडर का कोई काम होता है तो लोग गोहाना से पानीपत जाते हैं जबकि उनका ऐरिया गोहाना का है। यह बात समझ में नहीं आई कि उनको उल्टा पानीपत किस लिए भेजते हैं जबकि पानीपत के लिए अलग एस०डी०ओ० है। इसलिए मेरी आपके माध्यम से इरिगेशन मिनिस्टर महोदय से प्रार्थना है कि जे०एल०एन० फीडर का जो एस०डी०ओ० पानीपत में बैठता है उसका ऑफिस गोहाना में शिफ्ट किया जाए ताकि वह वहां पर सारे सिस्टम को ठीक रख सके (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, मैं सड़कों के बारे में एक बात कहना चाहता हूं। सड़कों का बहुत बुरा हाल है। हम यह सुनते थे कि चौटाला साहब पता नहीं बैंक से पैसा लेकर आएंगे या कहीं और से पैसा लाएंगे और सड़कों का काम करेंगे। उनकी सरकार तो चली गई लेकिन सड़कों का कोई काम नहीं हुआ है। सड़कों की हालत इतनी खराब है कि सड़कों में खड्डे नहीं हैं बल्कि खड्डों में सड़क है। हमारे यहां की सड़कों की हालत बहुत बुरी है। पता नहीं उस ऐरिया को खासतौर से छांट रखा था। (विघ्न) जैसे कोई गांव नेशनल हाईवे पर पड़ता हो तो दूसरी बात है लेकिन हमारे यहां पर जनरली सड़कों की वर्स्ट कण्डीशन है। 4-5 रोड्ज तो ऐसी हैं जो 1994 में मन्जूर हुई थीं लेकिन अभी तक बनी नहीं। 1994 में मैंसवाल से तिहाड़ सड़क मन्जूर हुई थी लेकिन उसके बाद हमारी सरकार चली गई थी। परन्तु यह सड़क मैंसवाल सीमा तक तो बन गई लेकिन आगे तिहाड़ तक काम पूरा नहीं हुआ और वह सड़क यूं की यूं ही पड़ी हुई है। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : मलिक साहब, अब आप अपनी सीट पर बैठें।

चौ० धर्मपाल सिंह मलिक : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दो-तीन बातें और कहनी हैं।उसके बाद मैं आपको दोबारा सारे सैशन में तंग नहीं करूंगा और मेरे सारे मामलों की छुट्टी हो जाएगी। इसमें एक बात तो यह है कि वह सड़क बीच में बननी छोड़ रखी है। वह सड़क गांव की सीमा तक तो बनी हुई है और सड़क आगे भी मन्जूर है लेकिन वह 11-12 साल से बनी ही नहीं यानि की यूं कि यूं ही पड़ी हुई है। इसलिए इसको बनवाया जाए। एक सड़क लाठ गांव से गुहणा वाया मैंसवाल बननी है वह भी नहीं बनी, वहां पर भी शुरू से ही इस किस्म की बात है। मेरा नम्र निवेदन है कि वह सड़क शीघ्र बनाई जाए। न्यात से गामड़ी, मोई हुड्डा से काहनी, बिधल से जौली और कैलाना खाल से खानपुर तक सड़क बननी है। खानपुर की सड़क की तरफ सरकार का ध्यान इसलिए दिलाना चाहता हूं क्योंकि इसका सब को पता है कि वहां पर उत्तरी भारत की लड़कियों की सब से बड़ी संस्था है और वहां पर बाहर से चारों तरफ से लड़कियां आती हैं। वहां जितने साधन होंगे लड़कियों का उतना ही भला होगा। यह गांव बीच में पड़ता है और लोग कहते हैं कि वे वहां पर जा नहीं सकते, लड़कियों को वहां पर कैसे भेजें। वहां पर कोई बस नहीं जाती है। वहां के लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वे लड़कियों को होस्टल में दाखिल करें। इसलिए आपसे मेरी यह

[चौ० धर्मपाल सिंह मलिक]

प्रार्थना है कि इन सब सड़कों को बनाया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं शिक्षा का जिक्र करना चाहूंगा । शिक्षा मन्त्री माननीय मुलाना साहब आ गए हैं मैं इनसे कुछ स्कूलों को अपग्रेड करने की बात कहना चाहूंगा। कटवाल, मोई हुड्डा और खेड़ी धनकन में 10+2 और दोघवा में 8वीं से 10वीं तक स्कूल बनाने की बात है। मुलाना साहब, मेरा आपसे कहना है कि वहां स्कूलों में टीचर्ज नहीं हैं, वहां पर बहुत बुरी हालत है इसलिए आप इस बारे में भी गौर करें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो वहां पर कह कर आया था कि जब मास्टर्ज आएंगे तब ही वे स्कूल में आएंगे। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, हैल्थ मिनिस्टर जी भी यहां पर बैठी हैं मैं उनसे भी एक दो बातें कहना चाहूंगा। **(इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए।)**

Mr. Speaker : Dharampal Ji, You have already taken 50 minutes. Please wind-up.

चौ० धर्मपाल सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां रिवाड़ा गांव में एक चैरिटेबल हॉस्टिपल बना रखा है और उस पर 20-30 लाख रुपए गवर्नमैंट ने भी खर्च किये हुए हैं। उसको अगर गवर्नमैंट टेकओवर कर ले तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि वहां पर एक ही डाक्टर है और वह भी कभी आता है और कभी नहीं आता है। अगर गवर्नमैंट उसको टेकओवर कर ले तो गवर्नमैंट को वहां पर बिल्डिंग भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा मोई गांव में भी एक प्राईमरी हैल्थ सैन्टर बनवाने का कष्ट करें। सरगथल, रिठाल और विधल तीन गांवों में भी वैटनरी डिस्पैंसरी खोलने का कष्ट करें। स्पीकर सर, मैं आखिर में एक बात कहना चाहता हूं कि चौधरी छोटू राम जी का जो सामान लाहौर में था अगर मैं अब इसकी बात करूंगा तो फिर चौटाला साहब की बात आ जाएगी। मैं उनका जिक्र नहीं करना चाहता हूं। क्योंकि वे अपने शासनकाल में शासन चलाने के लिए और लोगों को एक्सप्लायट करने के लिए लाहौर गए और पता नहीं वहां कहीं से कुछ सामान खरीद कर ले आए लेकिन वह सर छोटू राम जी का सामान नहीं था।

Mr. Speaker : This is not the subject of the budget. Please sit down.

चौ० धर्मपाल सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि चौटाला साहब सस्ती लोकप्रियता लेने के लिए इतने नीचे स्तर के प्रयास कर सकते हैं। मेरी आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना है कि हमें अपने तौर पर लाहौर जाना चाहिए और सर छोटू राम जी का सामान लाने का प्रयास करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

कुमारी शारदा राठौर (बल्लभगढ़) : स्पीकर सर, मैं 9 जून को पेश होने वाले बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ी हुई हूं। इस बजट के लिए मैं वित्तमंत्री जी को बधाई देना चाहती हूं जिन्होंने बहुत ही शानदार और कर मुक्त और रोजगारोन्मुखी बजट पेश किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं उनको इस बात के लिए भी बधाई देना चाहती हूं कि कांग्रेस पार्टी ने चुनावों से पहले अपने घोषणा पत्र में जो-जो बातें कहीं थी उनके अनुरूप ही उन्होंने इस बजट को पेश किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं महिला प्रतिनिधि होने के नाते हरियाणा की महिलाओं की तरफ से भी मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहती हूं कि उन्होंने अपने इस थोड़े से शासन काल में हरियाणा की महिलाओं के विकास के लिए कई बिन्दुओं को इस बजट में लिया है और महिलाओं के लिए कई योजनाएं शुरू करी हैं। अध्यक्ष महोदय, पिछले काफी समय से पिछली सरकारों ने हरियाणा में

लिंग अनुपात के अन्दर जो अन्तर आ रहा है, उसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए थे। लेकिन हमारी सरकार ने आते ही इस तरफ ठोस कदम उठाए हैं। आज हरियाणा में 1000 लड़कों के मुकाबले में लगभग 861 लड़कियां हैं। जिससे स्थिति बड़ी भयावह होती जा रही है। इससे एक सामाजिक विषमता भी पैदा होती है। इसके कारण ही बलात्कार जैसी घटनाएं, महिलाओं की खरीद फरोख्त या सन्तानोत्पत्ति के लिए महिलाओं को किराए पर लाने और शादियों के लिए दूसरे प्रदेशों से लड़कियां लाने जैसी समस्याएं पैदा होने लग रही हैं। लेकिन हमारी सरकार ने पी०एन०डी०टी० ऐक्ट जैसी योजना को एक अच्छे ढंग से दोबारा बनाकर उसमें धार्मिक, सामाजिक संगठनों को भी शामिल करके इस भयावह होती जा रही बुराई से मुक्ति पाने की कोशिश की है। सरकार ने महिलाओं को आगे लाने के लिए और लड़कियों की पैदाइश को प्रोत्साहन देने के लिए एक स्कीम और बनायी है जो लाडली स्कीम के नाम से जानी जाएगी। इस स्कीम में दूसरी लड़की के पैदा होने पर बेटी के मां बाप को पांच हजार रुपये प्रति वर्ष मिलेंगे। अध्यक्ष महोदय, इससे लड़की की पैदाइश को बढ़ावा मिलेगा। इसी तरह से इस स्कीम के तहत जिनके परिवारों में एक मात्र संतान बेटी ही है ऐसे परिवारों को पेंशन देने की भी सरकार की योजना है जोकि बहुत ही सराहनीय है। इसी तरह से अनुसूचित जाति और गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले इन परिवारों की कन्याओं के विवाह के लिए जो पहले 5100 रुपये दिए जाते थे, उसके स्थान पर अब हमारी सरकार ने 15 हजार रुपये देने का प्रावधान किया है ताकि लड़कियों को उनका उचित अधिकार मिल सके। अध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने महिलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए महिला सहकारी विकास बैंक की भी एक योजना बनायी है। इनमें महिलाएं ही कर्मचारी रखी जाएंगी जिससे महिलाओं के लिए रोजगार के नये अवसर पैदा होंगे। इसी तरह से जींद में महिला कालेज की बात आयी। इंदौरा जी ने कहा था कि इंदिरा गांधी के नाम पर केवल एक ही कालेज की स्थापना की गयी है। इंदौरा जी, आपको इस बारे में हमें बताने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे नेता के लिए हमारे दिलों में कितना सम्मान है। हम आपकी तरह नहीं हैं कि चौधरी देवीलाल के नाम पर सिरसा में एक यूनिवर्सिटी खोल दी जिसके कारण हजारों छात्र सड़कों पर आ गये। आपने तो चौधरी देवीलाल के नाम पर छात्रों की भावनाओं का भी ख्याल नहीं रखा। आपने उस यूनिवर्सिटी का नाम ताऊ देवीलाल के नाम से इसलिए रखा ताकि आप बार बार वोट बटोरते रहें लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम अपने नेता के नाम से वोट बटोरने जैसा काम नहीं करते । हम लोग उनके नाम पर कुछ करके दिखाने का काम करते हैं। इंदौरा जी, आपने हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचायी है और आप हमारे नेताओं का सम्मान नहीं करते। हमें आपसे इसके लिए कोई सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है इसलिए आपको इस बारे में माफी मांगनी चाहिए। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने 13 हजार टीचर्ज की जो भर्ती की घोषणा की है उसमें भी 33 परसैंट महिलाओं को आरक्षण देने की घोषणा बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सराहनीय है इसके लिए हरियाणा की सम्पूर्ण महिलाओं की तरफ से मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूं। पिछली सरकार ने महिलाओं के लिए ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अध्यक्ष महोदय, एडवर्स सैक्स रेशो से संबंधित जो समस्याएं हैं उनको उठाने के लिए और महिलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए एवं लड़कियों की पैदाइश को प्रोत्साहन देने के लिए मैं मुख्यमंत्री जी का खासतौर पर धन्यवाद करना चाहूंगी। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से जो लाटरी चल रही थी उसको मुख्यमंत्री जी ने आते ही बंद कर दिया, इसके लिए भी हरियाणा की महिलाएं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करती हैं। क्योंकि लाटरी से कहीं न कहीं महिलाएं ही खामियाजा भुगत

[कुमारी शारदा राठौर]

रही थीं। अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा के युवाओं की तरफ से वित्त मंत्री जी का और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगी क्योंकि यह जो बजट है यह रोजगारोन्मुखी बजट है। इंदौरा जी, आपकी सरकार ने बेरोजगारी को दूर करने के नाम पर बेरोजगारी भत्ता देकर बेरोजगारों को लोलीपोप के रूप में रोजगार देने की बात कही थी । आपने उनको रोजगार के नाम पर लोलीपोप पकड़ा दिया था। इन्होंने बताया था कि बजट में हमारी सरकार ने बेरोजगारी भत्ते के रूप में 45 करोड़ रुपये रखे थे लेकिन मात्र 3-4 करोड़ रुपये ही बेरोजगारी भत्ते के रूप में दिये गये। हमारे हरियाणा के युवाओं के साथ इससे बड़ा भद्दा मजाक और कोई नहीं हो सकता। मैं वित्त मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहती हूं कि हमारी सरकार ने इस भत्ते की पात्रता के मानदण्डों को तर्कसंगत बनाया है और 105 करोड़ रुपये की राशि बजट में बेरोजगारी भत्ते के रूप में रखी गई है जो निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। मैं इसके लिए हरियाणा के युवाओं की तरफ से उनका धन्यवाद करना चाहती हूं। जो नयी इंडस्ट्री खुलने जा रही है उनमें भी हरियाणा के कम से कम 10 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। इससे भी काफी हद तक हम बेरोजगारी दूर करने में कामयाब हो सकेंगे। पंजाब के गांवों के लगभग हर घर से कोई न कोई नौजवान विदेशों में रोजगार कर रहा है जबकि हरियाणा से विदेशों में रोजगार पाने वालों की संख्या बहुत ही कम है। हमारी सरकार ने विदेशों में रोजगार दिलाने के लिए विदेशी रोजगार ब्यूरो बनाने की योजना बनाई है। एक उच्चाधिकार प्राप्त कमेटी इस ओवरसीज इम्प्लायमैंट के लिए बनाई है इससे हरियाणा के युवकों को विदेशों में रोजगार के अवसर मिलेंगे। आजकल जो भूमंडलीकरण का दौर है इसमें हमारे नौजवान भी बाहर जाकर सीख पाएंगे और इससे प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी। इसके लिए नौजवान रोजगार सेवा योजनाएं औद्योगिक नगरों जैसे फरीदाबाद, गुड़गांव, यमुनानगर, सोनीपत में स्थापित करने की योजना बनाई गई है इससे भी रोजगार को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। हमारी कांग्रेस पार्टी स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करने वाली पार्टी है। मुख्यमंत्री जी जो स्वयं एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार से हैं इन्होंने सत्ता संभालते ही स्वतंत्रता सेनानियों को जो सम्मान पेंशन मिलती थी, उसको 1400 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये कर दिया है। मैं समझती हूं कि इससे बड़ी श्रद्धांजली देश के उन सपूतों को नहीं दी जा सकती जिनकी वजह से आज हम आजाद हिन्दुस्तान में जी रहे हैं। पिछली सरकार ने कारगिल शहीदों के नाम पर जो छोटी और ओछी राजनीति की, वह सबको मालूम है। उन्होंने विभिन्न योजनाएं देने की घोषणा की जो सिर्फ वोट बटोरने तक सीमित रहीं । वे योजनाएं न जाने कहां गुम हो गई ? चौटाला जी ने अपने शब्दों के जाल में न जाने कहां उनको छुपा लिया? शहीदों के परिवार उन योजनाओं का लाभ पाने के लिए भटकते रहे। हमारी सरकार ने किसानों को सहायता देने के लिए और कृषि क्षेत्र में विकास के लिए ट्रैक्टर पर रजिस्ट्रेशन फीस भी खत्म की है। सरकार ने आपदा राहत कोष की राशि 124.37 करोड़ रुपये बढ़ाई है इससे किसानों को बहुत फायदा हुआ। ओलावृष्टि से भी फसलों को बहुत नुकसान हुआ। गेहूं की फसल के लिए 50 प्रतिशत और अन्य फसलों के लिए 25 प्रतिशत की मुआवजा राशि में वृद्धि देकर हमारी सरकार ने किसानों को आर्थिक रक्षा प्रदान करने की कोशिश की है, इसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहती हूं। पिछली सरकार ने किसानों पर तरह तरह से मुकदमें चला दिए और दमनकारी नीति अपनाई। हमें खुशी है कि अब कोई ऐसा रास्ता अख्तियार नहीं किया जाएगा जिससे किसानों को नुकसान हो। बिजली के बिलों के भुगतान के हल के लिए सरकार ने कमेटी गठित कर दी है और इसके लिए जल्दी ही आसान तरीके निकाले

जाएंगे।

Mr. Speaker : Madam Rathore, please wind up.

कुमारी शारदा राठौर : स्पीकर सर, किसानों के बकाया बिजली के बिल अब आसानी से जमा हो पायेंगे और किसानों को राहत मिलेगी। सरकार ने इसके लिए 1708.21 करोड़ रुपये की सहायता देने की बात कही है। जिसमें से 1256 करोड़ रुपये की सब्सिडी रखी गई है। अभी बात हो रही थी, इन्दौरा साहब कह रहे थे कि हमारी सरकार के वक्त में भी 15 लाख रुपये गुड़गांव में किसानों को मुआवजा दिया है। लेकिन ऐसे भी कई केसिज गुड़गांव में आये हैं कि किसानों की जमीन को औने-पौने दामों में खरीदवाकर पिछली सरकार की मिलीभगत से और सांठगांठ से वह जमीन बिल्डिरों को रिलीज करवाई गई। बाद में बिल्डिरों ने उस जमीन को सोने के भाव बेचा जबकि किसान अपने मुआवजे की राशि बढ़वाने के लिए कोर्ट कचहरी के धक्के खाते रहे और दर-दर भटकते रहे। हमारी सरकार ने उस जमीन का एक फ्लैट रेट निर्धारित करके किसानों को दर-दर भटकने से और बिल्डिरों के चंगुल से बचाया है। अब उनका शोषण नहीं हो पायेगा। हमारी सरकार ने सिंचाई के पानी के समान बंटवारे की बात कही है। मुझे लगता है कि हम निकट भविष्य में पानी का समान बंटवारा कर पायेंगे। जिससे सभी जिलों के किसानों को फायदा पहुंचेगा। वर्तमान समय में जो जल संसाधन हैं उनको विकसित किया जा रहा है और उनकी भी वृद्धि की जा रही है इनमें सुधार की योजना है, इससे भी किसानों को काफी फायदा मिलेगा। मैं कहना चाहूंगी कि किसानों के साथ-साथ हमारी सरकार कर्मचारियों के लिए भी बहुत उदारतापूर्ण की नीति अपनाए हुए है। हमारी सरकार कर्मचारियों की मांगों के लिए और कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने के लिए सहानुभूतिपूर्वक विचार करती है। कर्मचारियों की बेटी के विवाह पर सरकार द्वारा जो पहले 25 हजार रुपये लोन के रूप में दिये जाते थे, आज उस राशि को बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दिया गया है। इसके लिए भी सरकार बधाई की पात्र है। जो कर्मचारी रिट्रैंच किये गये थे, जिनकी छंटनी हुई थी, उन कर्मचारियों के प्रति भी सरकार उदारतापूर्ण रवैया अपनाये हुए है। आज सुबह भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पिछली सरकार द्वारा गलत तरीके से की गई भर्ती के कारण ही कुछ कर्मचारियों को इस सरकार द्वारा निकाला गया है लेकिन नई भर्ती में सरकार उनको कुछ वेटेज जरूर देगी और सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी। इस तरह से कर्मचारियों के लिए सरकार उदारतापूर्ण नीति अपनाये हुए है। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि मैं फरीदाबाद जिले से संबंध रखती हूं इसलिए फरीदाबाद के बारे में कुछ कहना चाहती हूं। फरीदाबाद जिला एक समय में एशिया में नम्बर एक औद्योगिक नगर हुआ करता था। जब कांग्रेस का राज था तब हम नम्बर एक पर पहुंच गये थे। हमारा जिला हिन्दुस्तान की एक प्रमुख औद्योगिक नगरी थी लेकिन जब सरकार बदली तो सब कुछ बदल गया। पिछली सरकार ने तो हमारे जिले फरीदाबाद को फकीराबाद में परिवर्तित कर दिया था वहां लगभग एक हजार उद्योग धन्धे बन्द हो गये या उनका पलायन हुआ। फैक्ट्रियों पर मोटे-मोटे ताले लग गए। यह सब गलत नीतियों के कारण और पूर्व मुख्यमंत्री एवं उनके दोनों बेटों की वहज से हुआ क्योंकि उनकी नीति यह थी कि फरीदाबाद तो सोमनाथ का मन्दिर है इसे जितनी बार लूटा जाये उतना कम है। वहां व्यापारी और उद्योगपति अगर एक रुपया कमाते थे तो मुख्यमंत्री और उनके दोनों बेटे 75 पैसे ले जाते थे और बाकी 25 पैसे अधिकारियों और चेले चपाटे ले जाते थे ऐसे माहौल में उद्योगपति कहां रह पाते इसलिए उनका वहां से पलायन हो गया। इसी वजह से हरियाणा की आर्थिक स्थिति को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा।

Mr. Speaker : Madam Rathore, please wind up.

कुमारी शारदा राठौर : स्पीकर सर, हमारी सरकार ने नई उद्योग नीति इसी महीने घोषित की है। उसमें बहुत सारे रोजगार के अवसर तो हैं ही साथ ही पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए भी योजनाएं हैं। इसमें उद्योगों को लगाने के लिए बढ़िया इन्फ्रास्ट्रक्चर देने की योजनाएं हैं जो बाहरी निवेशक आयेंगे तो उनके लिए अच्छा औद्योगिक वातावरण पैदा करने की भी हमारी सरकार की योजनाएं हैं। जिससे पूरे हरियाणा के निवासियों को फायदा मिलेगा और हरियाणा जो उद्योग के क्षेत्र में पिछड़ गया था, फिर से एक बार नं० 1 पर आ सकेगा। इसके लिए सरकार ने कलस्टर डिवैल्पमैंट प्रोजैक्ट बनाया है। जिस तरह पानीपत में वस्त्र उद्योग को विकसित किया जाएगा, उसी तरह गुड़गांव में आटोमोबाइल इंडस्ट्रीज को विकसित किया जाएगा और फरीदाबाद में छोटे इंजीनियरिंग वर्क्स को बढ़ावा दिया जाएगा उससे मुझे लगता है कि फरीदाबाद फकीराबाद से पुन: फरीदाबाद बन जाएगा और जिन मजदूरों की फैक्ट्रियां बंद होने से रोजी-रोटी छिन गई थी, एक बार फिर उन मजदूरों के चहेरे पर खुशी की हम रोशनी देख पाएंगे। पिछली सरकार में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा गिरावट आ गई थी। सरकारी स्कूलों से लोगों का विश्वास उठ गया था। इसका नतीजा यह हुआ कि छोटे-छोटे प्राइवेट स्कूल खुल गए थे और लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में ही पढ़ाने लगे। 2 साल पहले चौटाला जी ने घोषणा की थी कि प्राइमरी लैवल से हम अंग्रेजी शिक्षा पढ़ाना शुरू करेंगे। वह योजना केवल योजना ही रह गई क्योंकि उस योजना का योजनाबद्ध तरीके से क्रियान्वयन नहीं हुआ। आनन-फानन में 2800 टीचर्स की भर्ती की गई लेकिन इसका बजट में कोई प्रावधान नहीं रखा गया। 2800 टीचर्स भर्ती तो हो गए लेकिन उनकी तनख्वाहों की हालत यह रही के वे तनख्वाहों के लिए भटकते रहे लेकिन उन्हें तनख्वाह नहीं मिल पाई। अब उनको तनख्वाहें देने का प्रावधान हमारी सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री महोदय ने प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 6 से 11 वर्ष की आयु के बच्चों को जो अनिवार्य शिक्षा देने की घोषणा की है वह शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बहुत अच्छा प्रयास है। मैं समझती हूं कि हरियाणा जैसे प्रदेश में शिक्षा के प्रचार और प्रसार की बहुत आवश्यकता है। हम अभी शिक्षा के क्षेत्र में अपने आप को पिछड़ा हुआ समझते हैं, आज के दौर में जब दूसरे प्रदेश के बच्चों के साथ हमें प्रतिस्पर्धा करनी होती है और जब हम वर्ल्ड क्लास एजूकेशन की बात करते हैं तो हमें शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना ही होगा। शिक्षा पर ज्यादा बजट खर्च करने की और ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। इसके लिए विल मंत्री ने शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए 'राजीव गांधी एजूकेशन सिटी' नाम की योजना बनाई है। विभिन्न विषयों में शिक्षा और श्रेष्ठ माहौल यह सिटी दे पाएगा। इसमें हरियाणा के बच्चों के लिए जो 25 प्रतिशत आरक्षण रखा गया है। उससे हमारे बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अभी 13 हजार टीचर्स की भर्ती की घोषणा की गई है। पिछली सरकार में कई स्कूलों में ताले लग गए थे। उस समय जो स्कूल बन्द हो गए थे, इन टीचर्स की भर्ती से वे ताले खुलने का काम जल्दी हो सकेगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए जो JBT टीचर्स की क्वालिफिकेशन को बी०ए० किया गया है यह एक प्रशंसनीय कदम है इसके अलावा 50 हजार छात्रों को राजीव गांधी छात्रवृत्ति देने की योजना से सरकारी स्कूलों के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ेगा, आकर्षण बढ़ेगा और प्रतिस्पर्धा की भावना हमारे छात्रों में पैदा होगी। हर जिले में सरकारी माडल स्कूल खोलने की योजना का काम भी एक सराहनीय कदम है। मैं कहना चाहती हूं कि सरकार ने स्थानीय निकायों को जो वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है उससे इनको अपना काम चलाने में सहायता मिलेगी। हमारा जो फरीदाबाद

का म्यूनिसिपल कारपोरेशन है तो अब उसको भी सहायता मिलेगी। इसके लिए हम सरकार का धन्यवाद करते हैं। शहरी नवीनीकरण मिशन के तहत कुछ जिलों को चुना गया है इस मिशन के तहत हमारे जिले को पहली योजना में ही चुना गया है, इसके लिए मैं फरीदाबाद के निवासियों की तरफ से सरकार का धन्यवाद करती हूं क्योंकि 47 करोड़ की अतिरिक्त सहायता हमारे शहर के नवीनीकरण के लिए मिलेगी। पंचायतों को अधिक प्रशासनीय और वित्तीय अधिकार देने की बात बजट में कही गई है, इसके लिए भी मैं सरकार का धन्यवाद करती हूं। राजीव गांधी ने जो पंचायती राज का सपना देखा था, सही मायनों में कांग्रेस की सरकार पंचायती राज संस्थाओं को उनके वित्तीय और प्रशासकीय अधिकार देकर राजीव गांधी के उस सपने को साकार कर रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का अधिक समय न लेते हुए कुछ बातें और कहना चाहूंगी कि वित्त मंत्री जी ने बजट बनाते हुए हर वर्ग के हितों को ध्यान में रखा है। इससे बेहतरीन बजट और कोई नहीं हो सकता। अध्यक्ष महोदय, मेरे विपक्ष के साथी कह रहे थे कि इन सब योजनाओं को लागू करने के लिए साधन कहां से जुटाए जायेंगे, पैसे का इंतजाम कहां से किया जायेगा और आने वाले समय में हमें लोन मिलना बंद हो जायेगा जिससे हमारी स्टेट कर्जदार हो जायेगी। वे इस तरह की फिजूल की बातें कर रहे थे। मैं इनको बताना चाहूंगी कि आर्थिक मजबूती के लिए फिस्कल रिस्पोंसिबिल्टि बिल और फिस्कल मैनेजमैंट बिल हमारी सरकार ला रही है जिससे हरियाणा प्रदेश को आर्थिक मजबूती मिलेगी। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री जी ने एक रिसोर्सिज मोबीलाईजेशन कमेटी का गठन किया है जिसके मुख्यमंत्री जी स्वयं अध्यक्ष हैं। इससे भी हमारे संसाधनों में इजाफा होगा। अध्यक्ष महोदय, इस बजट में जो भी योजनाएं दी गई हैं। हमें पूरा विश्वास है कि इस बजट के द्वारा हम उनको लागू करने में समर्थ होंगे। वित्तमंत्री जी का मैं दोबारा से धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा बजट प्रदेश की जनता को दिया है।

श्री अर्जन सिंह (छछरौली) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आपने मुझे आखिर में बोलने के लिए समय दिया है फिर भी जैसा कहते हैं कि देर आये दुरुस्त आये। अध्यक्ष महोदय, जहां तक बजट की बात है हम भी बजट की प्रशंसा करते हैं कि वित्त मंत्री जी ने बहुत अच्छा बजट प्रदेश के लोगों को दिया है लेकिन बड़े दुख की बात है कि इसमें यमुनानगर जिले का कहीं कोई जिक्र नहीं है। मेरा वित्तमंत्री जी से अनुरोध है कि हमारे यमुनानगर जिले की तरफ भी ध्यान दें ताकि यमुनानगर के लोग यह महसूस ना करें कि उन्हें शेष हरियाणा से अलग थलग रखा गया है । अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के साथी बजट की तारीफ कर रहे हैं। मैं तो यह कहना चाहूंगा कि सरकार ऐसे काम करे कि हम भी तारीफ करें। यदि सरकार अच्छे काम करेगी तो अच्छे काम का मैसेज जनता तक अपने आप जायेगा। जनता भी आपकी तारीफ करेगी और हम भी तारीफ करेंगे। जो आज सरकार में हैं वे पांच साल तक अपोजीशन में रहे और जो अपोजीशन में बैठे हैं वे सरकार में थे। पिछले सालों में यहां क्या हुआ उसको अब दोहराने की जरूरत नहीं है। सरकार को अब ऐसे काम करने चाहिएं जो दूसरों को अच्छे लगें। डाक्टर इंदौरा साहब कुछ समय पहले सत्ता में थे और आज ये सरकार से मांग कर रहे हैं। क्या ये 6 साल तक सत्ता में नहीं रहे ? ये जो बात आज कह रहे हैं वे काम पिछले पांच छः साल में कर लेने चाहिए थे। अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त पिछले सैशन में एक बात आई थी कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वालों को पीले कार्ड ईशू करने के लिए दोबारा से सर्वे किया जायेगा। उस समय यह बात भी आई थी कि बुढ़ापा पैंशन के लिए भी दोबारा सर्वे करवाया जायेगा। मैं मुख्यमंत्री जी से जानकारी चाहूंगा कि कब तक यह कार्य सरकार कर रही है ?

Vidhan Sabha Secretariat LIBRARY

[श्री अर्जन सिंह]

इसके अलावा पिछले सैशन में मुख्यमंत्री जी ने एक घोषणा और की थी कि सभी विधायकों को पी०ए० रखने के लिए भत्ता और एक-एक कम्प्यूटर दिया जायेगा। हमें बड़ी खुशी हुई थी कि हमें भी कम्प्यूटर सीखने का अवसर मिलेगा और हम सदन में पूरी जानकारी के साथ आयेंगे।

परिवहन मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को जानकारी देना चाहूंगा कि हर विधायक को एक व्यक्तिगत सचिव देने के लिए बिल का मसौदा तैयार होकर इसी सत्र में पास हो जायेगा।

श्री अर्जन सिंह : अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि****

Mr. Speaker: Now, the House is adjourned till 9.30 a.m. tomorrow, the 14th June, 2005 and Shri Arjan Singh will continue his speech tomorrow.

18.30 hrs (The Sabha then *adjourned till 9.30 a.m. on Tuesday, the 14th June, 2005).